REDRESS

Ending torture, seeking justice for survivors

यातना का सामान्यीकरण: भारत में राज्य प्रायोजित हिंसा

जून 2025

विषयसूची

संक्षिप्त रूप 4
आभार और कार्यप्रणाली 5
कार्यकारी सारांश और सिफ़ारिशें 6
परिचय 10
यातना के स्वरूप 13
- पुलिस हिरासत में यातना 14
- न्यायिक हिरासत में यातना 18
- हिरासत में यौन और लिंग आधारित हिंसा 21
- न्यायेतर हत्याएं: पुलिस मुठभेड़ें 23

प्रभावित समूह और यातना के संदर्भ 26
- असहमति जताने वालों पर अत्याचार 27
  - मानवाधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाना 28
  - विरोध प्रदर्शनों में अत्याचार 32
- भेदभावपूर्ण उत्पीड़न के साधन के रूप में यातना 35
  - अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार 36
  - धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार 37
- विशिष्ट क्षेत्रों में यातना 40
  - छत्तीसगढ़: आदिवासियों के खिलाफ हिंसा 40
  - भारत-बांग्लादेश सीमा (BSF हिंसा) 42
  - जम्मू और कश्मीर (AFSPA -सक्षम हिंसा) 44
  - मणिपुर में राज्य हिंसा 45

यातना को वैध ठहराना: राष्ट्रीय विधिक ढांचा 47
- UNCAT के अनुमोदन में विफलता तथा यातना का अपराधीकरण न करना 48
- कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता 50
- सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के कानून 52
- आतंकवाद विरोधी कानून 53

यातना के लिए दण्डहीनता 56
- प्रभावी जांच का अभाव 56
  - प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित विफलताएं 57
  - निष्पक्षता, तत्परता और प्रभावशीलता की कमी 58
  - कमजोर बाहरी शिकायत निकाय 60
- शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध 61
- जवाबदेही में अन्य बाधाएं 63

संक्षेपाक्षरों की सूची

AFSPA	आर्म्ड फोर्सेज़ स्पेशल पावर्स एक्ट
BNSS	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया)
BNS	भारतीय न्याय संहिता (दंड संहिता का स्थान लिया)
BSA	भारतीय साक्ष्य अधिनियम (साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया)
BJP	भारतीय जनता पार्टी
BSF	बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
CHRI	कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
CSO	सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन
HRCttee	यूएन ह्यूमन राइट्स कमिटी
ICCPR	यूएन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स
MASUM	बंग्लार मानवाधिकार सुरक्षा मंच
NCAT	नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर
NCRB	नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
NGO	नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन
NHRC	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
SHRC	राज्य मानवाधिकार आयोग
UAPA	अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट
UNCAT	यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन ऑर डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑर पनिशमेंट
UPR	यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू
WGAD	यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन

आभार एवं कार्यप्रणाली

यह रिपोर्ट REDRESS ने भारत में यातना-संबंधी मामलों पर कार्यरत विशेषज्ञ कानूनी प्रैक्टिशनरों और नागरिक समाज सदस्यों के परामर्श से तैयार की है। हम उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रति आभारी हैं जिनकी मूल्यवान अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता ने इस रिपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें रत्ना अप्पनेंडर, देविका प्रसाद, सज्जाद हसन के साथ-साथ अनेक गुमनाम सलाहकार भी शामिल हैं।

REDRESS टीम ने डेस्क-आधारित एवं ओपन-सोर्स रिसर्च के माध्यम से डेटा संकलित और विश्लेषित किया। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र निकायों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों तथा मीडिया संस्थानों की प्रकाशित सामग्रियों, वक्तव्यों और रिपोर्टों का उपयोग किया गया। केस स्टडीज़ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर चयनित की गईं।

इस प्रकाशन को यूरोपियन यूनियन द्वारा वित्तपोषित किया गया है और इसे यूनाइटेड अगेंस्ट टॉर्चर कंसोर्टियम इनिशिएटिव (यूएटीसी) के तहत विकसित किया गया है। इसके विषय-वस्तु की संपूर्ण जिम्मेदारी REDRESS की है, और यह आवश्यक नहीं कि यह यूरोपियन यूनियन के विचारों को प्रतिबिंबित करता हो।

UNITED AGAINST TORTURE

Funded by the European Union

कार्यकारी सारांश और सुझाव

भारत में यातना और दुर्व्यवहार कोई असामान्य घटनाएँ नहीं हैं — ये प्रथाएँ व्यवस्थित एवं गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं, जिन्हें प्रायः राज्य के अधिकारियों द्वारा दण्ड के बिना अंजाम दिया जाता है। हालाँकि भारत ने 1997 में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT) पर हस्ताक्षर किए थे, फिर भी वो दुनिया भर के उन 21 देशों में से एक है जिसने अभी तक इस संधि की पुष्टि नहीं की है।

भारतीय कानून में यातना को एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित न किए जाने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यातना या दुर्व्यवहार की श्रेणी में आने वाले कृत्यों के बारे में व्यापक और विश्वसनीय सरकारी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा संकलित, राज्यों में होने वाली हिंसा की रिपोर्टें एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती हैं, फिर भी वे इस मुद्दे को पूरे विस्तार और गंभीरता से उजागर करने में विफल रही हैं। यह आंशिक रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को लेकर मौजूद चिंताओं के कारण है। इस बीच, भारतीय नागरिक समाज संगठन (CSO) और मानवाधिकार रक्षक महत्वपूर्ण जोखिमों के बावजूद, यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण और पर्दाफाश करना जारी रखे हुए हैं।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सामाजिक सक्रियता और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित यह रिपोर्ट दर्शाती है कि व्यवहारिक स्तर पर भारत में यातना सामान्यीकृत हो चुकी है।

पुलिस और सुरक्षा बल कानून लागू करने के लिए नियमित रूप से यातना और दुर्व्यवहार का उपयोग करते हैं। शारीरिक और यौन हिंसा के साथ-साथ हिरासत में दुर्व्यवहार के अन्य रूप भी बहुत आम हैं। वर्षों से हिरासत में मौतों की चिंताजनक दरें दर्ज की जा रही हैं, फिर भी इन पर व्यापक रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। तथाकथित पुलिस 'मुठभेड़ों' में, आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान, और देश के विशिष्ट क्षेत्रों में न्यायेतर (एक्स्ट्रा जुडिशल) हत्याएँ भी प्रचलित हैं। जाँच के दौरान अधिकारी आमतौर पर कथित अपराधियों से स्वीकारोक्ति या जानकारी प्राप्त करने, या वंचित समुदायों के व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए यातना का इस्तेमाल करते हैं।

इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए, भारत का कानूनी ढाँचा, स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जैसे कानूनी परामर्श का अधिकार, गिरफ्तारी पर चिकित्सा परीक्षण, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जारी किए हैं। हालाँकि, हाल की आपराधिक कानून सुधारों की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इन सुधारों से पुलिस की शक्तियाँ विस्तारित हुई हैं और नागरिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की प्रभावशीलता में कमी आई है।। इसके अतिरिक्त, भारत के कानूनी ढाँचे और उसके क्रियान्वयन के बीच का अंतर – जिसमें उचित प्रक्रिया की व्यवस्थागत अवहेलना और कमज़ोर न्यायिक निगरानी शामिल है – बेहद चिंताजनक है।

भारत में राज्य द्वारा की जाने वाली हिंसा एक लगातार अधिक शत्रुतापूर्ण माहौल में घटित होती है, जिसकी विशेषता सिविक स्पेस का सिकुड़ना है। नागरिक समाज संगठनों के संचालन पर प्रतिबंध, और अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और सभा करने की स्वतंत्रता पर अंकुश के साथ मानवाधिकार रक्षकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की आवाज़ों को दबाने के लिए मनमाने ढंग से गिरफ़्तारियाँ और यातनाएँ की जाती हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान, पुलिस अधिकारी बल प्रयोग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं और प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ घातक और कम घातक, दोनों तरह के हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं – जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मौतें हुई हैं। सरकार का विरोध करने वालों के ख़िलाफ़ आतंकवाद-रोधी क़ानून का दुरुपयोग आम हो गया है, क्योंकि अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक प्रावधान दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं। अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA), व्यक्तियों और संगठनों को भारत के विरुद्ध असंतोष भड़काने जैसी "गैरकानूनी गतिविधियों" के लिए "आतंकवादी" घोषित करने और अपराधी ठहराने का अधिकार देता है। यह कानून मुकदमे से पहले लंबी हिरासत की अनुमति देता है और ज़मानत की कड़ी शर्तें लगाता है जिससे रिहाई काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अंततः, कानून के तहत फ़र्ज़ी आपराधिक मुकदमा चलाने की प्रक्रिया ही अक्सर सज़ा का एक रूप बन जाती है, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है।

हाशिए पर रहने वाले समुदाय, ख़ासकर अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी), राज्य की हिंसा से काफ़ी प्रभावित हैं। संवैधानिक और विधायी सुरक्षा के बावजूद, इन समुदायों को अब भी व्यवस्थागत भेदभाव, यातना और हिंसा के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है। भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड उनके ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा देते हैं और ऐसे कृत्यों के लिए दण्डमुक्ति उन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहार का और भी ज़्यादा शिकार बनाती है। रिपोर्टों में हिरासत में गंभीर मारपीट, यौन हिंसा, जाति-आधारित गाली-गलौज और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का विवरण दिया है - जिनमें कुछ की मौत भी हो जाती है।

मुस्लिम, ईसाई और सिख और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को भी राज्य द्वारा यातना, न्यायेतर हत्याओं और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का अधिक सामना करना पड़ता है। भेदभावपूर्ण और राष्ट्रवादी बयानबाज़ी और नीतियों ने ऐसी हिंसा को तेज़ी से स्वीकार्य बना दिया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिरासत में अत्याचार एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान, अंतर-सांप्रदायिक अशांति के जवाब में, कानून प्रवर्तन अभियानों में, और कथित "गौ-तस्करी" को रोकने की आड़ में, इन समूहों के खिलाफ हिंसा में राज्य के अधिकारियों को लिप्त पाया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अतिरिक्त दंडात्मक उपाय, जैसे घरों को ध्वस्त करना और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करना, उनके हाशिए पर होने की स्थिति को और गहरा करते हैं।

भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों की वजह से सुरक्षा और सशस्त्र बलों द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्थित हिंसा देखी गई है। इनमें छत्तीसगढ़, भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और मणिपुर सहित भारत के पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र शामिल हैं। उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने की आड़ में, अधिकारियों ने कथित तौर पर नियमित रूप से यातना, न्यायेतर हत्याएं और जबरन गायब करने की घटनाएं की हैं। भारतीय अधिकारी नियमित रूप से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) और (UAPA) का हवाला देकर इन उल्लंघनों को उचित ठहराते हैं, जो–आपातकालीन प्रावधानों के लक्षण होने के बावजूद – आपातकाल की औपचारिक घोषणा के बिना ही लागू होते हैं, और लंबे समय तक लागू रहते हैं। AFSPA के माध्यम से, राज्य सरकारें या राष्ट्रीय सरकार कुछ क्षेत्रों को "अशांत" घोषित कर सकती हैं, जिससे सशस्त्र बलों को इन क्षेत्रों में लोगों को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और उनके विरुद्ध घातक बल प्रयोग करने के व्यापक और अनियंत्रित अधिकार मिल जाते हैं। इस प्रकार, AFSPA सशस्त्र बलों द्वारा व्यापक हत्याओं और यातनाओं को बढ़ावा देता है और ऐसे कृत्यों को दंड से मुक्ति के साथ अंजाम देने की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों, और नागरिक समाज संगठनों ने बार-बार AFSPA और UAPA को निरस्त करने या संशोधित करने का आह्वान किया है, जो अभी भी बिना किसी बदलाव के लागू हैं।

भारत में यातना के लिए दंडमुक्ति एक आम बात है। हालाँकि शिकायतें प्राप्त करने और यातना तथा अन्य राजकीय दुर्व्यवहारों की जाँच करने के लिए तंत्र मौजूद हैं, फिर भी न्याय और जवाबदेही पीड़ितों और उत्तरजीवियों की पहुँच से काफी हद तक बाहर हैं। कई लोगों को शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करने पर उत्पीड़न, धमकी या यहाँ तक कि और अधिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारी अक्सर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने में देरी करते हैं या मना कर देते हैं, जो जाँच को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक कदम है। जहाँ जाँच होती भी है, वो अक्सर देरी, खराब दस्तावेज़ीकरण और स्वतंत्रता की कमी से प्रभावित होती है, जिसमें पुलिस अधिकारी अक्सर हस्तक्षेप करते हैं या अपने ही दुर्व्यवहारों को छिपाने की कोशिश करते हैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे बाहरी शिकायत निकाय – जिन्हें स्वतंत्र होना चाहिए था – अपने ही सहयोगियों की जाँच के लिए पुलिसकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जिससे निष्पक्षता कमज़ोर होती है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी काफी हद तक अप्रभावी साबित हुआ है; जो बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त करने के बावजूद अपेक्षाकृत कम मामलों में सिफ़ारिशें जारी करता है, और शायद ही कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँग करता है। आयोग ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कभी अनुशंसा नहीं की है, हालाँकि कुछ पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी सिफारिशों को लागू करने में असमर्थ रहा है।

जवाबदेही के मार्ग में कई अतिरिक्त बाधाएँ मौजूद हैं। राज्य के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता, और सशस्त्र बलों तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देने वाले राज्य के अधिकारियों को दी जाने वाली व्यापक छूट, जवाबदेही को और जटिल बना देती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)– जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया है – के तहत राज्य या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पुलिस अधिकारियों सहित लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यह जवाबदेही की राह में एक बड़ी बाधा है क्योंकि ऐसी अनुमति शायद ही कभी दी जाती है। साथ ही, AFSPA और UAPA के तहत सैन्य कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों को दी जाने वाली व्यापक छूट मानवाधिकारों के उल्लंघन को दंड से मुक्ति की अनुमति देती है।

भारत में अपराधियों के लिए यातना और दंड से मुक्ति के सामान्यीकृत होते वातावरण ने संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों और विशेषज्ञों में बढ़ती चिंता को जन्म दिया है, हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया सीमित रही है। कई देशों ने भारत की 2022 यूनिवर्सल पीरियाडिक रिव्यु (UPR) के दौरान इस मुद्दे पर सिफारिशें कीं, पर कई देशों ने द्विपक्षीय बातचीत में भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की है है। वैश्विक व्यापार में भारत की रणनीतिक और भू-राजनीतिक स्थिति और महत्व ने देशों की ओर से सार्थक कूटनीतिक या आर्थिक दबाव डालने की अनिच्छा को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्व्यवहार की प्रवृत्तियाँ बिना किसी ठोस चुनौती के बड़े पैमाने पर जारी रही हैं।

भारत में यातना और दुर्व्यवहार के संकट से निपटने के लिए यह रिपोर्ट भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए लक्षित सिफ़ारिशें प्रस्तुत करती है। यह यातना की रोकथाम, पीड़ितों को न्याय और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने, तथा देश में यातना और अन्य गंभीर उल्लंघनों को समाप्त करने हेतु आवश्यक कानूनी और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई का आह्वान करती है।

सिफ़ारिशें

भारत सरकार को

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और विधायी सुधार

- संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए।
- संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) के वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि की जाए और हिरासत के सभी स्थानों की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए एक प्रभावी और स्वतंत्र राष्ट्रीय निवारक तंत्र (NPM) स्थापित किया जाए।
- संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) के अनुरूप, यातना को घरेलू कानून में एक पृथक और दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाए — उदाहरणस्वरूप, भारतीय न्याय संहिता (जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है) में आवश्यक संशोधन किए जाएँ।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ली है) की धारा 148-150 में संशोधन करें, ताकि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके कि किन परिस्थितियों में सभाओं को तितर-बितर किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जाए कि बल प्रयोग वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, तथा घातक बल का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध हो, और कम घातक हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश, प्रदर्शन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र के मॉडल प्रोटोकॉल, और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून में तुरंत संशोधन या निरस्तीकरण किया जाए जिसमें कानूनी निश्चितता, आवश्यकता, आनुपातिकता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा शामिल हो। विशेष रूप से, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि:
    a. अधिकारियों को अनियंत्रित शक्तियां प्रदान करने वाले और लंबे समय तक मुकदमे से पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले प्रावधानों को निरस्त किया जाए।
    b. इन कानूनों में अस्पष्ट या व्यापक भाषा शामिल न किया जाए जो मानवाधिकार रक्षकों, कार्यकर्ताओं और हाशिए पर स्थित समुदायों को लक्षित करने के लिए उनके दुरुपयोग की अनुमति दे सकती है।
    c. आतंकवाद से संबंधित अपराधों के संदिग्ध व्यक्तियों को सभी कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएँ, जिसमें मनमानी हिरासत से सुरक्षा, त्वरित और निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा तक पहुंच, और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार शामिल हैं।
    d. 'अशांत क्षेत्रों' में सुरक्षा उपायों का उपयोग सीमित, अस्थायी, आनुपातिक, आवश्यक और स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण के अधीन किया जाए।
- उन प्रावधानों को रद्द किया जाए जो सरकारी अधिकारियों की सभी संबंधित घरेलू कानूनों से प्रतिरक्षा देते हैं या यातना और अन्य गंभीर अपराधों- जैसे कि न्यायेतर हत्याओं के आरोपी सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पहले से मंज़ूरी ज़रूरी करते हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने और इस संस्था को सशस्त्र बलों द्वारा यातना या अन्य दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने की अनुमति देने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाए।
- भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला व्यापक कानून अपनाया जाए, जिसमें अंतः संबंधी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव शामिल हों, ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर स्थित समूहों को यातना और अन्य प्रकार की हिंसा से सुरक्षा मिल सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए और यातना विरोधी मानकों को का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन किया जाए।

यातना-रोधी मानकों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन

- मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए।
- गिरफ़्तारी के क्षण से ही स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों के लिए विधिक सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन और नियमित न्यायिक निगरानी को सुनिश्चित किया जाए—जिसमें वकील तक शीघ्र पहुँच, अधिकारों की जानकारी, न्यायिक पर्यवेक्षण, स्वतंत्र चिकित्सकीय परीक्षण, और किसी परिवार सदस्य को सूचित करने का अधिकार शामिल है—ताकि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।
- पुलिस, जेल कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम में मानवाधिकार और यातना विरोधी प्रशिक्षण को एकीकृत किया जाए, जिसमें प्रभावी साक्षात्कार पर मेंडेज़ सिद्धांत, इस्तांबुल प्रोटोकॉल और मिनेसोटा प्रोटोकॉल शामिल हों।

- न्यायिक मज़िस्ट्रेटों को निर्देश दें कि वे रिमांड सुनवाइयों के दौरान टॉर्चर या दुर्व्यवहार के आरोपों की सक्रिय रूप से जाँच करें, और अंतर-राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टॉर्चर से प्रभावित किसी भी साक्ष्य को किसी भी कानूनी कार्यवाही से बाहर करें — सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसे साक्ष्य का उपयोग स्वयं कथित आरोपी के विरुद्ध टॉर्चर के प्रमाण के रूप में किया जा रहा हो।

दण्डहीनता का निराकरण।

- यातना का दस्तावेजीकरण करने और पीड़ितों का समर्थन करने वाले नागरिक समाज संगठनों के कार्य को सुगम एवं सुरक्षित वातावरण में संचालित करने की व्यवस्था की जाए, जिसमें अनुदान प्रदान करना, एक सक्षम कानूनी और नीतिगत माहौल सुनिश्चित करना, उनके संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों का उपयोग करने से बचना और मानवाधिकार रक्षकों को धमकी, उत्पीड़न या प्रतिशोध से बचाना शामिल है।
- यातना और दुर्व्यवहार के आरोपों, सक्रिय जांच और लगाए गए प्रतिबंधों पर अलग-अलग डेटा का व्यवस्थित संग्रह और प्रकाशन सुनिश्चित किये जाएँ।
- यह सुनिश्चित करें कि यातना के सभी पीड़ित और उनके परिवार, जिनमें हिरासत में लिए गए लोग भी शामिल हैं, स्वतंत्र निकायों को सुरक्षित रूप से शिकायतें दर्ज करा सकें और प्रतिशोध से सुरक्षित रहें।
- यह सुनिश्चित करें कि यातना के सभी आरोपों का दस्तावेज़ीकरण इस्तानबुल प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए, जिसमें अनिवार्य और स्वतंत्र चिकित्सकीय-कानूनी परीक्षण भी शामिल हों।
- यातना, हिरासत में मौत, न्यायेतर हत्याओं और अन्य गंभीर उल्लंघनों के सभी आरोपों की त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कार्य को स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ संपादित कर सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच से जुड़े अधिकारी पूर्णतः स्वतंत्र हों, और उन्हें यातना तथा अन्य गंभीर उल्लंघनों की जांच के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त हो।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मामलों में जांच के लिए समान और उच्च मानक अपनाए जाएं — चाहे वे मानवाधिकार रक्षकों, वकीलों, पत्रकारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों या अन्य हाशिये पर समुदायों से संबंधित हों — और सभी पीड़ितों और उत्तरजीवियों को न्याय और उचित मुआवज़ा प्राप्त हो।
- पूरे देश में यातना के सामान्यीकरण को चुनौती देने के लिए और जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाये जाएँ।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से

- भारत के साथ बातचीत में, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी, विकास सहयोग और राजनयिक संवाद के माध्यम से बातचीत के ज़रिए, यातना और दुर्व्यवहार को खत्म करने को प्राथमिकता दी जाए।
- भारत के साथ सभी व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग समझौतों में मानवाधिकार मानक — जिनमें यातना पर प्रतिबंध भी शामिल हो — को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
- भारत में असहमति को दबाने और धार्मिक या अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए यातना, दुर्व्यवहार और गैर-न्यायिक हत्याओं के इस्तेमाल पर सार्वजनिक रूप से और लगातार चिंता जताएं।
- यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच को बढ़ावा दें, ताकि सभी उपलब्ध माध्यमों के माध्यम से—और जहाँ उपयुक्त हो, सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्र (यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन) के सिद्धांत के तहत—दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- मानवाधिकार उल्लंघनों का संकलन करने, कानूनी सहायता प्रदान करने और न्याय और जवाबदेही की वकालत करने के लिए काम कर रहे भारतीय नागरिक समाज संगठनों को अनुदान और सुरक्षा तंत्र सहित सभी माध्यमों से समर्थन दें।
- राजनयिक जुड़ाव और विधायी और संस्थागत सुधारों पर सहयोग के माध्यम से, भारत द्वारा UNCAT के अनुसमर्थन को प्रोत्साहित करें और समर्थन करें।
- भारत में यातना के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करने और संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों और विशेष प्रक्रियाओं की सिफारिशों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सहित राजनयिक और बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करें।

परिचय

> **हिरासत में अमानवीय यातना, हमले और मौतें, जो चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुकी हैं, कानून के शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं। समाज का व्यथित होना स्वाभाविक है। न्याय की मांग और अधिक तीव्र हो जाती है तथा तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस होती है।**[1]
>
> – भारत का सर्वोच्च न्यायालय (मुंशी सिंह गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य)

भारत में हिरासत में यातना और दुर्व्यवहार एक प्रणालीगत और लगातार चलने वाली समस्या रही है।[2] 1980 की शुरुआत में ही राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस द्वारा «शॉर्टकट तरीकों से जल्दी नतीजे पाने» के लिए हिरासती यातना के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को माना था।[3] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2018 में उल्लेख किया कि «भारत में हिरासती हिंसा और यातना इतनी ज़्यादा है कि यह लगभग सामान्य प्रक्रिया बन गया है» ।[4] भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य राष्ट्रीय स्तर के न्यायालयों ने भी कानून लागू करने वाली संस्थाओं द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग, हिरासती यातना और मानवाधिकारों के अन्य गंभीर उल्लंघनों के लिए जवाबदेही की कमी को उजागर किया है।[5]

आज भी, नागरिक समाज संगठन, मानवाधिकार रक्षक और पीड़ित, अलग-अलग संदर्भों में कानून लागू करने वाली संस्थाओं और सुरक्षा बलों द्वारा यातना के इस्तेमाल को उजागर कर रहे हैं। यातना के मामले सामने आए हैं जहाँ पुलिस और न्यायिक हिरासत में, आपराधिक जांच के दौरान पिटाई, बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों का इस्तेमाल कबूलनामे निकलवाने, जानकारी हासिल करने या व्यक्तियों को सज़ा देने के लिए किया जाता है। अकेले 2024 में, हिरासती मृत्यु की 130 शिकायतें दर्ज की गईं, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने लंबित हिरासती मृत्यु के मामलों की संख्या बढ़कर 2,448 हो गई है ।[6]

इसी प्रकार, तथाकथित पुलिस 'एनकाउंटर' के रूप में न्यायेतर हत्याओं का बढ़ता प्रयोग भी गहरी चिंता का विषय है, जहाँ संदिग्ध व्यक्तियों को मारने या स्थायी रूप से विकलांग करने के इरादे से मारना या गोली मारना अक्सर अपराध नियंत्रण के एक स्वीकार्य उपाय के रूप में देखा जाता है।[7] यातना और अन्य दुर्व्यवहार उन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर होते हैं जिन्हें राज्य द्वारा 'अशांत क्षेत्र'[8] घोषित किया गया है - कथित तौर पर आतंकवाद और विद्रोह से प्रभावित -जहाँ सशस्त्र बलों[9] सहित सुरक्षा बल नागरिकों और हाशिए पर पड़े समूहों के खिलाफ हिंसा करते हैं।[10] इसी तरह के उल्लंघन उन क्षेत्रों में सैन्य अभियानों में भी होते हैं जिन्हें 'अशांत क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।[11]

यह भी दर्ज किया गया है कि शांतिपूर्ण सभाओं को नियंत्रित करने के दौरान अधिकारियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, जो यातना या दुर्व्यवहार के बराबर है, और कई बार प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से तितर-बितर कर डराने-धमकाने की कोशिश की।[12] यह एक ऐसे बढ़ते हुए शत्रुतापूर्ण माहौल में हो रहा है जहाँ राजनीतिक असंतुष्टों, पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों को यातना और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता

1 2005 (9) SCC 631
2 उपेंद्र बख्शी, भारत: एक बड़ा धोखा: राज्य द्वारा टॉर्चर के कृत्यों के लिए दण्ड से मुक्ति जारी है। कानून बनाने वाले और अदालतें अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए हैं
3 भारतीय विधि आयोग, रिपोर्ट संख्या 273, 'यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' का कानून के माध्यम से कार्यान्वयन (UNCAT का कार्यान्वयन), अक्टूबर 2017, पृ. 35. यह भी देखें राष्ट्रीय पुलिस आयोग, चौथी रिपोर्ट, जून 1980, पृ. 8, एस 27.26
4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), वार्षिक रिपोर्ट 2017–2018, पृ. 44
5 फ्रांसिस कोराली मुलीन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 1981 (1) SCC 608; गौरी शंकर शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 SCC (SUPP) 656; यह भी देखें भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार्यान्वयन, अक्टूबर 2017, पृ. 35
6 जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच, NHRC ने NHRC द्वारा रजिस्टर/निपटाने वाले मामलों के मंथली मुख्य आंकड़ों में हिरासत में हुई मौतों की 2,170 रिपोर्ट दर्ज कीं; ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW), भारत: 2024, 2025 की घटनाएँ भी देखें।
7 Frontline, The Hindu, "तत्काल अन्याय: राज्य की मनमानी पर — 'राज्य को भीड़ की चाल अपनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती'", 4 अप्रैल 2025.
8 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 के अनुसार, एक 'अशांत क्षेत्र' वह क्षेत्र है जिसे धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा उस समय के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने की शक्ति राज्य के मामले में राज्यपाल के पास और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक या केंद्र सरकार के पास होती है।
9 'सशस्त्र बलों' में सैन्य और अर्ध-सैन्य बल शामिल हैं जैसे भारत के सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखें इंडिया टुडे, CRPF से BSF तक: भारत के विभिन्न रक्षा बलों और उनकी भूमिकाओं को जानें, 15 फरवरी 2019.
10 HRW, भारत, 2024 की घटनाएँ, 2025.
11 फ्रंटलाइन, नागरिक समाज समूहों ने बस्तर में संघर्ष विराम का आह्वान किया, आदिवासियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा की, 5 अप्रैल 2025.
12 अमनेस्टी इंटरनेशनल (AI), भारत: प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग, मनमाना हिरासत और दंडात्मक कदम तुरंत बंद किए जाने चाहिए (भारत: अत्यधिक बल का प्रयोग), 14 जून 2022; दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों पर तथ्य-निष्ठ रिपोर्ट, जुलाई 2020

है, और असहमति को दबाने की एक व्यापक रणनीति के तहत आतंकवाद-रोधी कानूनों के अभियोजन का भी सामना करना पड़ता है।[13] धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर मौजूद समुदायों—जैसे दलितों और मुसलमानों—के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव के कारण यह समूह कानून प्रवर्तन संस्थाओं की हिंसा से अनुपातहीन रूप से प्रभावित होते हैं।[14]

इस गंभीर स्थिति ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों, संधि निकायों और यूनिवर्सल पीरियाडिक रिव्यु (UPR) कार्य समूह का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने इस पर बार-बार गहरी चिंता व्यक्त की है, और भारत से यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT) का अनुसमर्थन करने और यातना से निपटने के उपायों को लागू करने का आग्रह किया है।[15] जुलाई 2024 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति (HRCttee) ने हिरासत में मौतों की उच्च दर, पीड़ितों के परिवारों के खिलाफ प्रतिशोध और बंदियों - विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लोगों - के खिलाफ बलात्कार सहित यातना के प्रयोग पर चिंता व्यक्त की है।[16] HRCttee ने तथाकथित 'अशांत क्षेत्रों' में आतंकवाद-रोधी कानून के प्रयोग की भी निंदा की, जिसके परिणामस्वरूप:

> व्यापक और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, जिनमें अत्यधिक बल प्रयोग के कारण गैरकानूनी हत्याएं, वर्षों तक औपचारिक आरोपों के बिना मनमाना हिरासत, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जिनका शीघ्रता से निपटारा नहीं किया जाता, यौन हिंसा, जबरन विस्थापन और यातना एवं दुर्व्यवहार शामिल हैं।[17]

भले ही भारत ने 1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर किए थे और इसे अनुमोदित करने का बार-बार आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक इस संधि की पुष्टि नहीं की है।[18] वह अपने घरेलू कानूनी ढांचे में यातना को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में शामिल करने में भी विफल रहा है, क्योंकि 2010 में सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल तथा 2017, 2018 और 2022 में पेश किए गए निजी विधेयकों के माध्यम से यातना-विरोधी कानून बनाने के प्रयासों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और ये पहलें अब तक ठप पड़ी हैं।[19] 2023 के आपराधिक क़ानून सुधारों की भी आलोचना की गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस शक्तियों का विस्तार करके, हिरासत अवधि बढ़ाकर, और लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित न करके, पुलिस दुरुपयोग के विरुद्ध मौजूद सुरक्षा उपायों को कमजोर कर दिया है।[20] यातना को अपराध न मानना, यातना विरोधी मानकों को ठीक से लागू न करना और खास समूहों को निशाना बनाने के लिए कानूनों का गलत इस्तेमाल एक ऐसा माहौल बनाता है जो यातना को बढ़ावा देता है। इसका व्यापक प्रसार, सामान्यीकरण, और राज्य की ओर से उचित प्रतिक्रिया का अभाव — ये सभी ऐसा माहौल तैयार करते हैं, जो अपराधियों को बिना किसी जवाबदेही के भय के, लगातार ऐसे उल्लंघन करने की छूट देता है।

भारत में यातना और दुर्व्यवहार की व्यापकता ने भारत के बाहर की अदालतों को भी चिंतित कर दिया है, खासकर प्रत्यर्पण के मामलों में, जहाँ अदालतों ने उन भारतीय नागरिकों को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया जिनके खिलाफ वैध प्रत्यर्पण आदेश हैं। यह निर्णय यातना और दुर्व्यवहार के संभावित जोखिम के आधार पर लिए गए, भले ही भारत सरकार ने पूर्ण आश्वासन प्रदान किए हों।[21] राष्ट्रीय अदालतों के ऐसे निष्कर्षों और 2022 के यूपीआर[22] में 31 देशों द्वारा भारत को दी गई सिफारिशों के बावजूद भारत में बिगड़ती स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया सीमित रही है, और कई देश भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने से हिचकिचाते

13 बीबीसी, सिद्दीक़ क़प्पन: दो साल बाद भारतीय पत्रकार जेल से रिहा, 2 फ़रवरी 2023

14 CNN, भारतीय पुलिस न्याय दिलाने के लिए हिंसा को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करती है। इसका सबसे ज़्यादा बोझ ग़रीबों पर पड़ता है, 3 दिसंबर 2020; साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन, भारत में यातना, दण्डहीनता और धार्मिक अल्पसंख्यक, अप्रकाशित, पृ. 9; सिटिज़न्स अगेन्स्ट हेट, सबको चुप करा दिया गया है: उत्तर प्रदेश में एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की ज़्यादतियाँ और हिंसा के बाद की प्रताड़नाएँ, 2 मार्च 2020

15 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (HRC), सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR 2022) के कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, 14 दिसंबर 2022, A/HRC/52/11

16 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति (HRCttee), भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट पर निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ (Concluding Observations 2024), 25 जुलाई 2024, CCPR/C/IND/CO/4, पैरा 33

17 HRCttee, निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ 2024, पैरा 27

18 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR), भारत की अनुसमर्थन स्थिति

19 यह विधेयक पहली बार 2010 में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा (संसद का निचला सदन) ने इसे पारित किया। बाद में इसे राज्यसभा (ऊपरी सदन) की एक चयन समिति के पास भेजा गया। चयन समिति ने सिफ़ारिशें कीं, लेकिन आम चुनाव के लिए लोकसभा के विघटन के साथ ही विधेयक निष्प्रभावी हो गया। 2017, 2018 और 2022 में यातना-निरोधक विधेयक निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए।

20 कॉमन कॉज़, तीन नए आपराधिक क़ानून, 2024

21 देखें भंडारी बनाम भारत सरकार [2025] EWHC 449 (प्रशासनिक)। जिला न्यायाधीश, जिनके इस मामले पर निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि मिली, ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कई कारकों और स्रोतों पर भरोसा किया कि पुलिस अधिकारियों या अन्य जांच संस्थाओं द्वारा यातना और कुप्रवृत्ति का जोखिम अच्छी तरह स्थापित है। इनमें शामिल थे: भारत द्वारा UNCAT की पुष्टि न करना; भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 1 SCC 416 के बाद से यातना की स्वीकृति; भारतीय विधि आयोग और NHRC की रिपोर्टें; और विशेषज्ञ राय। देखें: भारत संघ सरकार बनाम विरकरन अवस्ती, 11 अप्रैल 2025, और एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, टॉर्चर अपडेट: इंडिया, दिसंबर 2018

22 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, (UNHRC) UPR 2022, पैरा 151–152

हैं।[23] वैश्विक सामान और सेवाओं के व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, और उसकी भूराजनीतिक अहमियत[24] ऐसे हालात बनाती हैं जिनमें देश मानवाधिकार मुद्दों पर भारत पर आर्थिक या कूटनीतिक दबाव डालने से कतराते हैं।

यह रिपोर्ट भारत में चल रही व्यापक यातना, दुर्व्यवहार और राज्य हिंसा के अन्य रूपों पर प्रकाश डालती है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह यातना के स्वरूप का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें पुलिस और न्यायिक हिरासत में हिरासत में बलात्कार और हिंसा के अन्य रूप, और पुलिस 'मुठभेड़ों' में गैर-न्यायिक हत्याएं शामिल हैं (भाग I)। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि यातना का उपयोग न केवल राजनीतिक दमन के उपकरण के रूप में किया जाता है, बल्कि भेदभावपूर्ण उत्पीड़न के एक साधन के रूप में भी किया जाता है, जो राजनीतिक असंतुष्टों, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों जैसे समूहों, और संघर्ष और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों को प्रभावित करता है (भाग II)। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट भारत के राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों और खामियों का खुलासा करती है जो ऐसे दुर्व्यवहारों को रोकने या संबोधित करने में विफल रहता है (भाग III), और दण्ड मुक्ति की गहरी संस्कृति को रेखांकित करती है जो अपराधियों को जवाबदेही के डर के बिना कार्य करने की अनुमति देती है (भाग IV)। अंत में, यह रिपोर्ट भारत को यातना और दुर्व्यवहार की रोकथाम, जांच तथा अभियोजन से संबंधित विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करती है। साथ ही, यह उन अन्य देशों को भी संबोधित करती है जिन पर यातना पर पूर्ण प्रतिबंध बनाए रखने की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है।

23 संदीप कुमार, भारत का भू-राजनीतिक उदय संदर्भ में: क्षेत्रीय प्रभाव, 22 मई 2023
24 सौतिक बिस्वास, भारत: क्या सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है? 10 दिसंबर 2024

यातना के स्वरूप

© Reuters/Mansi Thapliyal

एक पुलिसकर्मी नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाते हुए । भारतीय जेलों में यातना अभी भी बड़े पैमाने पर होती है, जिसमें बेरहमी से पिटाई और हिरासत में मौत के मामले सामने आए हैं।

भारत में यातना विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में की जाती है। और इसके कई रूप होते हैं, जैसे पुलिस और न्यायिक हिरासत में पिटाई और यौन हिंसा – जिसमें मनमानी गिरफ्तारियों या गैर-कानूनी हिरासत के दौरान होने वाली घटनाएं शामिल हैं –[25] और तथाकथित पुलिस 'एनकाउंटर' में गैर-न्यायिक हत्याएं। UNCAT के तहत, यातना की परिभाषा में चार तत्व शामिल हैं: (i) गंभीर दर्द या पीड़ा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक; (ii) जानबूझकर पहुँचाया गया हो; (iii) किसी खास मकसद के लिए, जैसे कि गुनाह कबूल करवाना, सज़ा देना, डराना या मजबूर करना, या किसी भी तरह के भेदभाव के आधार पर किसी भी कारण से; (iv) किसी सरकारी अधिकारी या आधिकारिक क्षमता में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके उकसाने पर, या उसकी सहमति या मिलीभगत से।[26] इस परिभाषा के आधार पर, रिपोर्ट का यह सेक्शन भारत में सरकारी लोगों द्वारा किए जाने वाले यातना के सबसे आम तरीकों की जांच करता है। दस्तावेजी उदाहरणों के माध्यम से, यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, यातना कानून-प्रवर्तन और जांच का एक व्यवस्थित हथियार बनकर रह गई है, जो नियंत्रण और डराने-धमकाने को बढ़ावा देती है।

25 भारत में बिना किसी कानूनी आधार या प्रक्रिया के और औपचारिक हिरासत स्थलों के बाहर व्यक्तियों की हिरासत को कभी-कभी 'अनौपचारिक हिरासत' कहा जाता है। देखें राज कुमार सिंह, न्याय सुनिश्चित करना: भारत में पुलिस अधिकार के कानूनी और संवैधानिक दायरे, 2024

26 यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (10 दिसंबर 1984 को अपनाया गया, 26 जून 1987 को लागू हुआ) 1465 UNTS 85 (UNCAT), अनुच्छेद 1

पुलिस हिरासत में यातना

> **मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पुलिस स्टेशनों में होता है।"**
>
> – नुथलपति रमना, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, 2021[27]

भारत में कानून लागू करने के तरीकों में यातना लंबे समय से जड़ें जमा चुकी है। यह एक ऐसी विरासत है जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही है।[28] आज भी यह एक गंभीर चिंता का विषय है और एक व्यापक रूप से प्रयुक्त तरीका है जो जांच तकनीकों का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।[29]

यह देखते हुए कि भारतीय कानून में यातना की कोई परिभाषा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) और ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी आधिकारिक सरकारी एजेंसियों के माध्यम से यातना के मामलों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करना मुश्किल है। हालांकि NCRB ने 2017 और 2022 के बीच पुलिस के खिलाफ दर्ज यातना के कई मामलों को दर्ज़ किया,[30] लेकिन यह संख्या NHRC और भारतीय नागरिक समाज द्वारा दर्ज किए गए संबंधित आँकड़े की तुलना में काफी कम है, जिसे इस रिपोर्ट में आगे प्रस्तुत किया गया है। नागरिक समाज संगठनों की रिपोर्टों के अलावा, NHRC द्वारा संकलित आँकड़े यातना की घटनाओं से जुड़े सबूत प्रदान करते हैं। NHRC हर साल उसे रिपोर्ट किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, और लगातार यह दिखाया है कि अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना पूरे देश में सामान्य हो गई है।[31] फिर भी, NHRC के आंकड़े हिरासत में हुई मौतों के मामलों तक ही सीमित हैं और इसमें यातना के सभी मामले शामिल नहीं हैं।[32] कम रिपोर्टिंग भी एक मुद्दा है, क्योंकि अधिकांश मामलों में, पीड़ित के वकील, नागरिक समाज संगठन या मानवाधिकार रक्षक ही NHRC को यातना की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, और हिरासत में लिए गए कई व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधित्व या नागरिक समाज की वकालत तक पहुंच नहीं होती है।

यातना का चलन इतना व्यापक और आम है कि यह पुलिस व्यवस्था में सामान्य रूप से स्वीकृत हो चुकी है।[33] 2019 में भारत में लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों के देशव्यापी सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 37% पुलिस अधिकारियों ने (कथित) छोटे अपराधों के लिए लोगों को दंडित करना अपना कर्तव्य माना, 75% ने महसूस किया कि संदिग्ध अपराधियों के प्रति हिंसक होने में पुलिस सही है, जबकि लगभग 80% ने कबूलनामा निकलवाने के लिए संदिग्धों को पीटना स्वीकार्य पाया।[34]

भारत में हिरासत में यातना – अन्य संदर्भों की तरह – आमतौर पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पहले 24 घंटों के भीतर होती है, इससे पहले कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।[35] यह भी बताया गया है कि पुलिस हिरासत में यातना का जोखिम तब बढ़ जाता है जब एक मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 15 दिन या उससे ज़्यादा समय तक पुलिस हिरासत में रखा जाए।[36] पूछताछ के दौरान अक्सर कबूलनामे निकलवाने या कथित अपराधों के लिए व्यक्तियों को सज़ा देने के लिए यातना का इस्तेमाल किया जाता है।[37] भारतीय समाचार प्लेटफ़ॉर्म, न्यूज़ मिनट, की एक 2025 की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के हड्डियों के टूटने के बढ़ते हुए आँकड़े सामने आए हैं।[38] रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के केंद्रीय कारागारों में रिमांड पर कम से कम 304 अभियुक्तों को 1 जनवरी से 7 अक्टूबर, 2024 के बीच पुलिस द्वारा हड्डियों के टूटने की चोटें आयी थीं।[39]

27 अमृत ढिल्लों, भारत के पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों के लिए खतरा हैं, कहते हैं मुख्य न्यायाधीश, 10 अगस्त 2021
28 कदीर आलम, भारतीय उपमहाद्वीप में यातना और अमानवीय दंड का ऐतिहासिक अवलोकन, 2018
29 भंडारी बनाम भारत सरकार [2025] EWHC 449 (एडमिन), पैरा. 117 में डॉ. एलन मिशेल की विशेषज्ञ राय।
30 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, और 2022 के लिए राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दर्ज मामले।
31 NHRC, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22; वार्षिक रिपोर्ट 2019-20; वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014; वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013
32 उदाहरण के लिए NHRC के आंकड़ों में यातना के मामलों के लिए एक श्रेणी की कमी देखें: NHRC, मानवाधिकार केस सांख्यिकी – दिसंबर 2024; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हिरासत में मौत/बलात्कार पर दिशानिर्देश, दिसंबर 1993
33 नित्या रामकृष्णन, हिरासत में: दक्षिण एशिया में कानून, दंड से मुक्ति और कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, मई 2013, पृष्ठ 3-4
34 कॉमन कॉज़ और लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2019: पुलिस पर्याप्तता और कार्यकारी परिस्थितियाँ, 2019, पृष्ठ 131
35 राजा बग्गा, पुलिस हिरासत में 60% से ज़्यादा मौतें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर होती हैं, 26 अक्टूबर 2020। यह भी देखें नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, इंडिया: टॉर्चर पर सालाना रिपोर्ट 2019, 26 जून 2020, पृ. 11
36 द इंडियन एक्सप्रेस, अधिकतम पुलिस हिरासत अभी भी 15 दिन है, इसे दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है: अमित शाह, 2 जुलाई 2024
37 नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, इंडिया: टॉर्चर पर सालाना रिपोर्ट 2020, 18 मार्च 2021, पृ. 17, 66
38 द न्यूज मिनट, टीएन पुलिस के 'फिसलन भरे' शौचालय: डेटा से पता चलता है कि हिरासत में 300 से अधिक संदिग्धों के अंग टूट गए, 20 मई 2025
39 द न्यूज मिनट, टीएन पुलिस के 'फिसलन भरे' शौचालय: डेटा से पता चलता है कि हिरासत में 300 से अधिक संदिग्धों के अंग टूट गए, 20 मई 2025

जुलाई 2024 में, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तेलंगाना के हैदराबाद में शादनगर पुलिस स्टेशन में एक कथित चोरी के मामले में तलब की गई दलित महिला सुनिता को कथित रूप से स्वीकारोक्ति के लिए यातना दी गई। सुनिता ने "आरोप लगाया कि उसके पैरों पर चमड़े की बेल्टों से बुरी तरह पीटा गया, पुलिसकर्मियों ने उसके हाथों पर पैर रखा, उसकी पसलियों पर ठोकर मारी और उन्होंने उस पर मोम भी डालने की कोशिश की", और उसे तब ही छोड़ा गया जब वह लगभग बेहोश हो गई थी।[40] सितंबर 2024 में एक अलग मामले में, हत्या के संदेह में हिरासत में लिए गए दो व्यक्तियों को कथित रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा लोहे की पाइप और लाठी (भीड़ नियंत्रण के लिए आमतौर पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल होने वाली बांस की छड़ें) से पीटा गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों "को हत्या की स्वीकारोक्ति करने के लिए पीटा गया।"[41] तमिलनाडु राज्य के एक मानवाधिकार समूह ने कहा कि दोनों पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में इलाज की आवश्यकता पड़ी, जिसमें से एक के शरीर पर "ऐसी चोटें थीं जो चरम पुलिस यातना का संकेत देती थीं।"[42]

केस स्टडी: हिरासत में स्वीकारोक्ति के लिए की गई प्रताड़ना के कारण मृत्यु

तामिर जिफ्री

31 जुलाई 2023 को, मलप्पुरम (केरल) निवासी 30 वर्षीय तामिर जिफ्री को केरल पुलिस के जिला मादक द्रव्य निरोधक विशेष कार्रवाई बल ने कथित तौर पर नशीले पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया।[43] उसे अन्य युवकों के साथ तनुस पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कथित तौर पर तामिर और कम से कम चार अन्य लोगों को नशीली दवाओं के सेवन को स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया।[44] गिरफ्तारी के अगले दिन, तामिर बेहोश हो गया और हिरासत में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि उसकी मौत नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन के कारण हुई, लेकिन उसके परिवार ने उसकी मौत के कारण पर संदेह व्यक्त किया।

एक फोरेंसिक सर्जन द्वारा किए गए शव परीक्षण में तामीर के शरीर पर 21 घाव पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसे हिरासत में यातना दी गई होगी।[45] पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, ये चोटें «हथकड़ी के बल प्रयोग» और «बिना धार वाला और बेलनाकार हथियार से जबरदस्ती की गई पिटाई» के कारण आई थीं।[46] रिपोर्ट में तामीर की मौत का कारण कई बार बलपूर्वक की गई चोटों, नशीली दवाओं के सेवन और अंतर्निहित कोरोनरी धमनी रोग का संयुक्त प्रभाव बताया गया है। तामीर की हिरासत में यातना और मौत ने जन आक्रोश को जन्म दिया।[47]

मामला केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दिया गया, जिसने मई 2024 में तामीर की मौत के सिलसिले में चार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। जुलाई 2024 में, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने पुष्टि की कि तामीर की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत में दी गई यातना के कारण हुई थी।[48]

पुलिस हिरासत में यातना का इस्तेमाल अपराध स्वीकार करवाने के अलावा लोगों को डराने या दंडित करने के लिए भी किया जाता है।[49] उदाहरण के लिए, सितंबर 2024 में दो महिलाओं ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया। नवंबर 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कथित यातना के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया।[50] कुछ मामलों में पुलिस खुलेआम हिरासत में हिंसा का इस्तेमाल न्यायेतर सजा के तौर पर करती है। उदाहरण के लिए, मई 2024 में एक प्रमुख मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठन पीपुल्स वॉच ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने

40 न्यूज नाइन, हैदराबाद: शादनगर डीआई, हिरासत में दलित महिला को प्रताड़ित करने के लिए पांच कांस्टेबल निलंबित, 5 अगस्त 2024; द टाइम्स ऑफ इंडिया, पुलिस थाने में चोरी के मामले में दलित महिला को निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया गया, 5 अगस्त 2024

41 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सीबी-सीआईडी ने कांचीपुरम में पूर्व पुलिसकर्मी की हत्या की जांच अपने हाथ में ली, 8 नवंबर 2024

42 द न्यूज मिनट, कांचीपुरम में पुलिस पर दो हत्या के संदिग्धों को प्रताड़ित करने का आरोप, एसएचआरसी ने जांच शुरू की, 30 सितंबर 2024

43 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामिर जिफ्री की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत में यातना के कारण हुई, 9 जुलाई 2024; मेट्रो

44 मेट्रो वार्ता, तनूर हिरासत में मौत का मामला: सीबीआई ने केरल के चार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, 4 मई 2024

45 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामीर जिफ्री की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत में यातना के कारण हुई, 9 जुलाई 2024

46 ओनमनोरमा, तनूर हिरासत में मौत: पिनाराई ने कहा कि केरल पुलिस भारत में सर्वश्रेष्ठ है, 10 अगस्त 2023

47 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामीर जिफ्री की मौत केरल पुलिस द्वारा हिरासत में यातना के कारण हुई, 9 जुलाई 2024

48 द न्यूज मिनट, एम्स ने पुष्टि की कि तामीर जिफरी की मृत्यु केरल पुलिस द्वारा हिरासत में यातना के कारण हुई, 9 जुलाई 2024

49 अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ), विरोध प्रदर्शन के लिए दंडित: कोविड-19 के समय में मानवाधिकार रक्षकों के विरुद्ध उल्लंघन, नवंबर 2002

50 द इकोनॉमिक टाइम्स, आरजी कर विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यातना मामले की विशेष जांच के आदेश दिए, हाईकोर्ट के समक्ष साप्ताहिक रिपोर्ट, 25 नवंबर 2024; एनडीटीवी, शीर्ष न्यायालय ने आरजी कर प्रदर्शनकारियों के कथित उत्पीड़न की विशेष टीम जांच के आदेश दिए, 25 नवंबर 2024

अपराध पर 'रोक' लगाने के प्रयास में हत्या के चार संदिग्धों के हाथ तोड़ दिए थे। पुलिस का दावा था कि इन व्यक्तियों को चोटें उस समय लगीं जब पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वे सड़क के बीच की मेडियन से टकरा गए। एनजीओ ने इस प्रथा की निंदा की और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के दुर्व्यवहार को «रोकथाम के रूप में सामान्य बना दिया गया है"।[51]

हरियाणा में 475 कैदियों के साक्षात्कारों पर आधारित कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) की 2019 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि लगभग आधे (227) ने पुलिस रिमांड के दौरान अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार या यातना का अनुभव किया। इसमें यौन यातना, बिजली का झटका, बलात्कार की धमकियाँ, लाठियों से पिटाई, उल्टा लटकाना, पानी में डुबोना और पैरों के तलवों पर मारना जैसे तरीके शामिल थे, जिनसे बाद में यातना के आरोपों को साबित करने के लिए बहुत कम निशान दिखाई देते हैं।[52]

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत में पुलिस और न्यायिक हिरासत में यातना के सभी मामलों को दर्ज करने वाले कोई आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे समस्या के पूरे पैमाने का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि, कई मामलों में, पुलिस हिरासत में यातना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, और ऐसी मौतें काफी संख्या में दर्ज की जाती हैं। हिरासत में मौतों की खतरनाक दरें हिरासत में यातना की गंभीरता और व्यापक प्रकृति को दर्शाती हैं।[53] अप्रैल 2014 और दिसंबर 2024 के बीच, NHRC को पुलिस हिरासत में 1,538 मौतों की सूचना दी गई, 2021-2022 के बीच 175 मामले, 2022-2023 में 166 और 2023-2024 में 158 मामले दर्ज किए गए - 2014-2015 के बाद से सबसे अधिक संख्या को चिह्नित करते हुए, जब 133 मौतें दर्ज की गई थीं।[54] हालांकि आधिकारिक आंकड़े यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करते हैं कि कितनी मौतें प्रत्यक्ष पुलिस हिंसा या यातना के कारण हैं, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर (NCAT) की 2019 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि उसके द्वारा दर्ज की गई हिरासत में लगभग 76% मौतें यातना के कारण हुईं।[55]

इसके विपरीत, NCRB ने 2014 और 2022 के बीच पुलिस हिरासत में केवल 328 मौतें दर्ज कीं। हालाँकि आँकड़ों में सूचीबद्ध पुलिस हिरासत में मौतों के संभावित कारणों में «पुलिस द्वारा शारीरिक हमले के कारण पुलिस हिरासत के दौरान लगी चोटें» शामिल हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में दर्ज कारणों में «पुलिस हिरासत से पहले लगी चोटें", "भीड़ का हमला/दंगे", "अन्य अपराधियों द्वारा हमला", "आत्महत्या", "पुलिस हिरासत से भागते समय", "बीमारी» और «प्राकृतिक मौतें» शामिल हैं।[56] NCRB के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, इनमें से किसी भी मामले में किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया।[57] उपरोक्त आँकड़े संभवतः पुलिस हिरासत में मौतों की पूरी सीमा को कम करके आंकते हैं, क्योंकि पीड़ित और उनके परिवार अक्सर पुलिस प्रतिशोध के डर से रिपोर्ट करने से बचते हैं (नीचे 'शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध' अनुभाग देखें)।[58] NCAT ने हिरासत में मौतों के आधिकारिक आँकड़ों को संभवतः «घोर कम किया आँकड़ा» बताया है।[59]

51 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, तमिलनाडु: पुलिस ने कथित तौर पर अपराध पर «रोक» लगाने के लिए हत्या के आरोपियों के हाथ तोड़े, 17 मई 2024। राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित स्वतंत्र निकाय हैं, जो एनएचआरसी को भी नियंत्रित करता है। SHRC का कार्य NHRC के समान है, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर कार्य करते हैं।

52 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI), हरियाणा की जेलों के अंदर, 2019, पृष्ठ 94-105 पर

53 OHCHR, संभावित रूप से गैरकानूनी मौत की जांच पर मिनेसोटा प्रोटोकॉल, (2016) एचआर/पीयूबी/17/4, पैरा 17.

54 ये आंकड़े NHRC द्वारा प्रत्येक अप्रैल-मार्च रिपोर्टिंग वर्ष के लिए «हिरासत में मौत (पुलिस) (इंक. कोड 807)" वर्गीकरण के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या पर आधारित हैं, जैसा कि निम्नलिखित स्रोतों में दर्ज किया गया है: वार्षिक रिपोर्ट 2021-22; वार्षिक रिपोर्ट 2019-20; वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014; अप्रैल 2022 से दिसंबर 2024 तक के मासिक आँकड़े।

55 CNN, भारतीय पुलिस न्याय पाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल एक शॉर्टकट के रूप में करती है। सबसे गरीब लोग ही इसके निशान झेलते हैं, 3 दिसंबर 2020। यह भी देखें: राष्ट्रीय अत्याचार विरोधी अभियान, भारत: अत्याचार पर वार्षिक रिपोर्ट 2019, 26 जून 2020, पृष्ठ 19

56 NCRB के अनुसार, यह आँकड़ा 2014, 2015 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 की भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्टों की तालिका ‹हिरासत में मौतों के कारण' से लिया गया है (ध्यान दें कि मई 2025 तक, 2023 या 2024 के लिए भारत में अपराध की कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट नहीं है)

57 NCRB, वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले (ध्यान दें कि NCRB के पास वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पुलिस कर्मियों की दोषसिद्धि पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़े नहीं हैं)

58 लाइवलॉ, हिरासत में यातना और मौतें: भारतीय पुलिस का स्याह पक्ष, 17 जुलाई 2020। कॉमन कॉज और विकासशील समाजों के अध्ययन केंद्र, भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2019, 2019, पृष्ठ 14-15. पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने और/या पुलिस हिंसा के बारे में शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें धमकाने पर पीड़ितों को दंडित करने के सामान्य पैटर्न के उदाहरणों के लिए, देखें बांग्लार मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM), मासिक रिपोर्ट सितंबर 2024, पृष्ठ 3; MASUM मासूम, मासिक रिपोर्ट जून 2024, पृष्ठ 3-4; पीपुल्स वॉच (PW), थूथुकुडी में ऑटो चालक हबीब के खिलाफ क्रूर अत्याचार, 24 फ़रवरी 2024। विश्व यातना विरोधी संगठन (OMCT), भारत: यातना पीड़ित के परिवार को सुरक्षा कानूनों के तहत दंडित और चुप करा दिया जाता है, 15 नवंबर 2023

59 CNN, भारतीय पुलिस न्याय पाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल एक शॉर्टकट के रूप में करती है। सबसे गरीब लोग ही इसके ज़ख्म सहते हैं, 3 दिसंबर 2020

केस स्टडी: हिरासत में यातना के परिणामस्वरूप मृत्यु

विग्नेश

18 अप्रैल 2022 को, एक बीसियों की उम्र के पुरुष विग्नेश को चेन्नई पुलिस ने देर रात वाहन जाँच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सुरेश नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ उसे हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर गंभीर शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।। रिपोर्टों के अनुसार, पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे डंडों और अन्य वस्तुओं से पीटा। गंभीर चोटों के बावजूद, उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई और 19 अप्रैल 2022 को हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस ने उसकी मौत का कारण दौरा पड़ना बताया। हालाँकि, रिपोर्टों में कहा गया है कि उसके शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों से पता चलता है कि उसकी मौत हिरासत में यातना के कारण हुई। उसकी मौत के बाद, पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार अत्यंत जल्दी करके और उसके परिवार पर चुप रहने का दबाव बनाकर घटना को छिपाने की कोशिश की।[60]

मोहम्मद आदिल

24 मई 2024 को, कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्नगिरी निवासी 33 वर्षीय बढ़ई मोहम्मद आदिल को जुए के एक मामले में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, पूछताछ के दो मिनट के भीतर ही आदिल बेहोश हो गया। अधिकारियों को दौरा पड़ने का संदेह हुआ, उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया और उसे एक स्थानीय अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।[61] हालाँकि, आदिल के परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी मौत पुलिस द्वारा हिरासत में दी गई यातना का परिणाम थी।[62] नागरिक स्वतंत्रता समूह पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक द्वारा प्रकाशित एक तथ्य-खोजी रिपोर्ट में आदिल की पत्नी ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले उसे कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। उन्होंने आगे बताया कि "कई समुदाय के सदस्यों और परिवार के सदस्यों ने आदिल के शरीर पर चोटों के निशान देखे थे।"[63] आदिल की मौत की खबर सुनकर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया।[64] 25 मई 2024 को, आपराधिक जाँच विभाग, बेंगलुरु ने आदिल की हिरासत में हुई मौत की जाँच अपने हाथ में ले ली।[65] 20 जनवरी 2025 तक, जाँच पूरी नहीं हुई थी, और न ही आदिल की पत्नी - हीना बानो - को आदिल के परिवार द्वारा कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद राज्य से कोई मुआवज़ा मिला था।[66]

COVID-19 महामारी के दौरान, पुलिस द्वारा महामारी संबंधी लॉकडाउन प्रतिबंधों को लागू करने के दौरान हिरासत में मौतों के कई मामले सामने आए।[67] मार्च 2020 में लॉकडाउन के पहले सप्ताह में, पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टें आईं, जिनमें मारपीट और हत्याएं शामिल थीं।[68]

60 हिरासत में यातना के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई - तमिलनाडु, श्री विग्नेश की हिरासत में मौत, जी-5 स्टेशन, चेन्नई, 4 मई 2022; पीपुल्स वॉच, चेन्नई में पुलिस हिरासत में मौत - विग्नेश, 24 फ़रवरी 2024

61 द न्यूज़ मिनट, चन्नागिरी में हिरासत में मौत: हिंसा भड़कने के बाद सीआईडी ने जाँच अपने हाथ में ली, 27 मई 2024; पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ कर्नाटक, चन्नागिरी में हिरासत में मौत - एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ 7-8।

62 द न्यूज़ मिनट, चन्नागिरी में हिरासत में मौत: हिंसा भड़कने के बाद सीआईडी ने जाँच अपने हाथ में ली, 27 मई 2024

63 PUCL, चन्नगिरी में हिरासत में मौत - एक तथ्य खोज रिपोर्ट, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ 2

64 PUCL, चन्नगिरी में हिरासत में मौत - एक तथ्य खोज रिपोर्ट, 30 अगस्त 2024, पृष्ठ 2

65 अनुच्छेद 14, कर्नाटक पुलिस हिरासत में मुस्लिम बढ़ई की मौत के लिए जवाबदेही का अभाव स्थानिक राष्ट्रीय विफलताओं की ओर इशारा करता है, 20 जनवरी 2025; द न्यूज़ मिनट, 'चन्नगिरी हिरासत में मौत: हिंसा भड़कने के बाद सीआईडी ने जांच संभाली›, 27 मई 2024

66 अनुच्छेद 14, कर्नाटक पुलिस हिरासत में मुस्लिम बढ़ई की मौत के लिए जवाबदेही का अभाव स्थानिक राष्ट्रीय विफलताओं की ओर इशारा करता है, 20 जनवरी 2025

67 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के अंत तक, NHRC ने पुलिस हिरासत में मौत के 114 मामले और न्यायिक हिरासत में मौत के 1586 मामले दर्ज किए। NHRC, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, पृष्ठ 249. अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक यह संख्या क्रमशः 175 और 2367 मामलों तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। NHRC, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, पृष्ठ 22

68 यातना, पुलिस बर्बरता और अनुचित मौतों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, भारत के COVID-19 लॉकडाउन को प्रभावित कर रहा है, अप्रैल 2020; यह भी देखें: डॉयचे वेले, भारतीय पुलिस लॉकडाउन लागू करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, 28 मार्च 2020

केस स्टडीज: कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस द्वारा अत्याचार

लाल स्वामी, पी जयराज, जे बेनिक्स, हबीब मोहम्मद और मुरुगनंथम

मार्च 2020 में लॉकडाउन के पहले दिन, पश्चिम बंगाल में लाल स्वामी नामक एक व्यक्ति की पुलिस ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी, जब वह दूध खरीदने के लिए बाहर गया था। उसकी पत्नी का कहना है कि वह उस भीड़ का हिस्सा था जिस पर पुलिस ने लाठियाँ चलाई थीं।[69]

एक और व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया मामला पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स का है, जिन्हें तमिलनाडु में कोविड-19 कर्फ्यू कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में रहते हुए, कथित तौर पर उन्हें यातना देकर मार डाला गया था। पुलिस ने आरोपों से इनकार किया और ये दावा किया कि लगी चोटें आंशिक रूप से पीड़ितों के «सड़क पर लोटने» के कारण थीं।[70]

एक अलग मामले में, गैर सरकारी संगठनों ने बताया कि 33 वर्षीय व्यक्ति, हबीब मोहम्मद को पुलिस ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी एक किडनी खराब हो गई, जिसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी।[71]

खबरों के अनुसार पेकुलम गांव के मुरुगनन्थम नामक एक अन्य व्यक्ति को जून 2020 में स्थानीय पुलिस ने यातनाएं देकर मार दिया।[72]

न्यायिक हिरासत में यातना

> **[इस देश में हिरासत में हिंसा और यातना इतनी व्यापक है कि इसे सामान्य जीवनशैली में समाहित देखा जा सकता है।]**
>
> – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2019[73]

भारत में यातना केवल पुलिस हिरासत तक ही सीमित नहीं है; इसे न्यायिक हिरासत में भी सामान्य बना दिया गया है, जहाँ बंदियों को पुलिस रिमांड की प्रारंभिक अवधि के बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है।[74] जहाँ सभी बंदियों को यातना और अन्य दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, वहीं विचाराधीन कैदी - जो मुकदमे की प्रतीक्षा या सुनवाई के दौरान हिरासत में हैं[75] - लंबी हिरासत, व्यवस्थागत उपेक्षा और भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं।[76] कई विचाराधीन कैदी कई कारणों से वर्षों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, जिनमें «न्यायालय प्रणाली में लंबित मुकदमों की संख्या, कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी और गरीब व वंचित लोगों के लिए जमानत का खर्च वहन करने में कठिनाई शामिल

69 इंडिया टुडे, बंगाल के व्यक्ति के परिवार का कहना है कि उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई, पुलिस का कहना है कि उसे दिल की बीमारी थी, 26 मार्च 2020; यातना, पुलिस बर्बरता और अनुचित मौतों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान, भारत के COVID-19 लॉकडाउन को प्रभावित कर रहा है, 1 अप्रैल 2020

70 टाइम्स ऑफ इंडिया, थूथुकुडी हिरासत में मौतें: आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, 30 जून 2020

71 टाइम्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु हिरासत में मौतें: पुलिस यातना के और मामले सामने आए, 27 जून 2020

72 टाइम्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु में हिरासत में मौतें: पुलिस यातना के और मामले सामने आए, 27 जून 2020

73 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, पृष्ठ 34

74 लॉ टाइम्स जर्नल, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में क्या अंतर है?, 6 दिसंबर 2020

75 विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है जिसे जाँच या मुकदमे के लंबित रहने तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। देखें NHRC, कैदियों के अधिकार, 2021 साथ ही गृह मंत्रालय, मॉडल जेल मैनुअल 2016, 2016, पृष्ठ 21 देखें। व्यक्तियों को केवल 15 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा जा सकता है, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच के लिए 60 दिनों या 90 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया जाना चाहिए। देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 187

76 चिनार गर्ग और सुखमणि सिंह, सलाखों के पीछे से आवाज़ें: भारतीय न्याय प्रणाली में विचाराधीन कैदियों की कहानी, 2023; दीपक, भारत में हिरासत में यातना और विचाराधीन कैदियों के अधिकार: एक सुधारात्मक दृष्टिकोण, 2023; AI, विचाराधीन न्याय: भारत में परीक्षण-पूर्व हिरासत का एक अध्ययन (विचाराधीन न्याय), 2017 पृष्ठ 6

है» ।[77] इससे जेलों में भीड़भाड़ बढ़ जाती है और बंदियों को यातना और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है।[78] CHRI द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2017 में भारत की 149 जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की दर 100% से अधिक थी, जबकि 14 जेलों में यह दर 300% से अधिक थी।[79]

नागरिक समाज पहल, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक, भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या कुल कैदियों का लगभग 76% थी।[80] यह आबादी धार्मिक अल्पसंख्यकों और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समूहों से संबंधित व्यक्तियों से असमान रूप से बनी है।[81] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आंकड़ों का उपयोग करके NCAT द्वारा किए गए एक विश्लेषण में पाया गया कि भारत में हिरासत में हुई मौतों के 70% से अधिक मामलों में, पीड़ित निम्न-आय और/या हाशिए पर रहे समूहों से थे।[82]

भारत की जेलों में यातनाएँ «स्थायी, संस्थागत और न्याय प्रशासन का केंद्र बनी हुई हैं» ।[83] कई दर्ज किए गए मामले न्यायिक हिरासत में बंदियों के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा की जाने वाली यातनाओं के एक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिसमें अक्सर क्रूर पिटाई शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है।[84] जेल अधिकारी कथित तौर पर यातना के कारण होने वाली ऐसी हिरासत में मौतों को चिकित्सकीय स्थितियों या आत्महत्या के कारण बताकर छिपाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि, कई मामलों में, ये स्पष्टीकरण इस सबूत से कमज़ोर पड़ जाते हैं कि पीड़ितों का हिरासत में रहने के समय स्वास्थ्य अच्छा था।[85] न्यायिक हिरासत में यातना की व्यापकता दर्ज की गई मौतों की चिंताजनक संख्या से स्पष्ट होती है। अप्रैल 2014 और दिसंबर 2024 के बीच, NHRC ने न्यायिक हिरासत में 20,158 मौतों का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से वार्षिक आंकड़े अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच 2,367, अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच 2,354 और अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच 2,183 पर पहुँच गए।[86] हिरासत में मौतों की उच्च दर और जेल स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत विफलता[87] यह दर्शाती है कि दुर्व्यवहार, चिकित्सा उपेक्षा और यातना इन मौतों का कारण निर्धारित करने में प्रमुख कारक हैं।[88]

न्यायिक हिरासत में खराब हिरासत की स्थिति, चिकित्सा देखभाल की कमी और दुर्व्यवहार के कारण होने वाली मौतों के कई मामले उन सामान्य संदर्भों को दर्शाते हैं जिनमें हिरासत में यातना होती है।

77 चिनार गर्ग और सुखमणि सिंह, सलाखों के पीछे से आवाज़ें: भारतीय न्याय प्रणाली में विचाराधीन कैदियों की कहानी, 29 मई 2023, पृष्ठ 3

78 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जेलों में भीड़भाड़, 23 जनवरी 2024। AI, न्याय विचाराधीन, 2017 भी देखें; चिनार गर्ग और सुखमणि सिंह, सलाखों के पीछे से आवाज़ें: भारतीय न्याय प्रणाली में विचाराधीन कैदियों की कहानी, 29 मई 2023; काउंटरकरेंट्स, भारतीय जेल प्रणाली: बढ़ती भीड़भाड़ और न्याय की प्रतीक्षा, 22 नवंबर 2024; डिग्निटी - यातना के खिलाफ डेनिश संस्थान, जेल में भीड़भाड़: तथ्य पत्रक, अक्टूबर 2022; दीपक, भारत में हिरासत में यातना और विचाराधीन कैदियों के अधिकार: एक सुधारात्मक दृष्टिकोण, 2023

79 राजा बग्गा, भारतीय जेलों में ठसाठस भरी कोठरियाँ, [n.d.]

80 भारत न्याय रिपोर्ट, पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता की क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग, अप्रैल 2025, पृष्ठ 7; भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुसंधान एवं नियोजन केंद्र, भारत में जेलों पर रिपोर्ट: जेल नियमावली का मानचित्रण और सुधार एवं भीड़भाड़ कम करने के उपाय, अक्टूबर 2024, पृष्ठ 132

81 देवांगना कलिता, धर्म, जाति और हाशिये पर: भारतीय आपराधिक न्याय और जेल प्रणाली पर विचार, 19 सितंबर 2023; श्रीहरि पलियाथ, भारत की जेल आबादी प्रणालीगत हाशियाकरण को दर्शाती है, 26 अक्टूबर 2020

82 देवांगना कलिता, धर्म, जाति और हाशिये पर: भारतीय आपराधिक न्याय और जेल प्रणाली पर विचार, 19 सितंबर 2023; दि हिन्दू, भारत में हिरासत में होने वाली मौतों में 71% गरीब हैं, 4 दिसंबर 2021

83 एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, भारत: द स्टेट ऑफ़ रिफ़्लमेंट, 2018, पृ. 329

84 HRW, गेटिंग अवे विद टॉर्चर इन इंडिया, 20 अगस्त 2017

85 HRW, गेटिंग अवे विद टॉर्चर इन इंडिया, 20 अगस्त 2017

86 यह आँकड़ा NHRC की 2014 और 2022 के बीच की वार्षिक रिपोर्टों से हिरासत में हुई मौतों (न्यायिक) कॉलम सेल के योग से लिया गया है, इसके अलावा अप्रैल 2022 और दिसंबर 2024 के बीच के मासिक आँकड़े भी शामिल हैं। NHRC वार्षिक रिपोर्ट 2021-22; वार्षिक रिपोर्ट 2019-20; वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 देखें।

87 देखें अविनाश कृष्ण गोस्वामी और रितु गौतम, 'उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में कैदियों की चिकित्सा स्वास्थ्य स्थिति और सुविधाओं में विसंगति›, 2022. मैत्रेयी मिश्रा, भारतीय जेल में देखभाल और देखभाल की नैतिकता के बीच पतली नीली रेखा, 4 फ़रवरी 2025

88 UN OHCHR, मिनेसोटा प्रोटोकॉल, 2016

केस स्टडी: न्यायिक हिरासत में यातना

शरवन सोनी

19 फरवरी 2024 को, राजस्थान के अजमेर सेंट्रल जेल में जेल कर्मचारियों के साथ झगड़े के दौरान 45 वर्षीय शरवन सोनी की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि आठ से दस जेल अधिकारियों ने लोहे की छड़ों और डंडों से उसकी पिटाई की थी।। उसके भाई के अनुसार, शरवन के शरीर पर पिटाई के निशान थे, फिर भी शरवन के बेटे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके भाई ने यह भी बताया कि शरवन को अपनी एचआईवी पॉजिटिव स्थिति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा और हिरासत में एंटीरेट्रोवाइरल दवा प्राप्त करने के लिए उसे अक्सर रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता था। शरवन के बेटे ने बताया कि, अपनी मृत्यु से पहले फ़ोन पर शरवन ने कहा था कि उसे «जेल प्रशासन द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था"।[89]

हिरासत में मौत के मामले में, जेल अधिकारियों को कानूनी रूप से 24 घंटे के भीतर मामले की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देना अनिवार्य था, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जाँच या मजिस्ट्रेट जाँच के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई शुरू हो जाती। हालाँकि, मीडिया कवरेज के कारण, 20 फ़रवरी 2024 को NHRC ने कार्रवाई की और जेल निदेशालय को एक नोटिस भेजकर सोनी की मौत की परिस्थितियों पर छह हफ़्तों के भीतर रिपोर्ट माँगी। आज तक, NHRC को कथित तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, और इस मामले की आखिरी सुनवाई मई 2024 में हुई थी। यह मामला दर्शाता है कि हिरासत में हुई मौतों की जाँच के लिए मौजूदा तंत्र कितने सीमित हैं और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल हैं[90]

सितंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुने गए एक अलग मामले में, मनीष कुमार झा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में जेल अधिकारियों ने उससे जबरन वसूली करने की कोशिश करते हुए उसे प्रताड़ित किया।[91] दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल अधीक्षक को आरोपों की प्रारंभिक जाँच करने और «अगर कुछ भी लापरवाही पाई जाती है» तो मनीष कुमार झा को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।[92] हालाँकि, न्यायालय ने कथित यातना के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का कोई ज़िक्र नहीं किया।[93]

केस स्टडी: न्यायिक हिरासत में यातना

इब्राहिम

फ़रवरी 2022 को, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में पुलिस ने एक टेंपो चालक इब्राहिम को 25 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में 7 हिरासत में लिया। पुलिस ने कथित तौर पर उसकी रिहाई के लिए 10,000 रुपये (लगभग 120 अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत माँगी और उसकी पत्नी शाहिबा बानो से कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे मार दिया जाएगा। इब्राहिम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और पाँच दिन बाद ही शाहिबा को एक फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि इब्राहिम ने जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। हालाँकि, जब इब्राहिम का शव दफ़नाने के लिए वापस लाया गया, तो शाहिबा ने बताया कि उस पर "गंभीर पिटाई के साफ़ निशान [94]"थे, जिसमें उसकी कमर, पैर और गर्दन पर चोट के निशान थे।

89 NHRC, केस संख्या 228/20/1/2024-जेसीडी, कार्रवाई संख्या 3, 14 मई 2024

90 NHRC, केस संख्या 228/20/1/2024-जेसीडी, कार्रवाई संख्या 3, 14 मई 2024; यह भी देखें टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई का कहना है-"भाई को जेल कर्मचारियों को प्रताड़ित किया क्योंकि वह एचआईवी पॉजिटिव था", 22 फ़रवरी 2024

91 मनीष कुमार झा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2921/2024

92 मनीष कुमार झा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2921/2024, पैरा 9

93 मनीष कुमार झा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 2921/2024

94 न्याय के लिए आवाज, कुछ रुपयों के लिए: इब्राहिम की दुखद मौत और हिरासत में यातना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई, 14 फरवरी 2025; Unbias The News!, भारत के उत्तर प्रदेश में हिरासत में पुरुषों की मौत के बीच महिलाएँ संघर्ष करती हैं, 14 जून 2023

हिरासत में यौन और लिंग-आधारित हिंसा

भारतीय अधिकारियों द्वारा हिरासत में की जाने वाली हिंसा के सबसे आम रूपों में से एक यौन शोषण, विशेष रूप से बलात्कार, है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, बलात्कार को लिंग-आधारित हिंसा का एक रूप माना जाता है जो यातना के समान हो सकता है।[95]

2014 और 2022 के बीच, हिरासत में बलात्कार के कम से कम 557 मामले आधिकारिक तौर पर NCRB को रिपोर्ट किए गए।[96] हालाँकि, यह संख्या संभवतः समस्या के पूरे पैमाने को नहीं दर्शाती है। यौन हिंसा से जुड़े सामाजिक कलंक को देखते हुए, अन्य मुद्दों के अलावा सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने या प्रतिशोध का सामना करने के डर से पीड़ितों का आगे नहीं आना आम बात है।[97] भारत में यौन हिंसा की कम रिपोर्टिंग विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब इस तरह के उल्लंघन पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं,[98] रिपोर्टों में अधिकारियों द्वारा बलात्कार के मामलों को दर्ज करने से इनकार करने का उल्लेख है।[99]

हिरासत में बलात्कार के दर्ज मामले कोई छिटपुट घटनाएँ नहीं हैं; बल्कि, देश के विभिन्न हिस्सों में हिरासत में बलात्कार की लंबे समय से चली आ रही व्यापकता और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता[100] यह संकेत करते हैं कि ये मामले एक व्यापक प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाते हैं।[101]

हालाँकि यह पूरे देश में होता रहता है, लेकिन हिरासत में बलात्कार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 16% आबादी रहती है, लेकिन पिछले एक दशक में हिरासत में बलात्कार की लगभग 65% रिपोर्टें यहीं से दर्ज हुई हैं।[102]

2020 में, NCAT ने हिरासत में बलात्कार के नौ मामले दर्ज किए, जिनमें रेलवे स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा, आपराधिक जाँच के दौरान, और यहाँ तक कि पीड़ितों द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले भी शामिल हैं।[103]

जुलाई 2020 में, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, कविता नाम की एक महिला ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ में हिरासत में अपनी 17 वर्षीय बेटी और 20 वर्षीय भतीजी के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया।[104] उन्हें पुलिस अधिकारियों की हत्या में कथित संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया था। कविता के अनुसार, उनकी बेटी को 10 से 12 पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार और उसके शरीर में कांच की बोतलें डालने सहित कई यातनाएँ सहन करनी पड़ीं, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसका इलाज नहीं किया गया। शुरुआती शिकायतों को खारिज किए जाने के बावजूद, जन आक्रोश के कारण हरियाणा पुलिस ने जाँच शुरू की। अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया और जनवरी 2021 तक दोनों महिलाएं न्यायिक हिरासत में रहीं।[105] आज तक, हमारी जानकारी के अनुसार, कथित अपराधियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

95 UNHRC महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, उसके कारण और परिणाम पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, 19 अप्रैल 2021, ए/एचआरसी/47/26; यातना विरोधी समिति (कैट), सामान्य टिप्पणी संख्या 2, 24 जनवरी 2008, कैट/सी/जीसी/2; HRCttee, सामान्य टिप्पणी संख्या 28, 29 मार्च 2000, सीसीपीआर/सी/21/संशोधन 1/अतिरिक्त/10

96 NCRB के अनुसार, यह आँकड़ा वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्टों से 'महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की घटना (I), पीड़ित (V) और दर (R)' या 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध (अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)' या 'बलात्कार के तहत पंजीकृत मामले' (वर्ष के आधार पर) तालिकाओं से प्राप्त किया गया है

97 अमेरिकी विदेश विभाग, 2023 के लिए मानवाधिकार प्रथाओं पर देश रिपोर्ट (देश रिपोर्ट 2023), 2023, पृ. 8

98 अमेरिकी विदेश विभाग, 2023 के लिए मानवाधिकार प्रथाओं पर देश रिपोर्ट (देश रिपोर्ट 2023), 2023, पृ. 8

99 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, पैरा 33; US डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट, कंट्री रिपोर्ट्स 2023

100 NCRB, 'महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की घटनाएं (I), पीड़ित (V) और दर (R)' या 'महिलाओं के खिलाफ अपराध (अपराध शीर्ष-वार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार)' या 'बलात्कार के तहत पंजीकृत मामले' तालिकाएं (वर्ष के आधार पर) देखें, जो भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्ट 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के से हैं। NHRC वार्षिक रिपोर्ट 2021-22; वार्षिक रिपोर्ट 2019-20; वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 देखें। हिरासत में यौन हिंसा के हाल के मामलों के इस खंड में दिए गए साक्ष्य के अलावा, REDRESS शोध में हिरासत में बलात्कार, पुलिस अधिकारियों द्वारा सामूहिक बलात्कार, पुलिस हिरासत में नाबालिगों और युवाओं के यौन शोषण के कई पुराने उदाहरण भी मिले हैं, उदाहरण के लिए वर्ष 2015 और 2016 में

101 ऐसा ही एक प्रणालीगत मुद्दा पुलिस अधिकारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है। इस मुद्दे को भारतीय संसद में महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा उजागर किया गया था, जिसने दिसंबर 2017 में हिरासत में महिलाओं और न्याय तक पहुंच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में हिरासत में बलात्कार की व्यापकता पर टिप्पणी की गई थी, और उचित प्रशिक्षण और बेहतर निगरानी की मांग की गई थी। भारत की संसद देखें लोकसभा, महिला सशक्तिकरण समिति, हिरासत में महिलाएं और न्याय तक पहुंच (दसवीं रिपोर्ट, 2017)

102 NCRB के अनुसार, 2014-2022 के बीच हिरासत में बलात्कार के 375 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए

103 राष्ट्रीय यातना विरोधी अभियान, भारत: यातना पर वार्षिक रिपोर्ट 2020, 18 मार्च 2021, पृष्ठ 73-78

104 कविता बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य सीआरएम नं.एम-35684 ऑफ 2020 (ओएंडएम)

105 चाहत राणा, हरियाणा पुलिस पर हिरासत में बलात्कार का आरोप लगाने वाली नाबालिग को अभी भी राज्य की हिरासत में क्यों रखा गया है, 15 जनवरी 2021

पिछले कुछ वर्षों के मामले भी इसी तरह के रुझान दर्शाते हैं, जहाँ न्याय प्रणाली से जुड़ी महिलाओं को बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है, और अपराधी बेखौफ रहते हैं। उदाहरण के लिए, 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज एक मामले में, प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी के साथ थाना प्रभारी ने पुलिस हिरासत में बलात्कार किया, उसे प्रताड़ित किया और उसका यौन शोषण किया। प्रेम सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी ने उसकी बेटी के साथ कई बार बलात्कार किया «और उसके गुप्तांगों में बाहरी वस्तुएँ भी डालीं और डॉक्टर के साथ मिलीभगत कर के एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट पेश की"।[106]

ये घटनाएँ अक्सर प्रणालीगत और भेदभावपूर्ण हिंसा की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, खासकर हाशिए के समूहों के खिलाफ। जैसा कि रिपोर्ट के 'भेदभावपूर्ण उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में यातना' खंड में नीचे बताया गया है, दलितों जैसे हाशिए के समूहों को पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा असमान रूप से हिंसा का निशाना बनाया जाता है, जिसमें यातना और यौन हिंसा भी शामिल है। 2022 की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक 13 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार किया गया था, जब उसने पुलिस अधिकारी से चार पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने में मदद मांगी थी। इस घटना ने भारत में आक्रोश पैदा कर दिया और कई लोगों ने पुलिस पर इस यौन हिंसा की प्रणालीगत संस्कृति"[107]को जारी रखने में मदद करने का आरोप लगाया।

जून 2023 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को राजस्थान के बीकानेर जिले में दो पुलिस अधिकारियों सहित तीन लोगों द्वारा एक 21 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप प्राप्त हुए।[108]

केस स्टडी: यौन हिंसा सहित हिरासत में यातना

सूरज चंदोला और तनुजा चंदोला

11 अगस्त 2023 को, पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर नालागढ़ (सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश) में विवाहित जोड़े सूरज और तनुजा चंदोला के घर में घुसकर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और ऐसी चीज़ें ले गए जिनका किसी जाँच से कोई संबंध नहीं था। सूरज और तनुजा को एक निजी वाहन में नालागढ़ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि पुलिस अधिकारी शराब पी रहे थे और जोड़े की पिटाई कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान, सूरज और तनुजा को रोज़ पीटा गया और लगातार तीन रातों तक सोने नहीं दिया गया। सूरज को उसकी पत्नी के सामने निर्वस्त्र किया गया और उसके साथ «दुर्व्यवहार» किया गया। कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी ने सूरज के चेहरे पर पेशाब कर दिया। वही पुलिस अधिकारी कथित तौर पर शराब के नशे में तनुजा के कपड़े भी उतार दिए और «उसके गुप्तांगों को छुआ»। इस मामले में, पुलिस अधिकारियों ने अपने अपराधों को छिपाने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने की साजिश रचना और कुछ सीसीटीवी फुटेज मिटाना शामिल था।[109]

106 NHRC वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, पृष्ठ 165

107 CNN, 13 साल की एक लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। फिर एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया6 ,' मई 2022; यह भी देखें द ट्रिब्यून, ललितपुर सामूहिक बलात्कार: आरोपी एसएचओ को न्यायिक हिरासत में भेजा गया; पाली पुलिस स्टेशन में नए कर्मचारियों की तैनाती, 6 मई 2022

108 NHRC, बीकानेर जिले में एक दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या में दो पुलिसकर्मियों की कथित संलिप्तता पर राजस्थान सरकार को NHRC का नोटिस, 27 जून 2023; टाइम्स ऑफ इंडिया, दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में NHRC का सीएस और डीजीपी को नोटिस, 28 जून 2023

109 लखबीर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सीआरएमपी (एम) संख्या: 2987/2024, 3 जनवरी, 2025

केस स्टडी: पुलिस द्वारा तीन रिश्तेदारों का बलात्कार

देवा पारधी और परिवार

13 जुलाई 2024 को, 24 वर्षीय देवा पारधी शादी से पहले की हल्दी की रस्मों में शामिल थे, जब पुलिस अधिकारियों ने समारोह में बाधा डाली। मध्य प्रदेश के गुना जिले में अत्यधिक हाशिए पर रहने वाली पारधी जाति के सदस्य देवा को उनके चाचा गंगाराम पारधी के साथ हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पहले झागर पुलिस चौकी पर हिरासत में लिया गया और उसके तुरंत बाद लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित सुनसान म्याना पुलिस चौकी में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ, "देवा और गंगाराम दोनों को बाँधकर छत से लटका दिया गया, उनके चेहरे काले कपड़े से कसकर ढँक दिए गए और बेरहमी से पीटा गया।» पुलिस ने उनकी पिटाई जारी रखते हुए उनके चेहरे पर गर्म पानी फेंका। उनके गुदा में लोहे की छड़ें डाली गईं और कुछ तरल पदार्थ, जिसके पेट्रोल होने का संदेह था, भी डाला गया था। उसी दिन देवा की मृत्यु हो गई, और गंगाराम के हाथ-पैर और सिर गंभीर रूप से घायल हो गए।[110]

उसी दिन, जब परिवार उत्सव के दौरान पुलिस से भाग रहा था, देवा की एक रिश्तेदार के साथ कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी ने बलात्कार किया, जिसे वह जानती थी और कहती थी कि उसने पहले भी कई मौकों पर उसे परेशान किया था।[111]

जैसा कि रिपोर्ट के 'विशिष्ट क्षेत्रों में यातना' खंड में नीचे बताया गया है, भारत के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति है, और इस प्रकार वे व्यवस्थित रूप से तीव्र हिंसा से पीड़ित हैं, जिसमें हिरासत में और गैर-हिरासत दोनों स्थितियों में यौन हिंसा शामिल है।

न्यायेतर हत्याएँ: पुलिस मुठभेड़

न्यायेतर हत्याएँ भारतीय कानून प्रवर्तन और सुरक्षा बलों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाले दुर्व्यवहार का एक और स्वरूप हैं। हालाँकि सभी न्यायेतर हत्याओं में यातना शामिल नहीं होती, फिर भी संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी समिति ने बार-बार इन्हें UNCAT के गंभीर उल्लंघनों में वर्गीकृत किया है।[112] भारत में, ये घटनाएँ अक्सर उन परिस्थितियों में होती हैं जिन्हें सरकार अपराध-नियंत्रण अभियानों के रूप में दर्शाती है, और जो आमतौर पर पुलिस के साथ हिंसक मुठभेड़ों में घटित होती हैं।[113] ये 'मुठभेड़ें' संदिग्धों को बिना गिरफ्तारी, जाँच या मुकदमे के गोली मार देने के सन्दर्भ में कही जाती हैं। न्यायेतर हत्याएँ 'फ़र्ज़ी मुठभेड़ों' या बनावटी 'मुठभेड़ों' के रूप में भी होती हैं। इनका आशय किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने और न्यायेतर रूप से उसकी हत्या करने से है, जिसके बाद यह झूठा दावा किया जाता है कि पीड़ित की मृत्यु पुलिस के साथ कथित गोलीबारी शुरू करने के बाद हुई।[114]

हिरासत में यातना के प्रयोग की तरह, न्यायेतर हत्याओं का चलन भारत में व्यापक रूप से है। अप्रैल 2014 से दिसंबर 2024 तक, NHRC ने '[पुलिस] मुठभेड़ में हुई मौतों' की 1,575 शिकायतें दर्ज कीं।[115] मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक, NHRC ने 90 कथित न्यायेतर हत्याएं दर्ज कीं।[116] NCRBI के आंकड़े 2014 और 2022 के बीच कानून प्रवर्तन में अत्यधिक बल प्रयोग को उजागर करते हैं।[117] पुलिस मुठभेड़ों, आग्नेयास्त्रों और लाठियों के इस्तेमाल के कारण 387 मौतें[118] और 3,017 नागरिक घायल हुए।[119]

110 सुकन्या शांता, एक हत्या, मारपीट, अपंगता और बलात्कार: मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों पारधी समुदाय पर असाधारण अत्याचार, 11 सितंबर 2024

111 सुकन्या शांता, एक हत्या, मारपीट, अपंगता और बलात्कार: मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों पारधी समुदाय पर असाधारण अत्याचार, 11 सितंबर 2024

112 जना मार्टिनकोवा, द कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर अप्रोच टू एक्स्ट्राज़ुडिशियल किलिंग, 7 अगस्त 2018

113 मनोज जोशी, मणिपुर में 10 कुकी-ज़ो पुरुषों की मुठभेड़ में हत्या भाजपा सरकार की छवि खराब करती है, दिसंबर 2024

114 HRW, टूटी हुई व्यवस्था: शिथिलता, भारतीय पुलिस में दुर्व्यवहार और दंड से मुक्ति, 4 अगस्त 2009; जस्टिन रॉलेट, भारत में ‹फर्जी मुठभेड़' चौंकाने वाली बात क्यों हैं, 13 अप्रैल 2015; JKCCS, कथित ‹फर्जी मुठभेड़' में राजौरी के 3 युवकों का गायब होना और उनकी हत्या, कश्मीर में राज्य की हिंसा की गैर-जवाबदेह प्रकृति का जारी रहना: JKCCS और APDP 12 अगस्त 2020

115 यह आंकड़ा अप्रैल 2022 और दिसंबर 2024 के बीच के मासिक आंकड़ों के अलावा, 2014 और 2022 के बीच NHRC की वार्षिक रिपोर्टों से मुठभेड़ में हुई मौतों के कॉलम सेल के योग से लिया गया है। NHRC वार्षिक रिपोर्ट 2021-22; वार्षिक रिपोर्ट 2019-20; वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 देखें। पुलिस मुठभेड़ एक शब्द है जिसका प्रयोग पुलिस गोलीबारी के लिए किया जाता है। कई मामलों में पुलिस मुठभेड़ें फर्जी होती हैं। उदाहरण के लिए देखें बीबीसी, भारत में पुलिस हत्याएँ: अपराध पर नकेल कसने के पीछे की कहानी, 5 अक्टूबर 2017

116 HRW, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को भारत की समीक्षा हेतु प्रस्तुति, जून 2024; NHRC, मानवाधिकार मामलों के आँकड़े, 6 मई 2024 भी देखें।

117 यहाँ 2014 से 2022 की अवधि का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि एनसीआरबी के पास वर्तमान में 2022 के बाद के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं

118 NCRB, वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्टों से 'पुलिस अभियानों के दौरान मारे गए नागरिक' तालिका

119 NCRB, वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्टों से 'पुलिस अभियानों के दौरान मारे गए नागरिक' तालिका

पुलिस मुठभेड़ों में न्यायेतर हत्याओं को भी कानून प्रवर्तन में कई लोगों द्वारा अपराध नियंत्रण के एक स्वीकार्य उपाय के रूप में माना गया है। उदाहरण के लिए, 2019 के एक सर्वेक्षण में पता चला कि पाँच में से एक पुलिस कर्मी का मानना है कि «खतरनाक अपराधियों» को मारना कानूनी मुकदमों से बेहतर है।[120] न्यायेतर हत्याओं में शामिल पुलिस अधिकारियों को अक्सर महिमामंडित किया जाता है और सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता है,[121] जिनमें सबसे ज़्यादा न्यायेतर हत्याओं में शामिल अधिकारियों को 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' कहा जाता है।[122] ऐसे ही एक अधिकारी, मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रमुख दया नायक ने कथित तौर पर 87 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है।[123] 2018 में, पत्रकारों को एक लाइव मुठभेड़ देखने के लिए «आमंत्रित» भी किया गया था, जिसके दौरान पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर हथियारबंद और एक खंडहर इमारत में छिपे दो लोगों को मार डाला था।[124]

भारत के कुछ क्षेत्रों, खासकर उत्तर प्रदेश में, पुलिस मुठभेड़ें खास तौर पर प्रचलित हैं। 2017 से 2021 के बीच, राज्य में ऐसी 8,472 से ज़्यादा घटनाएँ दर्ज की गईं। इन मुठभेड़ों के दौरान, पुलिस ने कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल कम से कम 3,302 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 146 लोगों की मौत हो गई। ये कार्रवाइयाँ अपराध के खिलाफ एक अनौपचारिक कार्रवाई का हिस्सा थीं, जिसे 'ऑपरेशन लंगड़ा' कहा जाता है।[125] मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने प्रशासन के «कानून-व्यवस्था» एजेंडे के तहत पुलिस मुठभेड़ों की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी टिप्पणियों, जैसे «यदि आप कोई अपराध करते हैं, तो आप ठोक दिये जाएंगे ",[126] की व्यापक रूप से आलोचना की गई है।[127]

2019 में, चार संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदकों ने उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ हत्याओं की प्रथा की निंदा की, और «उच्च पदस्थ राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बयानों पर चिंता व्यक्त की, जो हत्याओं को उकसाने, उचित ठहराने या मंजूरी देने वाले प्रतीत होते हैं»।[128] नागरिक समाज संगठनों ने यह भी बताया कि उस वर्ष सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक आधिकारिक सरकारी पत्र भेजा गया था, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के रूप में हत्याओं और घायलों की संख्या सूचीबद्ध की गई थी।[129] 2021 की एक रिपोर्ट में, नागरिक समाज संगठनों ने उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ हत्याओं की जाँच प्रक्रियाओं की आलोचना की, जिसमें कथित न्यायेतर हत्याओं के 17 मामलों पर प्रकाश डाला गया। NHRC में शिकायत के बावजूद, किसी भी पुलिस अधिकारी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया।[130]

एक और राज्य जहाँ पुलिस मुठभेड़ में मौतें आम हैं, वह है असम।[131] रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 में, जब हिमंत बिस्वा सरमा मंत्री थे, मुठभेड़ में हत्याओं में वृद्धि हुई[132] और 2021 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें और वृद्धि हुई।[133] उस वर्ष, सरमा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो लोग हिरासत से भागते हैं, उनके पैरों में गोली मार दी जानी चाहिए।[134] 22 अक्टूबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 से असम में मुठभेड़ में हत्याओं में वृद्धि पर ध्यान दिया और «इस मुद्दे को 'बहुत गंभीर' बताया।"[135]

120 कॉमन कॉज़, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2019, पृष्ठ 131
121 द 420, मिलिए दलजीत सिंह चौधरी से, आईपीएस: ‹एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' जो अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, अगस्त 2024, पृष्ठ 4
122 हिंदुस्तान टाइम्स, मुंबई पुलिस के 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए | मुंबई समाचार - हिंदुस्तान टाइम्स, 12 जनवरी 2016
123 पत्रिका, 'बाबा सिद्दीकी मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कौन हैं? | ताज़ा खबर | पत्रिका न्यूज़', 13 अक्टूबर 2024.
124 यूथ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 27
125 'लंगड़ा' शब्द का अर्थ है लंगड़ाते हुए व्यक्ति; अवनीश मिश्रा, ऑपरेशन लंगड़ा: उत्तर प्रदेश में मुठभेड़, 3,300 ‹अपराधियों' को गोली मारी गई, 13 अगस्त 2021
126 126 न्यू इंडियन एक्सप्रेस, यूपी में योगी क्यों हैं ‹एनकाउंटर मैन'?, 22 जुलाई 2019
127 नेशनल हेराल्ड इंडिया, योगी की एनकाउंटर नीति से यूपी के पुलिसवालों को बढ़ावा, 9 अक्टूबर 2019
128 OHCHR, भारत: उत्तर प्रदेश में कथित पुलिस हत्याओं से संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ चिंतित, 11 जनवरी 2019
129 यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 26
130 यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृष्ठ 18-19
131 हिंदुस्तान टाइम्स, हॉर्न्स ऑफ़ ए डिलेमा: एक सींग वाले गैंडे को बचाने की लड़ाई में परिणाम दिखाने की कोशिश में, काजीरंगा के वन अधिकारी निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे होंगे', [n.d]
132 फ्रंटलाइन, 2017 से मुठभेड़ में हुई मौतों के मामलों में वृद्धि के बाद असम जांच के दायरे में - फ्रंटलाइन, 4 मई 2023
133 आर्टिकल 14, मवेशी तस्करों, ड्रग तस्करों, संदिग्ध विद्रोहियों की गोलीबारी: असम में मुठभेड़ में हुई हत्याओं में 20 गुना वृद्धि के अंदर, 5 अप्रैल 2024
134 फ्रंटलाइन, 2017 से मुठभेड़ में हुई मौतों के मामलों में वृद्धि के बाद असम जांच के दायरे में - फ्रंटलाइन, 4 मई 2023
135 न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 171"घटनाएं चिंताजनक हैं': पुलिस मुठभेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने असम से मांगा ब्योरा22 ,' अक्टूबर 202।

केस स्टडी: कथित भागने के प्रयासों में हत्याएँ

मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और चिन्ताकुंता चेन्नाकेशावुलु

2019 में, तेलंगाना में, पुलिस ने चार युवकों - मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और चिन्ताकुंता चेन्नाकेशवुलु की हत्या कर दी - जो एक बलात्कार और हत्या के मामले में संदिग्ध थे। ये हत्याएँ कथित अपराध स्थल पर ही हुईं, पुलिस का दावा है कि संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया था।[136] हालाँकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जाँच आयोग ने पाया कि ये हत्याएँ न्यायेतर हत्याएँ थीं और हत्या के आरोपों पर सुनवाई के लिए मामले को राज्य न्यायालय को भेज दिया।[137] 3 मई 2024 को, न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आगे की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए, इस फैसले को अब पीड़ितों के परिवार चुनौती दे रहे हैं[138]

विकास दूबे

2020 में एक संदिग्ध गिरोह के नेता, विकास दूबे की पुलिस हिरासत में आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दावा किया कि उसने भागने का प्रयास किया, एक पुलिस अधिकारी की बंदूक चुराई और पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई। हालाँकि, घटनाओं के इस संस्करण पर सोशल मीडिया और प्रेस में टिप्पणीकारों द्वारा व्यापक रूप से सवाल उठाए गए थे, जिन्होंने पूछा था कि «एक संदिग्ध जिसने कथित तौर पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, वह भागने का प्रयास क्यों करेगा, और वह एक अधिकारी की बंदूक कैसे ले पाएगा» ।[139] ध्यान देने योग्य है कि अपनी हत्या वाले दिन, विकास दूबे ने कथित पुलिस 'मुठभेड़' से संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।[140]

अक्षय शिंदे

अगस्त 2024 में, महाराष्ट्र राज्य के बदलापुर स्थित एक स्कूल परिचारक अक्षय शिंदे को स्कूल परिसर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 23 सितंबर 2024 को, जेल और पुलिस थाने के बीच पुलिस की गाड़ी में ले जाते समय अक्षय की हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि उसने एक पुलिस अधिकारी से बंदूक छीनकर गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे गोली मार दी। उस महीने अक्षय के पिता द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने घातक बल का उपयोग करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, विशेष रूप से यह देखते हुए कि गाड़ी में पाँच अधिकारी मौजूद थे और अक्षय शारीरिक रूप से बलशाली नहीं था।[141] जनवरी 2025 में, अदालत को सौंपी गई एक मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस अधिकारियों का बल प्रयोग उचित नहीं था।[142] रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय की उंगलियों के निशान उस बंदूक पर नहीं पाए गए थे जिसे उसने कथित तौर पर छीना था।[143]

136 इंडिया टुडे, हैदराबाद पशुचिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले के सभी 4 आरोपी पुलिस पीछा करते हुए मारे गए6 ,' दिसंबर 2019
137 द हिंदू, सुप्रीम कोर्ट पैनल ने 2019 में हुई हत्याओं के लिए तेलंगाना पुलिस को दोषी ठहराया, 21 मई 2022
138 हिंदुस्तान टाइम्स, तेलंगाना मुठभेड़ हत्याएँ: पीड़ितों के परिवार पैनल रिपोर्ट के निलंबन को चुनौती देंगे, 3 मई 2024
139 बीबीसी, विकास दुबे: भारतीय पुलिस हत्या के संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद गोली मारकर हत्या, 10 जुलाई 2020; इंडिया टुडे, 'क्या विकास दुबे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया, मीडिया के वाहनों को क्यों रोका गया: मौत कई सवाल उठाती है›, 10 जुलाई 2020
140 यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ, अक्टूबर 2021, पृ. 26.
141 सबरंग इंडिया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की मौत के लिए ज़िम्मेदार 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया, 22 जनवरी 2025
142 द हिंदू, बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: हिरासत में आरोपी की मौत के लिए ज़िम्मेदार 5 पुलिसकर्मियों की जाँच पूरी, 20 जनवरी 2025
143 सबरंग इंडिया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की मौत के लिए ज़िम्मेदार 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया, 22 जनवरी 2025

प्रभावित समूह और यातना के संदर्भ

© Reuters/Adnan Abidi

2021 में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद दिल्ली में लाल किले के सामने दंगा रोधी गियर में पुलिस पहरा देती हुई। भारत के व्यापक किसान विरोध प्रदर्शनों ने पुलिस की बर्बरता के आरोपों को जन्म दिया।

भारत में यातनाएँ विभिन्न संदर्भों में होती हैं और विविध समूहों को प्रभावित करती हैं। यह खंड असहमति को दबाने, मानवाधिकार रक्षकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को प्रताड़ित करने, और धार्मिक अल्पसंख्यकों व अन्य हाशिए के समुदायों पर अत्याचार करने के एक साधन के रूप में यातना के व्यापक उपयोग की जाँच करता है। यह इस बात का भी पता लगाता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में यातनाएँ और अन्य दुर्व्यवहार विशेष रूप से तीव्रता से कैसे प्रकट होते हैं, या तो इसलिए कि उन्हें राज्य द्वारा 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है या किसी विशिष्ट स्थानीय और राजनीतिक संदर्भ के कारण।

असहमति जताने वालों पर अत्याचार

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उदय के बाद से, भारत में मानवाधिकारों के रिकॉर्ड में गंभीर गिरावट आई है और नागरिक अधिकार तेज़ी से कम होते जा रहे हैं।[144]हालाँकि विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में भारतीय नागरिक समाज को दबाने के प्रयास लंबे समय से देखे जाते रहे हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार रक्षकों पर हमले काफ़ी बढ़ गए हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद (हिंदुत्व) को बढ़ावा देने और असहमति जताने वालों को चुप कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है।[145]

2014 और 2024 के बीच, भारत रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 19 स्थान नीचे खिसककर 140वें से 159वें स्थान पर आ गया है, जो रूस से सिर्फ़ तीन स्थान ऊपर है।[146] 2024 में, पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी नीतियों के अन्य आलोचकों के उत्पीड़न के कारण, फ्रीडम हाउस ने भारत को «आंशिक रूप से स्वतंत्र» की श्रेणी में डाल दिया था।[147] अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का एक स्पष्ट उदाहरण जनवरी में 2023 में, सरकार ने 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगों की जाँच करने वाली बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया,[148] जिसके बाद बीबीसी के कार्यालयों पर छापे मारे गए।[149] देश के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए, अधिकारियों ने ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों को डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटाने का निर्देश दिया।[150]

वास्तव में, भाजपा के सत्ता में आने के बाद से नागरिक समाज पर ऑनलाइन अभिव्यक्ति-नियंत्रण और सख्त हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि ट्विटर और यूट्यूब ने आम तौर पर ऑनलाइन आवाज़ों को नियंत्रण करने के सरकार के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है।[151] अकेले 2022 में, भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में 84 बार इंटरनेट बंद किया।[152]

इसके अतिरिक्त, एक अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता पहल, पेगासस प्रोजेक्ट ने 2017 और 2023 के बीच सरकार द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग के माध्यम से भारतीय नागरिकों की गैरकानूनी निगरानी का पर्दाफाश किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र निकायों में चिंताएँ बढ़ गईं।[153] जाँच से पता चला कि मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों, वकीलों और विपक्षी राजनेताओं के कम से कम 300 फ़ोन नंबर प्रभावित हुए।[154]

गैर-सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक समाज संगठनों को भी निशाना बनाया गया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), जो आपातकाल के दौर का एक कानून था, को 2010 के पहले से ही परेशानी भरे संशोधनों के बाद 2020 में और संशोधित किया गया, जिससे भारत सरकार को गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की अनुमति मिल गई।[155] उदाहरण के लिए, 2016 में, गृह मंत्रालय ने एनजीओ पीपुल्स वॉच के लाइसेंस नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया था।[156] इस फैसले को चुनौती देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पीपुल्स वॉच द्वारा दायर एक मुकदमे में, गृह मंत्रालय ने तर्क दिया कि समूह ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया, "भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को नकारात्मक रूप में चित्रित किया ”।[157]

144 सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस, भारत में नागरिक समाज घेराबंदी में, 12 जनवरी 2024
145 फॉरेन अफेयर्स हिंदू राष्ट्रवाद का अजेय उदय | फॉरेन अफेयर्स 13 अप्रैल 2022; यह भी देखें CIVICUS भारत: प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में नागरिक स्वतंत्रता पर खतरनाक हमला, 17 अप्रैल 2024
146 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया फैक्टफाइल, [n.d]
147 फ्रीडम हाउस, भारत: विश्व में स्वतंत्रता 2024 देश रिपोर्ट, 2024; वी-डेम इंस्टीट्यूट, निरंकुशता वायरल हो रही है: लोकतंत्र रिपोर्ट 2021, मार्च 2021, पृष्ठ 20
148 HRW भारत: अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते दुर्व्यवहार, आलोचक (अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार)11 ,‘ जनवरी 2024; HRW, भारत द्वारा BBC को ब्लॉक करना वृत्तचित्र व्यापक कार्रवाई को दर्शाता है, 23 जनवरी 2023
149 जॉर्ज राइट, आयकर अधिकारियों द्वारा बीबीसी इंडिया कार्यालयों की तलाशी, 14 फरवरी 2023
150 HRW अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार, 11 जनवरी 2024; HRW, भारत द्वारा बीबीसी वृत्तचित्र को ब्लॉक करना व्यापक कार्रवाई को दर्शाता है, 23 जनवरी 2023
151 द वाशिंगटन पोस्ट, भारत ने ट्विटर को कैसे नियंत्रित किया और ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए वैश्विक मानक स्थापित किया, 2023
152 एक्सेस नाउ, लगातार पाँच साल: भारत 2022 का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन अपराधी है, 28 फ़रवरी 2023
153 AI, भारत 2021, 2021; HTCttee, समापन अवलोकन 2024, पैरा 43
154 AI, भारत 2021, 2021; HRCttee, समापन अवलोकन 2024, पैरा 43
155 फ़र्स्ट पोस्ट, विदेशी चंदे को लेकर एनजीओ पर सीबीआई की कार्रवाई: इंदिरा गांधी द्वारा पारित एफसीआरए को पिछले कुछ वर्षों में कैसे संशोधित किया गया है, 11 मई 2022
156 OMCT भारत: सरकार को मानवाधिकार समूहों को परेशान करना बंद करना चाहिए, 18 जनवरी 2021
157 OMCT, भारत: सरकार को मानवाधिकार समूहों को परेशान करना बंद करना चाहिए, 18 जनवरी 2021

अप्रैल 2022 में, हिरासत में यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने वाले एक अन्य प्रमुख मानवाधिकार संगठन, CHRI का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।[158] लगभग उसी समय, सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और बाल श्रम पर काम करने वाले 10 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए।[159] इसके अतिरिक्त, 80 से अधिक परोपकारी और मानवाधिकार संगठनों को «पूर्व संदर्भ श्रेणी» में रखा गया, जिसके तहत उन्हें प्राप्त होने वाले किसी भी विदेशी धन के लिए गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था।[160]

मानवाधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाना

नागरिक स्वतंत्रताओं के लगातार सिमटते माहौल के बीच, मानवाधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और नागरिक समाज के अन्य सदस्यों को यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों के जोखिम का सामना करना पड़ता है। अधिकारी अक्सर इन समूहों के खिलाफ मनमानी गिरफ्तारी, लंबे समय तक मुकदमे से पहले हिरासत, यातना और दुर्व्यवहार, और हिंसा के अन्य रूपों का सहारा लेते हैं।[161] «मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों, सरकारी आलोचकों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मुक़दमा चलाने और उन्हें परेशान करने के लिए 'दमनकारी आतंकवाद-निरोधक और राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानूनों' के उपयोग को ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा विस्तार से प्रलेखित किया गया है[162] और इसने मानवाधिकार समिति (HRCttee) में गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। 2024 के समापन अवलोकनों में HRCttee ने विशेष रूप से, आतंकवाद-रोधी कानून से जुड़े निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला:

क) घातक बल का उपयोग करने की व्यापक शक्तियाँ;
ख) अत्यधिक लम्बी अवधि तक बिना आरोप लगाए या न्यायिक समीक्षा के, निवारक हिरासत में रखना;
ग) विस्तृत और अस्पष्ट रूप से परिभाषित प्रावधानों के तहत कार्यपालिका संस्थाओं को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें व्यक्तियों को ऐसे कृत्यों के लिए ज़िम्मेदार ठहराना शामिल है जो 'खतरा पैदा करने की संभावना' रखते हों या 'लोगों में आतंक फैलाने की संभावना' रखते हों। यह प्रावधान निर्दोष होने की अवधारणा का उल्लंघन कर सकता है और असहमति जताने वालों व कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दुरुपयोग की आशंका पैदा करता है।[163]

भारत में मानवाधिकार रक्षकों के उत्पीड़न का एक प्रतीकात्मक मामला फादर स्टेन स्वामी का है, जो एक 84 वर्षीय जेसुइट पादरी, मानवाधिकार रक्षक और दलितों और आदिवासियों जैसे कमजोर समूहों के अधिकारों के लिए लंबे समय से पैरोकार थे। 8 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा कथित आतंकवाद के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।[164] भीड़भाड़ वाली तलोजा सेंट्रल जेल में हिरासत में रहने के दौरान, उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और तेज़ी से बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद, उन्हें नौ महीने तक चिकित्सा देखभाल और ज़मानत से वंचित रखा गया। अंततः 5 जुलाई 2021 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, जिन्होंने फादर स्वामी की मृत्यु से महीनों पहले उनकी नज़रबंदी के बारे में भारत सरकार के समक्ष चिंता जताई थी, ने एक बयान जारी कर कहा कि फादर स्वामी की मृत्यु «भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर हमेशा एक धब्बा रहेगी"।[165]

एक और मामला जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ मनमानी गिरफ्तारी, यातना और लंबे समय तक मुकदमे-पूर्व हिरासत के इस्तेमाल को दर्शाता है, वह है ब्रिटिश मानवाधिकार रक्षक और ब्लॉगर जगतार सिंह जोहल का मामला।[166]

158 हिंदुस्तान टाइम्स, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का विदेशी धन के लिए लाइसेंस रद्द, 26 अप्रैल 2022
159 द हिंदू, सरकार ने 10 जलवायु परिवर्तन, बाल श्रम एनजीओ के लिए फंडिंग पर रोक लगाई, 14 सितंबर 2021
160 द हिंदू, सरकार ने 10 जलवायु परिवर्तन, बाल श्रम एनजीओ के लिए फंडिंग पर रोक लगाई, 14 सितंबर 2021
161 OMCT, भारत: आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 18 मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है, 26 जनवरी 2022; HRW, भारत: गिरफ्तारियाँ, छापे निशाने पर सरकारी आतंकवाद निरोध के आलोचक, 13 अक्टूबर 2023
162 HRW भारत: संयुक्त राष्ट्र अधिकार समीक्षा में गंभीर चिंताएँ उठाई गईं, 18 नवंबर 2022
163 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 27
164 मानवाधिकार रक्षक स्मारक, मानवाधिकार रक्षक फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु पर वक्तव्य, 6 जुलाई 2021
165 संयुक्त राष्ट्र समाचार, मृत्यु कार्यकर्ता पादरी की हिरासत, भारत के अधिकारों के रिकॉर्ड पर एक धब्बा: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ, 15 जुलाई 2021
166 मनमाने ढंग से हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह (WGAD), ईसाई जेम्स माइकल (संयुक्त अरब अमीरात और भारत) के संबंध में राय संख्या 88/2020, 4 मार्च 2021, ए/एचआरसी/डब्ल्यूजीएडी/2020/88

केस स्टडी : मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाना

जगतार सिंह जौहल

जगतार सिंह जौहल एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जिन्हें 2017 से भारत में मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है। उन पर राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है। ये आरोप यातना के ज़रिए लिए गए बयान पर आधारित हैं। जगतार एक सिख कार्यकर्ता और ब्लॉगर हैं, जो भारत सरकार द्वारा सिखों के ख़िलाफ़ किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना करते रहे हैं।[167]

अक्टूबर 2017 में, वे शादी करने के लिए भारत आए थे। शादी के तीन हफ़्ते बाद, पंजाब के जालंधर शहर में सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सड़क से ग़ैरक़ानूनी तरीके से अगवा कर लिया। इन पुलिस अधिकारियों ने न तो अपनी पहचान बताई और न ही जगतार की गिरफ़्तारी का वारंट दिखाया। 5 नवंबर 2017 को, जगतार को पुलिस हिरासत में रखा गया। 10 दिनों तक उन्हें एक अज्ञात स्थान पर बिना किसी संपर्क के रखा गया, जहाँ न तो किसी वकील से, न ही उनके परिवार से, और न ही ब्रिटिश उच्चायोग के किसी प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सका। जगतार को झूठे «स्वीकारोक्ति» के लिए प्रताड़ित किया गया था, जिसका इस्तेमाल अधिकारियों ने उसके खिलाफ कई मामलों में किया है।[168]

उसके खिलाफ आपराधिक मामलों में 2018 के आरोपपत्रों में हत्या की साजिश, आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों के इस्तेमाल जैसे कथित अपराधों का उल्लेख है। «आतंकवाद» का उल्लेख बेहद चिंताजनक है क्योंकि, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, भारत में आतंकवाद के आरोपों वाले मामलों में यातना का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, भारतीय कानून में कुछ आतंकवादी अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, और हाल के वर्षों में ऐसी मृत्युदंड की सज़ाएँ दी गई हैं।

मई 2022 में, अवैध रूप से स्वतंत्रता से वंचित करने के मामलों पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र की मनमानी हिरासत पर कार्यदल (WGAD) ने पाया कि की की हिरासत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मनमानी है, क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और उनके न्यायसंगत मुकदमे के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है।[169] अगस्त 2022 में, इंवेस्टिगेटरी पावर्स कमिश्नर का कार्यालय— जो यूके की खुफिया निगरानी संस्था है — द्वारा एक रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद यह सामने आया कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों MI5 और MI6 ने भारतीय अधिकारियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करके जगतर की हिरासत और यातना में योगदान दिया हो सकता है।[170] ली डे में जगतर की कानूनी टीम द्वारा, Reprieve और REDRESS के समर्थन के साथ दायर एक कानूनी दावा यूके की अदालतों में लंबित है।[171]

सितंबर 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करने के बावजूद कि जगतर के मुकदमों में गंभीर देरी हुई है, उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया।[172]

मार्च 2025 में, जगतर को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष उनके एक आतंकवादी साज़िश से जुड़े होने का कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इस मामले में बरी होने के बावजूद, जगतर अब भी हिरासत में हैं, और भारत की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज आठ अतिरिक्त मामलों का सामना कर रहे हैं—जो सभी उसी "कबूलनामे" पर आधारित हैं, जिसे यातना के तहत उनसे लिया गया था।

यूएन अधिकारियों सहित कई बार उनकी तत्काल रिहाई की मांग किए जाने के बावजूद—और गिरफ्तारी व यातना के 7 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी—जगतर मनमाने ढंग से हिरासत में बने हुए हैं।

167 REDRESS, जगतार सिंह जौहल; राहत, जगतार सिंह जौहल
168 REDRESS, और राहत, जगतार सिंह जौहल: मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए ब्रिटिश ब्लॉगर को मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है, 2023
169 WGAD, जगतार सिंह जौहल (भारत) के संबंध में राय संख्या 80/2021, 4 मई 2022, A/HRC/WGAD/2021/80, पैरा 119
170 BBC न्यूज़, जगतार सिंह जौहल मामला: ब्रिटेन की जासूसी एजेंसियों पर मुखबिरी का आरोप, जिसके कारण यातना दी गई, 22 अगस्त 2022
171 REDRESS, जगतार सिंह जौहल
172 द गार्जियन, ब्रिटिश कार्यकर्ता को बिना मुकदमे के भारतीय जेल में वर्षों बिताने के बाद ज़मानत से वंचित कर दिया गया, 19 सितंबर 2024

भारत में असहमति को दबाने के लिए व्यापक हिंसा की HRCttee ने निंदा की है। HRCttee ने 2024 में 2018 से भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले 60 से अधिक कार्यकर्ताओं, व्हिसलब्लोअर, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों की हत्या और ऑनलाइन या शारीरिक हमलों और उत्पीड़न की रिपोर्टों पर ध्यान दिया।[173] मानवाधिकार आयोग ने इन पर भी चिंता व्यक्त की:

> 2006 से 59 पत्रकारों की हत्या, साथ ही [...] मानवाधिकार रक्षकों को भारत से बाहर यात्रा करने और संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ जुड़ने से रोकने के आरोप, जैसे कि खुर्रम परवेज का मामला, एक कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक, जिसे मानवाधिकार परिषद में भाग लेने के लिए जिनेवा जाने से रोका गया था और 2021 से मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है।[174]

फरवरी 2021 में, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स अलर्ट-इंडिया (HRDA-India) और तीन प्रमुख मानवाधिकार संगठनों द्वारा श्रम अधिकार कार्यकर्ता और मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार के अपहरण, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और यातना देने के संबंध में NHRC को एक तत्काल अपील दी गयी।[175] उनकी गिरफ़्तारी जनवरी 2021 में उनकी सहयोगी और दलित श्रम अधिकार कार्यकर्ता, नौदीप कौर की गिरफ़्तारी के बाद हुई, जिन्हें भी पुलिस ने पीटा था। हिरासत में रहते हुए, कुमार को कथित तौर पर सोनीपत स्थित CIA के सदस्यों और हरियाणा के सोनीपत स्थित कुंडली थाने की पुलिस द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी गईं। कम से कम पांच मेडिकल जांचों में दुर्व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद, बाद में एक मेडिकल जांच से पता चला कि उनके पैरों के तलवों पर मारा गया था, उन पर गर्म पानी डाला गया था, दोनों पैरों और हाथों में फ्रैक्चर थे, और उन्हें नींद से वंचित रखा गया था।[176] पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंततः पुष्टि की कि कुमार को प्रताड़ित किया गया था, यह कहते हुए कि सरकारी डॉक्टरों ने «स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियों के इशारे पर काम किया था"।[177]

राजनीतिक और मानवाधिकार सक्रियता को दबाने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा आतंकवाद-रोधी कानून के उपयोग का उदाहरण BK-16 के रूप में जाने जाने वाले 16 कार्यकर्ताओं के मामले से भी मिलता है।[178] ये कार्यकर्ता, जो दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए के समूहों के अधिकारों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे, को जून 2018 और अक्टूबर 2020 के बीच विभिन्न समयों पर गिरफ्तार किया गया था और अन्य आरोपों के अलावा, "भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने» के लिए गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपित किया गया था।[179] फादर स्टेन स्वामी - जो इन 16 कार्यकर्ताओं में से थे और जिनके मामले का उल्लेख ऊपर किया गया है - की हिरासत में मृत्यु हो गई, कुछ को ज़मानत मिल गई, और कई लोग अभी भी इस दमनकारी कानून के तहत जेल में बंद हैं।[180]

भारत सरकार द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर, कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने को लेकर भी चिंताएँ बढ़ गई हैं। भारत के अपने 2024 के परीक्षण में, HRCttee ने «राजनीतिक विरोधियों और मानवाधिकार रक्षकों के अंतरराष्ट्रीय दमन» के बारे में चिंता व्यक्त की।[181] यह हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिख अलगाववादी नेता निखिल गुप्ता और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्याओं से उजागर हुआ है, जहाँ भारत सरकार की संभावित भागीदारी पर सवाल उठाए गए हैं।[182]

भारत में पत्रकारों पर हमले भी बढ़ रहे हैं, समाचार प्रकाशनों ने भारत को «पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक» करार दिया है।[183] मीडिया संस्थानों को अक्सर छापेमारी और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है, फरवरी 2023 में बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई दोनों कार्यालयों पर छापे मारे गए,[184] और उसी वर्ष न्यूज़क्लिक कार्यालय और न्यूज़क्लिक पत्रकारों के घरों पर छापे मारे गए।[185] 2024 में 226

173 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जुलाई 2024, अनुच्छेद 1
174 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जुलाई 2024, अनुच्छेद 1
175 CHRI, कार्रवाई के लिए तत्काल अपील - हरियाणा: मानव संसाधन विकास मंत्री श्री शिव कुमार का सोनीपत में हरियाणा पुलिस द्वारा अपहरण, अवैध हिरासत, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना (तत्काल अपील - हरियाणा), 27 फरवरी 2021
176 CHRI, तत्काल अपील - हरियाणा, 27 फरवरी 2021
177 द प्रिंट, जांच रिपोर्ट कहती है हरियाणा पुलिस ने श्रमिक कार्यकर्ता शिव कुमार को प्रताड़ित किया, डॉक्टरों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, 23 दिसंबर 2022
178 आउटलुक इंडिया, भीमा कोरेगांव 16: किन कार्यकर्ताओं को ‹भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने' के लिए कैद किया गया था? (भीमा कोरेगांव 16), 18 जनवरी 2024
179 AI, BK16 की रिहाई की मांग के लिए अभी कार्रवाई करें, 12 दिसंबर 2022
180 आउटलुक इंडिया, भीमा कोरेगांव 16
181 HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 51
182 Time, भारत अपने देश और दुनिया भर में सिखों को क्यों निशाना बना रहा है, 5 दिसंबर 2023; अमेरिकी न्याय विभाग, जनसंपर्क कार्यालय | न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश के संबंध में आरोपों की घोषणा की | संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग, 29 नवंबर 2023; एसोसिएटेड प्रेस, हरदीप सिंह निज्जर: वह सिख कार्यकर्ता कौन था जिसकी हत्या ने कनाडा और भारत को विभाजित कर दिया है? | एपी न्यूज़, 20 सितंबर 2023. एसोसिएटेड प्रेस, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कनाडा में सिखों को निशाना बनाने के भारत के आरोपों को उठाया, 5 नवंबर 2024 को भी देखें
183 द नेशन, मोदी का भारत «पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक" | द नेशन, 8 नवंबर 2021
184 AP न्यूज़, भारतीय अधिकारियों ने तलाशी के बाद बीबीसी पर कर चोरी का आरोप लगाया, 17 फरवरी 2023
185 एसोसिएटेड प्रेस, न्यूज़क्लिक: भारतीय पुलिस ने स्वतंत्र समाचार साइट के संपादक और प्रशासक को गिरफ्तार किया | एपी न्यूज़, 5 अक्टूबर 2023

पत्रकारों को निशाना बनाया गया और पिछले वर्ष 194 को निशाना बनाया गया था।[186] कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 11 पत्रकार मारे गए।[187]

पत्रकारों के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानून UAPA के इस्तेमाल का भी दस्तावेजीकरण किया गया है। पत्रकारों के खिलाफ आतंकवाद-रोधी यूएपीए (UAPA) कानून के उपयोग का भी दस्तावेज़ीकरण किया गया है। 2022 में, यह रिपोर्ट किया गया कि सात में से छह कैद पत्रकारों की यूएपीए के तहत जाँच की जा रही थी या उन पर आरोप लगाए गए थे, जो अब तक का सबसे अधिक आँकड़ा था।[188] इन सात पत्रकारों में से तीन एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद थे। सात में से एक, आसिफ सुल्तान को UAPA के तहत अपनी प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद ज़मानत मिल गई थी, लेकिन जल्द ही उसे जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुक़दमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, और ज़मानत के लिए आवेदन करने या क़ानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुँचने की उसकी क्षमता सीमित होती है।[189]

केस स्टडी : मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाना

सिद्दीक कप्पन

सिद्दीक कप्पन एक पत्रकार और मानवाधिकार रक्षक हैं जो भारत में धार्मिक और जातिगत अल्पसंख्यकों पर होने वाले वाले मानवाधिकार उल्लंघनों पर रिपोर्ट करते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को, वह हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या की जाँच करने जा रहे थे, जब उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार कर लिया।[190] भारतीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सिद्दीक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध थे और कथित तौर पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया। हिरासत में रहने के दौरान, उन्हें उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिला और वे कोविड-19 से बीमार पड़ गए।[191] सिद्दीक कप्पन पर भारतीय दंड संहिता, UAPA और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए थे।[192] सितंबर 2022 में जमानत मिलने के बावजूद, सिद्दीक फरवरी 2023 तक जेल में रहे।

मोहम्मद जुबैर का मामला भी असहमति को दबाने के लिए मनमानी गिरफ्तारियों के बढ़ते इस्तेमाल का उदाहरण है।[193] पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक, जुबैर को 27 जून 2022 को 2018 के एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में अधिकारियों ने दावा किया था कि वह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला था। उनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब ऑल्ट न्यूज़ सोशल मीडिया पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा और गलत सूचनाओं, की रिपोर्टिंग कर रहा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। उन पर भारतीय दंड संहिता और विदेशी फंडिंग नियमों सहित विभिन्न कानूनों के तहत आरोप लगाए गए, जिसे व्यापक रूप से स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया। लगभग एक महीने तक हिरासत में रहने, कानूनी उत्पीड़न और राजनीति से प्रेरित आरोपों का सामना करने के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई 2022 को उन्हें जमानत दे दी, और आरोपों को अत्यधिक बताते हुए खारिज कर दिया।[194]

जम्मू-कश्मीर से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ भी इसी तरह के उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता, सज्जाद गुल को जनवरी 2022 में श्रीनगर में एक गोलीबारी के दौरान एक रिश्तेदार की हत्या का विरोध कर रहे एक परिवार का वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि उसी महीने उन्हें ज़मानत मिल गई थी, लेकिन उन्हें तुरंत जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और दो साल से ज़्यादा समय तक नज़रबंदी में रहने के बाद, 8 जुलाई 2024

186 भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट की छाया रिपोर्ट, [n.d]; HRCttee, समापन अवलोकन 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 51

187 कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स 2020 और 2025 के बीच भारत में पत्रकारों पर हमला, [n.d]

188 द वायर, जेल में बंद पत्रकारों की संख्या नए वैश्विक रिकॉर्ड पर, भारत में सात जेल में, 14 दिसंबर 2022

189 द वायर, जेल में बंद पत्रकारों की संख्या नए वैश्विक रिकॉर्ड पर, भारत में सात जेल में, 14 दिसंबर 2022; द वायर, पीएसए का दुरुपयोग': प्रेस निकायों ने कश्मीरी पत्रकार आसिफ सुल्तान की दोबारा गिरफ्तारी की निंदा की, 13 अप्रैल 2022

190 द वायर, 'अपनी लड़ाई जारी रखूंगा': सिद्दीकी कप्पन दो साल से अधिक समय बाद जेल से बाहर आए, 2 फरवरी 2023

191 द वायर, सिद्दीकी कप्पन का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आतंकवादी समूहों से संबंध स्वीकार करने के लिए 'यातना' दी, 4 फरवरी 2023

192 फ्रंटलाइन डिफेंडर्स, मानवाधिकार रक्षक और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन दो साल बाद जेल से रिहा, 7 फरवरी 2023

193 OMCT, भारत: पत्रकार और अधिकार रक्षक मोहम्मद जुबैर की मनमानी हिरासत, 12 जुलाई 2022

194 फ्रंटलाइन डिफेंडर्स, मानवाधिकार रक्षक मोहम्मद जुबैर जमानत पर रिहा, 20 जुलाई 2022

तक रिहा नहीं किया गया।[195] एक अन्य मामले में, स्वतंत्र समाचार आउटलेट कश्मीरवाला के मालिक और संपादक, फहाद शाह को फ़रवरी 2022 में गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने 600 से ज़्यादा दिन नज़रबंदी में बिताए।[196] ज़मानत मिलने और आरोपों के धीरे-धीरे खारिज होने के बावजूद, शाह दिसंबर 2023 तक जेल में रहे।[197] अपनी नज़रबंदी के दौरान, उन्हें कम से कम 20 दिनों के एकांत कारावास में रखा गया।[198]

विरोध प्रदर्शनों में यातना

भारतीय अधिकारियों ने हिंसक दमन के ज़रिए भी असहमति को दबाया है, जहाँ पुलिस ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने या तितर-बितर करने के लिए लाठियों,[199] आग्नेयास्त्रों,[200] शॉटगन छर्रों,[201] आँसू गैस के गोलों,[202] और अन्य कम घातक हथियारों और हिंसा के रूपों का इस्तेमाल किया है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) - जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कहा जाता है - ने अस्पष्ट भाषा के माध्यम से ऐसी व्यवस्थित अत्यधिक हिंसा को बढ़ावा दिया है जिससे भीड़ को नियंत्रित करने और विरोध प्रदर्शनों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, 2023 BNSS की धारा 148, पुलिस को, मजिस्ट्रेट या थाने के प्रभारी अधिकारी की अनुमति से, पाँच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा में उन लोगों के विरुद्ध बल प्रयोग करने की अनुमति देती है जिनसे «सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना» हो, बशर्ते कि तितर-बितर होने की मौखिक चेतावनी का पालन न किया जाए।[203] हालाँकि, BNSS यह स्पष्ट नहीं करता कि किस प्रकार की अवैध सभाओं को संभावित रूप से बल प्रयोग करके तितर-बितर किया जा सकता है। इसके अलावा, यह स्पष्टता नहीं प्रदान करता कि "अवैध सभाओं" को तितर-बितर करने के लिए बल का स्वीकार्य उपयोग क्या माना जाएगा, जिसमें अनुपात, आवश्यकता, और अंतरराष्ट्रीय कानून व मानकों द्वारा निर्धारित घातक बल पर प्रतिबंध शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में बल प्रयोग को कड़ाई से नियंत्रित करते हैं। शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर मानवाधिकार आयोग की सामान्य टिप्पणी 37 स्पष्ट करती है कि कानून प्रवर्तन को वैध उद्देश्यों, जैसे किसी सभा को तितर-बितर करना या किसी अपराध को रोकने के लिए, अनुपात से अधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।[204] इसी प्रकार, कानून लागू करने वाले अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता में कहा गया है कि बल का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब «सख्ती से आवश्यक» हो और «अपने कर्तव्य के पालन के लिए आवश्यक सीमा तक", और कभी भी अनुपातहीन तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।[205] कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत आगे चेतावनी देते हैं कि कम घातक हथियारों के प्रयोग को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि असंबद्ध व्यक्तियों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।[206]

जैसा कि इस खंड में दर्शाया गया है, भारतीय अधिकारी अक्सर विरोध प्रदर्शनों के पुलिस कार्य में इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अवहेलना करते हैं। इसका एक उदाहरण 2024 में कलकत्ता के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बाद देखने को मिला।[207] इसके जवाब में, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं और बड़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारियाँ कीं, जिसमें कम से कम 100 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।[208] बाद में खबरें सामने आईं कि हिरासत में बंदियों को यातनाएँ दी जा रही हैं।[209]

195 फ्रंटलाइन डिफेंडर्स, मानवाधिकार रक्षक और पत्रकार सज्जाद गुल को 15 अक्टूबर 2024 को जमानत पर रिहा किया गया; द वायर, जेल में बंद पत्रकारों की संख्या नए वैश्विक रिकॉर्ड पर, भारत में सात जेल में, 14 दिसंबर 2022

196 अलजज़ीरा, कश्मीरी पत्रकार फहद शाह 600 दिनों के बाद जेल से बाहर आए, 23 नवंबर 2023; जेल में बंद पत्रकारों की संख्या नए वैश्विक रिकॉर्ड पर, भारत में सात जेल में, 14 दिसंबर 2022

197 द गार्जियन, 'जेल आपको धीरे-धीरे कुचलती है': कश्मीरी पत्रकार जेल की यातना पर विचार करते हैं, 5 दिसंबर 2023

198 द गार्जियन, 'जेल आपको धीरे-धीरे कुचलती है': कश्मीरी पत्रकार जेल की यातना पर विचार करते हैं, 5 दिसंबर 2023

199 द वायर, भारतीय पुलिस द्वारा 'लाठीचार्ज' का दुरुपयोग, 18 मई 2018

200 पीपुल्स वॉच, द समर दैट शुक थूथुकुडी: द एंटी-स्टरलाइट प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग, 2018

201 अलजजीरा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत से कश्मीरी बच्चों पर पेलेट गन का इस्तेमाल बंद करने को कहा, 30 जून 2021

202 रॉयटर्स, भारतीय पुलिस ने कोलकाता डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, 27 अगस्त 2024

203 भारत सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 148, पृष्ठ 45. यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 129 थी

204 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामान्य टिप्पणी संख्या 37, 17 सितंबर 2020, सीसीपीआर/सी/जीसी/37, पैरा 79; OHCHR कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के प्रयोग पर मूल सिद्धांत, 7 सितंबर 1990, सिद्धांत 3 और 5(बी)

205 संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार संहिता, 17 दिसंबर 1979 का महासभा संकल्प 34/169 (संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता)

206 संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत, सिद्धांत 3 और 5(बी)

207 BBC, अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से भारत में विरोध प्रदर्शन भड़के, 14 अगस्त 2024

208 BBC, भारतीय डॉक्टर की हत्या से नाराज़ प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी गई, 27 अगस्त 2024

209 द टेलीग्राफ इंडिया, आरजी कर विरोध प्रदर्शन | सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार विरोधी प्रदर्शनकारी को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाई SIT की नए सिरे से समीक्षा के निर्देश दिए – टेलीग्राफ इंडिया, 11 नवंबर 2024

वर्षों से, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में कार्यरत पुलिस और सुरक्षा बल शॉटगन के छर्रों का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें आँखों की रोशनी को नुकसान और अन्य दीर्घकालिक विकलांगताएँ शामिल हैं।[210] 2016 में इस क्षेत्र में हुए एक विद्रोह के दौरान, छर्रों के कारण 1,100 से ज़्यादा लोगों की दृष्टि चली गई थी।[211] 2021 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जम्मू और कश्मीर में प्रदर्शनकारी नाबालिगों के खिलाफ शॉटगन के छर्रों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की।[212]

कई मामलों में, भारतीय अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बल, जिसमें आग्नेयास्त्रों और शॉटगन के छर्रों का इस्तेमाल शामिल है, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यातना या अन्य दुर्व्यवहार के समान है।[213] सुरक्षा बलों द्वारा लाठियों का इस्तेमाल एक पुनरावृत्ति वाली प्रथा बन गई है जो बल के स्वीकार्य स्तर से अधिक है। यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के अनुसार, "लाठियां कानून प्रवर्तन का कोई भी वैध उद्देश्य पूरा नहीं करती, जिसे अन्य कम हानिकारक साधनों के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता।"[214]

भारत में विरोध प्रदर्शनों पर व्यापक और हिंसक कार्रवाई का उदाहरण 2020 में पेश किए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया से मिलता है।[215]

केस स्टडी: प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार

किसान आंदोलन

2020 में, देशव्यापी प्रदर्शन हुए, जिसमें हज़ारों लोग कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन एक साल तक चले, जिसका जवाब कानून प्रवर्तन संस्थाओं ने हिंसा से दिया, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया,[216] जिसके परिणामस्वरूप 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई।[217] इन घटनाओं के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने एक बयान जारी कर भारत में अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों से «अधिकतम संयम बरतने» और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया।[218] विरोध प्रदर्शनों का हिंसक दमन बाद के वर्षों में भी जारी रहा, जिसमें पुलिस द्वारा गंभीर चोटों का दस्तावेजीकरण फरवरी 2024 में एक प्रदर्शन के दौरान किया गया, जिसका आयोजन मज़दूर संघों और अन्य लोगों ने 2021 के किसान विरोध प्रदर्शनों के बाद किए गए वादों की जवाबदेही की मांग के लिए किया था।[219]

210 AI, कश्मीर में दृष्टि खोना: पैलेट गन का प्रभाव, 13 सितंबर 2017
211 अल-जज़ीरा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत से कश्मीरी बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करने को कहा | बाल अधिकार समाचार | अल जज़ीरा, 30 जून 2021
212 अल-जज़ीरा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत से कश्मीरी बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करने को कहा | बाल अधिकार समाचार अल जज़ीरा, 30 जून 2021
213 UNHRC , शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, क्लेमेंट न्यालेत्सोसी वौले, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने हेतु कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आदर्श प्रोटोकॉल, 31 जनवरी 2024, A/HRC/55/60
214 ओमेगा रिसर्च फ़ाउंडेशन, प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राज्य हिंसा: कम घातक हथियारों के उपयोग के परिप्रेक्ष्य और रुझान, 2024, पृष्ठ 10 26
215 यूके हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी, भारत में किसानों का विरोध प्रदर्शन और कृषि सुधार, 13 दिसंबर 2021
216 BBC, भारत विरोध: किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली में दिल्ली के लाल किले में घुसपैठ की, 26 जनवरी 2021
217 BBC, भारत किसान विरोध प्रदर्शन: पंजाब के परिवार अपने मृतकों के लिए शोक मना रहे हैं, 8 दिसंबर 2021. विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के अन्य उदाहरणों में शामिल हैं: न्यूज़ क्लिक, पुलिस लाठीचार्ज के बाद, यूपी में दलित विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया | न्यूज़क्लिक, 2 अप्रैल 2018 और स्क्रॉल.इन, भीमा कोरेगांव हिंसा के कथित भड़काने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुंबई में हजारों लोगों की रैली, 26 मार्च 2018
218 UN न्यूज़, भारत: संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों में ‹अधिकतम संयम' बरतने का आग्रह किया, 7 फरवरी 2021
219 AI, भारत: विरोध की कीमत मौत नहीं होनी चाहिए, 22 फरवरी 2024

2021 और फरवरी 2024 के प्रदर्शनों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में अत्यधिक बल का उपयोग, इंटरनेट बंद करना, प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट और वीज़ा रद्द करने की धमकियाँ, और मार्च को रोकने के लिए काँटेदार तार और कीलों से बने भारी अवरोध शामिल थे।[220] कम-घातक हथियारों का उपयोग भी दर्ज किया गया, जिनमें रबर की गोलियाँ, लंबी दूरी की ध्वनि उपकरण—जो सुनने की क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं—और ड्रोन-आधारित आंसू गैस लॉन्चर शामिल थे।[221] रिपोर्ट किया गया कि ये ड्रोन-आधारित आंसू गैस लॉन्चर मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन अब इन्हें प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए बढ़ते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है।[222]

आगे की रिपोर्टों में कहा गया कि सुरक्षा बलों द्वारा लोहे के छर्रों का उपयोग भी किया गया, जिससे गंभीर आँखों की चोटें आईं।[223] फरवरी 2024 के प्रदर्शनों के दौरान लगी चोटों के परिणामस्वरूप कम से कम चार प्रदर्शनकारियों की मौत की सूचना मिली।[224] पुलिस अत्याचार के और भी आरोप सामने आए, जिनमें एक प्रदर्शनकारी की हिरासत में यातना शामिल थी—उसे गर्दन में बंधी रस्सी से घसीटा गया और पीटा गया, जिसके परिणामस्वरूप सिर में चोट और कई हड्डियों में फ्रैक्चर हुए।[225]

एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण, जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के संदर्भ में अत्यधिक बल प्रयोग और यातना का उपयोग किया गया, वह है विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया।

केस स्टडी: प्रदर्शनकारियों की यातना

नागरिकता अधिनियम विरोध प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2015 से पहले भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को तेज़ी से नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखता है।[226]

कानून के विरोधी तर्क देते हैं कि यह भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है। दिसंबर 2019 में इसके पारित होने से देशभर में व्यापक विरोध शुरू हो गए, जिनमें दसियों हज़ार लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद अधिकारियों ने भारत के कई हिस्सों में सार्वजनिक जुटानों पर प्रतिबंध लगा दिया।[227]

इन प्रदर्शनों के बाद अनेक रिपोर्टें सामने आईं, जिनमें यातना और अत्यधिक बल प्रयोग का विवरण दर्ज किया गया—जिसमें भीड़, प्रदर्शनकारियों तथा राहगीरों पर अंधाधुंध जीवित गोलियों का प्रयोग भी शामिल था।[228] देशभर में की गई कार्रवाई के दौरान कम से कम 31 व्यक्तियों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, की मृत्यु हुई, जिनमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही 14 प्रदर्शनकारियों के गोली लगने या गोली-संबंधी चोटों से मरने की सूचना मिली।[229]

220 एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI), भारत: सरकार को किसानों के विरोध को कुचलना और असहमति को 'दुश्मन 'के रूप में पेश करना बंद करना चाहिए, 09 फ़रवरी 2021; HRW भारत: किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करें, 29 फ़रवरी 2024; हिंदुस्तान टाइम्स, विरोध के दौरान हिंसा में शामिल किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 29 फ़रवरी 2024. निक्केई एशिया, भारत के विशाल किसान विरोध प्रदर्शनों से पुलिस की बर्बरता के आरोप बढ़े, 28 फ़रवरी 2024

221 PUCL, हमारे किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ना बंद करें – पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, 15 फ़रवरी 2024; द वायर, किसान विरोध ने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट को पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, 2 मार्च 2024; यूरोन्यूज़, भारतीय किसानों के विरोध में पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी, 13 फ़रवरी 2024; स्काई न्यूज़, ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी गई जब किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, 13 फ़रवरी 2024; बीबीसी न्यूज़, देखें कैसे भारतीय पुलिस किसानों पर आंसू गैस दागती है, 13 फ़रवरी 2024

222 हिंदुस्तान टाइम्स, हरियाणा कैसे पाकिस्तान सीमा पर उपयोग होने वाले ड्रोन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस गिराने के लिए कर रहा है, 14 फ़रवरी 2024

223 अल जज़ीरा, "हमें गरिमा चाहिए": भारत के किसान पैलेट्स और ड्रोन का सामना करते हुए नया सौदा मांगते हैं, 21 फ़रवरी 2023; HRW, भारत: किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करें, 29 फ़रवरी 2024

224 इंडिपेंडेंट, दिल्ली मार्च फिर शुरू होने पर पुलिस की हिंसा के बीच एक किसान की मौत, 21 फ़रवरी 2024. सबरंग इंडिया देखें: किसान विरोध: सांस की समस्या से तीन और किसानों की मौत; कुल मौतें बढ़कर 10, 19 मार्च 2024

225 ABP लाइव, सिर में चोट, फ्रैक्चर, गर्दन में रस्सी बांधकर खींचा: किसान नेता का दावा — गिरफ्तार प्रदर्शनकारी को हिरासत में 'यातना 'दी गई, 25 फ़रवरी 2024; ANI, किसान नेता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारी को हिरासत में यातना दी गई, 25 फ़रवरी 2024

226 BBC न्यूज़, CAA: भारत के नए नागरिकता कानून की व्याख्या, 12 मार्च 2024

227 BBC न्यूज़, नागरिकता अधिनियम विरोध: भारत में तीन मौतें और हज़ारों हिरासत में, 19 दिसंबर 2019

228 द वायर बिजनौर में, CAA विरोध के बाद बच्चों ने यूपी पुलिस द्वारा पिटाई का भयावह विवरण दिया, 25 दिसंबर 2019

229 स्क्रॉल इन: नागरिकता अधिनियम विरोध: उत्तर प्रदेश में 17 मौतों में से 14 'गोली लगने की चोटों' के कारण हुईं, 23 दिसंबर 2019

जनवरी 2020 में किए गए एक तथ्यान्वेषण में पाया गया कि लगभग 41 बच्चों को हिरासत में लेकर यातना दी गई, क्योंकि वे प्रदर्शनों में शामिल थे। कुछ बच्चों को कथित तौर पर वयस्कों के साथ हिरासत में रखा गया और उन्हें वयस्कों पर की जा रही यातना देखने के लिए मजबूर किया गया।[230] बचे हुए व्यक्तियों की गवाहियों में पुलिस द्वारा डंडों और लाठियों से गंभीर रूप से पीटे जाने का उल्लेख है, साथ ही अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार—जैसे नींद से वंचित करना, धमकियाँ देना और पीने के पानी तक पहुँच से इनकार करना—भी दर्ज किए गए।[231]

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन व्यक्तियों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जिनके बारे में दावा किया गया कि वे प्रदर्शनों में "कथित रूप से" शामिल थे—उनके नाम और पते प्रकाशित कर दिए गए तथा किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही उन्हें "दोषी" घोषित कर दिया गया।[232] यह तरीका व्यक्तियों और उनके समुदायों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से अपनाया गया।[233]

इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) ने निष्कर्ष निकाला कि प्रदर्शनों के प्रति पुलिस तथा भारत सरकार की प्रतिक्रिया जीवन के अधिकार और यातना तथा क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति के अधिकार की रक्षा करने के दायित्वों का उल्लंघन थी।[234]

यातना के आरोपों और हुई मौतों की व्यापक, त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांगों के बावजूद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को एक स्थल-निरीक्षण करने में दो वर्ष लग गए।[235] इस अवधि के दौरान, पीड़ित परिवारों ने पुलिस और राज्य अधिकारियों द्वारा डराए-धमकाए जाने, पोस्ट-मॉर्टेम रिपोर्ट देने से इनकार और विभिन्न प्रकार की धमकियों की शिकायत की।[236] जांच का निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, और उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी राज्य प्राधिकारी को दर्ज उल्लंघनों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया है।[237]

भेदभावपूर्ण दमन के उपकरण के रूप में यातना

अब तक इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारतीय अधिकारी नियमित रूप से कानून प्रवर्तन और हिरासत संबंधी संदर्भों में ऐसे हिंसक तरीकों का उपयोग करते हैं जो यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के समान हैं। जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति इस तरह की हिंसा का सबसे भारी बोझ उठाते हैं। अपनी 2020 की रिपोर्ट में, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर (NCAT) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1996 से 2018 तक की NHRC की वार्षिक रिपोर्टें दिखाती हैं कि भारत में हिरासत में हुई लगभग 71% मौतों में गरीब या हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे। इन समूहों में अनुसूचित जातियों (दलित), अनुसूचित जनजातियों (आदिवासी), और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक समूह, मुख्य रूप से मुसलमान शामिल हैं।[238]

230 क्विल फाउंडेशन सिटिजन्स अगेंस्ट हेट, HAQ: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, मासूमियत के साथ बर्बरता: CAA विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए यूपी पुलिस द्वारा नाबालिगों की हिरासत, यातना और अपराधीकरण, जनवरी 2020

231 क्विल फाउंडेशन सिटिजन्स अगेंस्ट हेट, HAQ: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, मासूमियत के साथ बर्बरता: CAA विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए यूपी पुलिस द्वारा नाबालिगों की हिरासत, यातना और अपराधीकरण, pp 3-7 जनवरी 2020. द गार्जियन "मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा": भारत के कार्यकर्ताओं ने झूठी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना की कहानी बताई, 1 फरवरी 2020

232 इंडिया टुडे: योगी का नाम और शर्म का राज: लखनऊ में CAA प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों, व्यक्तिगत विवरणों वाले बैनर लगाए गए, 7 मार्च 2020

233 क्विल फाउंडेशन सिटिजन्स अगेंस्ट हेट, HAQ: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, मासूमियत के साथ बर्बरता: CAA विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए यूपी पुलिस द्वारा नाबालिगों की हिरासत, यातना और अपराधीकरण, जनवरी 2020

234 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बल के गैरकानूनी उपयोग पर ब्रीफिंग पेपर

235 द वायर, यूपी में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों की हत्या के दो साल बाद, NHRC ने मौके पर जांच की, 29 दिसंबर 2021

236 द गार्जियन "मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा": भारत के कार्यकर्ताओं ने झूठी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना की कहानी बताई, 1 फरवरी 2020

237 द वायर, द इंडियन एक्सप्रेस, दंगा एफआईआर में विवरण, समयरेखा है, पुलिस को क्लीन चिट देता है; हत्या पर एफआईआर सिर्फ एक पैराग्राफ है, 2 जनवरी 2020

238 नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, क्लेप्टोमैनिया का कोई बहाना नहीं: भारत में गरीबी, पूर्वाग्रह और यातना, 10 दिसंबर 2020

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की यातना

भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरुद्ध राज्य और निजी पक्षों द्वारा लंबे समय से भेदभाव किया जाता रहा है। दशकों से, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध, जिनमें यातना भी शामिल है, बड़े पैमाने पर दंडमुक्ति के साथ किए गए।[239] भेदभावपूर्ण मान्यताओं ने अनुसूचित जातियों के सदस्यों के जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून के समक्ष समान व्यवहार के अधिकारों को प्रभावित किया है। इसने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2006 में रंगभेद के अपराध के साथ इस भेदभाव की समानता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।[240]

वर्षों से, भारतीय संसद ने 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और इसके 2016 के संशोधन सहित विधायी सुधारों के माध्यम से व्यवस्थित भेदभाव और हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य अधिक सुरक्षा प्रदान करना था। हालाँकि, संवैधानिक और विधायी सुरक्षा के बावजूद, व्यवहार में, भेदभाव और व्यापक हिंसा दंडमुक्ति के साथ बनी हुई है।[241] इस हिंसा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिकों द्वारा किया जाता है, जिन पर शायद ही कभी मुकदमा चलाया जाता है, जिससे दंडमुक्ति की संस्कृति और ऐसे कृत्यों के सामान्यीकरण को बढ़ावा मिलता है। 2023 में, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के खिलाफ 50,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए।[242] जबकि इन अपराधों के लिए अभियोजन पर आधिकारिक डेटा अनुपलब्ध है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर कम रही है - 2022 में केवल 32%।[243]

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ सामान्यीकृत भेदभाव का यह माहौल पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा यातना सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। 2019 में, नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस ने मानवाधिकार समिति (HRCttee) को बताया कि दलितों को अक्सर हिंसक तलाशी और छापे, साथ ही झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी के बाद यातना का सामना करना पड़ता है।[244] संगठन ने नोट किया कि हिरासत में दलितों को अक्सर जाति-आधारित मौखिक दुर्व्यवहार, गंभीर पिटाई, यौन हिंसा और खराब कारावास की स्थिति, और अन्य प्रकार की यातना और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में मौत हो जाती है।[245]

2021 में कर्नाटक में, एक दलित व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि गोनीबीडु पुलिस स्टेशन के तीन पुलिस अधिकारियों ने उसे "कथित तौर पर गांव में एक जोड़े के बीच कलह पैदा करने" के लिए हिरासत में रहते हुए मूत्र पीने के लिए मजबूर किया।[246] पीड़ित ने कहा कि कबूलनामा निकालने के प्रयास में उसे घंटों तक पीटा गया और अपमानित किया गया।[247]

कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।[248] सितंबर 2021 में, एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद सब-इंस्पेक्टर को कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।[249]

एक स्थानीय समाचार पत्र ने 2020-2022 के बीच पुलिस द्वारा यातना के 33 मामलों की जांच और रिपोर्ट की, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के खिलाफ किए गए थे।[250]इन मामलों में पुलिस द्वारा गंभीर पिटाई, बंदियों के बीच जबरन बलात्कार, और यातना के परिणामस्वरूप हिरासत में मौत के दस मामले शामिल हैं।

239 HRW, दलितों के खिलाफ भेदभाव का 'छिपा हुआ रंगभेद': सरकार जाति-आधारित अलगाव और हमलों को समाप्त करने में विफल, 13 फरवरी 2007
240 HRW दलितों के खिलाफ भेदभाव का 'छिपा हुआ रंगभेद': सरकार जाति-आधारित अलगाव और हमलों को समाप्त करने में विफल, 13 फरवरी 2007
241 नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस (NCDHR) न्याय की खोज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और नियम 1995 के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट, 2020
242 टाइम्स ऑफ इंडिया ST के खिलाफ अपराध: 2022 में SC के खिलाफ अपराध 13% और SC के खिलाफ 14.3% बढ़े: NCRB, 6 दिसंबर 2023
243 सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, यूपी दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सबसे आगे, मध्य प्रदेश एसटी के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों में शीर्ष पर, 24 सितंबर 2024
244 नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस और इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को संयुक्त प्रस्तुति, मुद्दों की सूची को अपनाना, 26 जुलाई 2019
245 नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस और इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को संयुक्त प्रस्तुति, मुद्दों की सूची को अपनाना, यह भी देखें कॉमन कॉज भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पृष्ठ 28
246 इंडियन एक्सप्रेस, 'सबसे जघन्य कृत्य': कर्नाटक अदालत ने दलित व्यक्ति को मूत्र पीने के लिए मजबूर करने के आरोपी पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, 04 जून 2021
247 इंडियन एक्सप्रेस, 'सबसे जघन्य कृत्य': कर्नाटक अदालत ने दलित व्यक्ति को मूत्र पीने के लिए मजबूर करने के आरोपी पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, 04 जून 2021
248 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 173; पूर्व में भारत की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973, धारा 154
249 इंडिया टुडे, कर्नाटक: दलित युवक का आरोप, पुलिस ने उसे पीटा, पुलिस थाने के अंदर मूत्र चाटने को मजबूर किया - बैंगलोर समाचार, 22 मई 2021
250 द प्रिंट, हिरासत में मौतें, यातना के दावे - झारखंड में आदिवासियों को कैसे 'पुलिस दमन' का सामना करना पड़ता है, 27 मार्च 2022

केस स्टडी: अनुसूचित जातियों और जनजातियों की यातना

परभणी में दलितों की गिरफ्तारी और यातना

दिसंबर 2024 में, संविधान की एक प्रतिकृति के साथ तोड़फोड़ को लेकर परभणी में अशांति फैल गई। 11 दिसंबर को, स्थानीय दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के जवाब में, पुलिस ने दलित आबादी वाले क्षेत्रों में हिंसक अभियान चलाया और कम से कम 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं की एक तथ्य-खोज टीम द्वारा प्रलेखित अनुसार, बंदियों को बुरी तरह पीटा गया, और हिरासत में ली गई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया।[251] बंदियों में सोमनाथ सूर्यवंशी भी शामिल थे, जिन्हें बुरी तरह पीटा गया, और 15 दिसंबर 2024 को न्यायिक हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम जांच में यह निर्धारित होने के बावजूद कि सोमनाथ की मृत्यु "कई चोटों के कारण सदमे" से हुई थी, पुलिस ने दावा किया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। 15 जनवरी 2025 को, सोमनाथ की मां द्वारा उनकी मृत्यु के लिए मुआवजे से इनकार करने और जवाबदेही की मांग करने के बाद, हिरासत में मौत और परभणी में दलित लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया गया था।

धार्मिक अल्पसंख्यकों की यातना

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को यातना, न्यायेतर हत्याओं और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा है।[252] जबकि कई धार्मिक समूह भेदभावपूर्ण हिंसा के शिकार हैं, मुस्लिम, ईसाई और सिख अनुपात अनुपात से अधिक प्रभावित हैं।[253] इन दुर्व्यवहारों को प्रणालीगत भेदभाव और राष्ट्रवादी बयानबाजी के व्यापक संदर्भ द्वारा सुगम बनाया गया है, जो पिछले एक दशक में भाजपा सरकार के तहत तेज हो गया है। इसने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को 2024 के चुनाव से पहले धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरनाक अमानवीय भाषण और उकसावे पर चिंता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है।[254]उदाहरण के लिए, झारखंड राज्य में 2024 के राज्य चुनावों में, भाजपा ने मुसलमानों को अपमानजनक और अमानवीय तरीके से चित्रित करने वाली प्रचार सामग्री प्रकाशित की, जिससे मुस्लिम विरोधी भावना को और सामान्य बना दिया गया।[255]

केस स्टडी: धार्मिक अल्पसंख्यकों की यातना

पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम लड़के की हत्या

अपनी अगस्त 2020 की रिपोर्ट में, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक मानवाधिकार एनजीओ, 'बांग्लार मानवाधिकार सुरक्षा मंच' (MASUM) ने एक युवा मुस्लिम लड़के, सहिनूर हक की न्यायेतर हत्या की सूचना दी। सहिनूर अपने घर के बाहर अपने दो भाइयों के साथ फोन पर गेम खेल रहा था जब सीमा प्रहरियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। प्रहरियों ने फिर सहिनूर के पास जाकर उसे बुरी तरह पीटा, जिसके बाद यूनिट के कमांडर ने पीड़ित को करीब से दो बार गोली मारी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सहिनूर के चाचा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज नहीं किया गया, बल्कि केवल एक केस डायरी प्रविष्टि (पुलिस रिपोर्ट) के रूप में जोड़ा गया। MASUM ने NHRC में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामले पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है।[256]

251 सबरंग इंडिया परभणी पुलिस जांच के घेरे में: फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में क्रूरता, अवैधता और संवैधानिक उल्लंघनों के आरोपों का खुलासा, 23 जनवरी 2025
252 AI, दिल्ली दंगों के छह महीने बाद, दिल्ली पुलिस मानवाधिकार उल्लंघन के बावजूद दंडमुक्ति का आनंद ले रही है, 27 अगस्त 2020
253 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 13
254 OHCHR, भारत: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने मानवाधिकारों की रक्षा करने और चुनावों से पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को समाप्त करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का आग्रह किया, 07 मार्च 2024. और फ़ॉरेन पॉलिसी, "मोदी का चुनावी भाषण खतरनाक है," 28 मई 2024
255 द न्यूज़ मिनट, भाजपा विज्ञापनों ने फिर से मुसलमानों को निशाना बनाया, इस बार झारखंड चुनाव के लिए, 17 नवंबर 2024
256 MASUM, मासिक रिपोर्ट, अगस्त 2020

हाल के वर्षों में, सांप्रदायिक हिंसा में कथित रूप से शामिल या भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध करने वाले अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले दंडात्मक उपाय एक चिंताजनक प्रवृत्ति के रूप में उभरे हैं। इनमें घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों[257] को ध्वस्त करना शामिल है। इस मुद्दे ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को चिंतित किया।[258]

ये घटनाएँ एक व्यापक संदर्भ में घटित होती हैं, जिसमें दुर्व्यवहार और हिंसा शामिल है—विशेष रूप से उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।। उदाहरण के लिए, जून 2022 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि राज्य के अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक बयानों के जवाब में मुस्लिम आबादी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों को पुलिस ने हिंसक रूप से दबा दिया, जिसके परिणामस्वरूप दो मौतें हुईं और घरों को ध्वस्त किया गया।[259]

अंतर-सांप्रदायिक झड़पों के जवाब में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य हिंसा का उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2022 में, कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले मुसलमानों के खिलाफ दंडात्मक उपायों में वृद्धि पर एक बयान में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक घटना का वर्णन किया जिसमें एक हिंदू त्योहार के दौरान पथराव करने के आरोपी मुस्लिम पुरुषों को पुलिस अधिकारियों द्वारा एक लैंप-पोस्ट से बांधकर सार्वजनिक रूप से लाठियों से मारा गया।[260]

मुसलमानों - साथ ही अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों - को भी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में रहते हुए भेदभावपूर्ण यातना का शिकार होना पड़ता है। NCAT ने बताया कि 2019 में, पुलिस हिरासत में मरने वालों में से 60% या तो मुस्लिम, दलित या आदिवासी थे।[261] 2022 के जेल आंकड़ों के अनुसार, भारत में 573,220 कैदियों में से 19.3% मुस्लिम थे, जबकि भारत में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 14.2% थी।[262] अपनी आबादी की तुलना में हिरासत में लिए गए मुसलमानों की संख्या की असमानता व्यक्तिगत राज्यों की जांच करने पर और भी स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना में जहां मुसलमान आबादी का लगभग 12.68% हैं, 2020 में 49.5% बंदी मुस्लिम थे।[263]

'शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिशोध' खंड में नीचे उल्लेखित यूनुस शाह का मामला मुसलमानों के ख़िलाफ़ यातना का एक उदाहरण है। इस मामले में, वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन (WGAD) ने पाया कि शाह को जिस अवधि में हिरासत में रखा गया और यातना दी गई, वह भेदभावपूर्ण आधारों पर आधारित थी—विशेष रूप से, धार्मिक अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय के सदस्य के रूप में उनकी स्थिति के कारण।[264] जून 2022 में, ऑनलाइन प्रसारित एक वीडियो में भारतीय पुलिस को हिरासत में मुसलमानों को बुरी तरह पीटते हुए दिखाया गया; इसे एक भाजपा सदस्य द्वारा साझा किया गया था जिसने दुर्व्यवहार को पुरुषों के लिए "उपहार" बताया।[265]

साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन ने अपनी रिपोर्ट 'भारत में यातना, दंडमुक्ति और धार्मिक अल्पसंख्यक' में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य बलों द्वारा यातना के और मामले प्रस्तुत किए। रिपोर्ट किए गए पैटर्न में गौ-हत्या के झूठे आरोप, हिंदू मंत्रों को दोहराने के लिए मजबूर करना, और पिटाई से मौत शामिल थी।[266]

257 AI, भारत: "अगर आप बोलेंगे, तो आपका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा": भारत में बुलडोजर अन्याय, 7 फरवरी 2024

258 जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच, पुनिटिव डिमोलिशन्स के कारण भारत में लगभग 7,40,000 लोग विस्थापित हुए, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें बिना उचित प्रक्रिया के इस प्रथा की निंदा की गई और किसी भी ढहाई से पहले कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। देखें: आवास के पर्याप्त अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक; अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष प्रतिवेदक और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिवेदक, 9 जून 2022; पारुल राघुवंशी, ऑक्सफ़र्ड ह्यूमन राइट्स हब,पर्याप्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक 9 जून 2022. यह भी देखें BBC, भारत की शीर्ष अदालत ने सजा के रूप में 'बुलडोजर न्याय' पर प्रतिबंध लगाया, 13 नवंबर 2024. देखें: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ढाँचों के विध्वंस के संबंध में निर्देशों पर याचिकाओं में निर्णय, 13 नवंबर 202

259 AI, भारत: अत्यधिक बल का प्रयोग, 14 जून 2022

260 HRW, भारत: मुसलमानों की त्वरित सजा में वृद्धि | ह्यूमन राइट्स वॉच, 7 अक्टूबर 2022

261 CNN, भारतीय पुलिस न्याय के लिए शॉर्टकट के रूप में हिंसा का उपयोग करती है, 3 दिसंबर 2020

262 आर्टिकल 14, कर्नाटक पुलिस हिरासत में मुस्लिम बढ़ई की मौत के लिए जवाबदेही की कमी, 20 जनवरी 2025

263 आर्टिकल 14, भारत की जेलों में मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत उनकी आबादी के अनुपात में क्यों नहीं है, 15 मार्च 2022

264 संयुक्त राष्ट्र वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन (WGAD), यूनुस शाह (भारत) से संबंधित राय संख्या 45/2024, 10 अक्टूबर 2024

265 BBC, नूपुर शर्मा विरोध प्रदर्शन: पुलिस की बर्बरता का वीडियो जिसने भारत को चौंका दिया, 17 जून 2022

266 साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन भारत में यातना और दंडमुक्ति: मुसलमानों के खिलाफ हिरासत में यातना का केस स्टडी, मई 2025

केस स्टडी: धार्मिक अल्पसंख्यकों की यातना

दाऊद शेख की यातना और मृत्यु

पश्चिम बंगाल के दो बच्चों के पिता और मुस्लिम दिहाड़ी मजदूर दाऊद शेख को 7 अप्रैल 2024 को उनके परिवार को सूचित किए बिना गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में रहते हुए, पूछताछ की गई और उन्हें यातना देकर मार डाला गया, हालांकि उनके परिवार को 13 अप्रैल 2024 को बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जब परिवार को उनका शव देखने की अनुमति दी गई, तो उन्हें कई खरोंचें मिलीं, जो मृत्यु के किसी अन्य कारण की ओर संकेत करते थे।[267] एक अस्पताल के डॉक्टर ने कथित तौर पर परिवार को बताया कि दाऊद की गर्दन पर निशान अप्राकृतिक मौत का संकेत देते हैं जो आत्महत्या के साथ असंगत है, जैसा कि पुलिस ने दावा किया था। 15 अप्रैल 2024 को, दाऊद की पत्नी ने शमशेरगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया।[268] नागरिक समाज के आह्वान के बाद, NHRC ने 6 सितंबर 2024 को हिरासत में मौत का मामला दर्ज किया।[269] आज तक NHRC द्वारा किसी भी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है।

इसके अतिरिक्त, सिख समुदाय के सदस्यों को भारत में लंबे समय से भेदभावपूर्ण हिंसा का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से पंजाब राज्य में, जहां सिखों का बहुमत है।[270] सिखों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन में जबरन गायब करना, न्यायेतर हत्याएं, मनमानी हिरासत, और आतंकवाद से संबंधित आरोपों के तहत यातना शामिल है, जैसा कि ऊपर वर्णित जगतार सिंह जोहल के मामले में बताया गया है है। इसी तरह, 2021 के किसान विरोध प्रदर्शनों के दौरान - जिसमें कई सिखों ने भाग लिया था - सिख प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर आतंकवादी कह कर राज्य के अधिकारियों द्वारा बदनाम किया गया।[271]

अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे ईसाई भी अत्यधिक स्तर की हिंसा का सामना करते हैं।[272] 2024 में अकेले, ईसाई समुदाय को लक्षित करने वाली 834 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2015 से लगातार वृद्धि को दर्शाती हैं, जब 179 मामले दर्ज किए गए थे, इसके बाद 2020 में 327 मामले और 2023 में 734 मामले दर्ज किए गए।[273]

भारतीय नागरिक समाज संगठनों ने रिपोर्ट दी है कि कई पीड़ित पूर्वाग्रह के डर से पुलिस शिकायत दर्ज करने में संकोच करते हैं, क्योंकि पुलिस अक्सर रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है और अपराधियों द्वारा प्रतिशोध के जोखिम का हवाला देती है।[274] इसके अतिरिक्त, ईसाई समुदाय के सदस्य भी एंटी-कन्वर्ज़न क़ानूनों के तहत आपराधिक अभियोजन का सामना करते हैं — यह ऐसे क़ानून हैं जिन्हें भारत के कई राज्यों में लागू किया गया है, जो धार्मिक परिवर्तन पर रोक लगाते हैं और जिनका उपयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अंतरधार्मिक संबंधों को निशाना बनाने के लिए किया गया है।[275] जून 2024 में, धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबंधित आरोपों में उत्तर प्रदेश में 13 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया।[276]

2022 में, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 1,000 आदिवासी ईसाइयों को कथित तौर पर उनके गांवों से विस्थापित कर दिया गया था। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 2023 में रिपोर्ट दी कि भारत में ईसाइयों को प्रति दिन औसतन दो हमलों का सामना करना पड़ता है।[277]

मणिपुर में, 2023 की अशांति ने ईसाई कुकी समुदाय को अनुपातहीन रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 160 मौतें हुईं, 300 से अधिक लोग घायल हुए, और हजारों लोग विस्थापित हुए। मणिपुर हिंसा, जिसमें सामूहिक बलात्कार सहित यौन हिंसा शामिल थी, ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को गंभीर चेतावनी व्यक्त करते हुए एक बयान जारी करने के लिए प्रेरित किया।[278] साथ ही, जुलाई 2024 में,

267 OMCT, भारत: पुलिस हिरासत में दाऊद शेख की मौत पुलिस यातना को उजागर करती है, 31 मई 2024
268 काउंटर व्यू इन, पश्चिम बंगाल में 27 वर्षीय युवक की हिरासत में मौत को आत्महत्या 'प्रदर्शित' किया गया, 17 मई 2024
269 NHRC, केस नंबर 76/25/13/2025-AD, एक्शन नंबर 1, दिनांक 24 मार्च 2025
270 द सिख कोएलिशन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (USCIRF) के समक्ष सुनवाई के लिए बयान, 25 जनवरी 2025
271 यूके हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी, जगतार सिंह जोहल की कैद, 18 जनवरी 2023
272 मानवाधिकार परिषद, यूरोपीय केंद्र फॉर लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान, 28 फरवरी 2024
273 द वायर मानवाधिकार समूह: 2024 में भारत में ईसाइयों पर 834 हमले, 10 जनवरी 2025
274 द वायर, 2024 में भारत में ईसाइयों पर 834 हमले, 10 जनवरी 2025
275 USCIRF, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते दुर्व्यवहार, अक्टूबर 2024
276 यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज़, उत्तरी भारतीय राज्य में 13 ईसाइयों को जेल, 26 जून 2024
277 ईएफई 'प्रति दिन दो हमले': भारत ईसाइयों के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक क्यों है, 14 दिसंबर 2023
278 OHCHR, भारत: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने मणिपुर में जारी दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त की, 04 सितंबर 2023

HRCttee ने "धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बहुत उच्च स्तर, जैसे कि मई 2023 से मणिपुर में घटनाएं और 2002 में गुजरात में दंगे, और परिणामी न्यायेतर हत्याओं सहित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही की कमी" के बारे में अपनी चिंता नोट की।[279]

विशिष्ट क्षेत्रों में यातना

ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से, भारत के कुछ क्षेत्र सुरक्षा और सशस्त्र बलों द्वारा यातना, जबरन गायब करने और न्यायेतर हत्याओं सहित व्यवस्थित और व्यापक हिंसा से काफी प्रभावित हुए हैं, अक्सर उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने की आड़ में। इस तरह के उल्लंघनों को सही ठहराने में, भारतीय अधिकारी आमतौर पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) और UAPA पर भरोसा करते हैं, जिन्हें आपातकालीन उपाय माना जा सकता है, लेकिन जो आपातकाल की आधिकारिक घोषणा के बिना होते हैं और लंबी अवधि तक बने रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों को राज्यपाल द्वारा AFSPA ढांचे के तहत "अशांत" क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसने अंतरराष्ट्रीय क़ानून के उल्लंघन के रूप में मानवाधिकार समिति (HRCttee) की गंभीर चिंता को जन्म दिया है।[280] तथाकथित 'अशांत क्षेत्रों' में असम, नागालैंड और मणिपुर के पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र सहित राज्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह खंड उन क्षेत्रों के उदाहरणों की जांच करता है जो भारतीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों द्वारा तीव्र हिंसा, मुख्य रूप से यातना, न्यायेतर हत्याएं और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं।

छत्तीसगढ़: आदिवासियों के खिलाफ हिंसा

जैसा कि पिछले खंड में बताया गया है, अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) भेदभाव से अनुपातहीन रूप से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण और औद्योगीकरण के कारण भूमि की जब्ती और विस्थापन के प्रति आदिवासी प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है - एक ऐसा संदर्भ जिसने दशकों लंबी अशांति को हवा दी है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सशस्त्र विद्रोह भी शामिल है, जिसे आमतौर पर "माओवादी" कहा जाता है।[281] इस संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नागरिक आबादी को व्यवस्थित हिंसा का सामना करना पड़ा है, जिसमें न्यायेतर हत्याएं, सामूहिक बलात्कार, आगजनी और बड़े पैमाने पर विस्थापन शामिल हैं।[282]

2025 के पहले तीन महीनों में, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर 140 लोग मारे गए।[283] अप्रैल 2023 में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में ड्रोन हमलों के साथ हवाई बमबारी के बाद, यूके के सांसदों, मानवाधिकार संगठनों और शिक्षाविदों ने कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा बस्तर की आदिवासी आबादी पर किए गए "आतंक" की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया।[284]

इसी तरह, रिपोर्टों से पता चलता है कि 2024 के पहले छह महीनों में ही, विद्रोह विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों द्वारा 150 लोग मारे गए। जबकि सरकार ने दावा किया कि मारे गए सभी व्यक्ति "सशस्त्र माओवादी" थे, मानवाधिकार समूह पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और स्वतंत्र पत्रकारों ने आधिकारिक संस्करण को चुनौती दी और रिपोर्ट दी कि कई पीड़ित निहत्थे नागरिक थे, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे।[285]

छत्तीसगढ़ में लोगों को अक्सर "माओवादी" होने या "माओवादियों" के लिए जिम्मेदार अपराध करने के मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर मनमानी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। 2017 में, सुकमा जिले में "माओवादी" हमले के संबंध में लगभग 121 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया और पांच साल के लिए कैद किया गया। 2022 में, सबूतों के अभाव में सभी 121 लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए हथियार उनके थे।[286]

यौन और लिंग-आधारित हिंसा भी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा दुर्व्यवहार का एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। रिपोर्टें संकेत देती हैं कि अक्टूबर 2015 और फरवरी 2016 के बीच, 50 से अधिक महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, जिसमें बस्तर क्षेत्र में सामूहिक

279 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 45
280 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 27
281 इंडिया जस्टिस प्रोजेक्ट और ECCHR, विकास के नाम पर, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी अधिकारों का उल्लंघन और सिकुड़ता स्थान, 14 अक्टूबर 2022
282 द पोलिस प्रोजेक्ट "विकास" के नाम पर वर्षों का उत्पीड़न, बस्तर में जारी मानवाधिकार उल्लंघनों की कहानी, 2 सितंबर 2021 इंडिया जस्टिस प्रोजेक्ट और EC-CHR, विकास के नाम पर, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी अधिकारों का उल्लंघन और सिकुड़ता स्थान, 14 अक्टूबर 2022
283 फ्रंटलाइन, बस्तर: हमारे हाथ खून से सने हैं, 09 अप्रैल 2025
284 छत्तीसगढ़, भारत में ड्रोन बम हमलों के खिलाफ बयान, 17 अप्रैल 2023। यह भी देखें, फ्रंटलाइन डिफेंडर्स, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में मानवाधिकार रक्षकों की गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई, कॉर्पोरेटाइजेशन और मिलिटराइजेशन के खिलाफ अभियान, 15 मई 2024
285 काउंटरकरंट्स, बस्तर में एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, गलत गिरफ्तारी और जबरन सरेंडर: मानवाधिकारों का बिना रोक-टोक उल्लंघन, 29 जून 2024
286 न्यूज़लॉन्ड्री, झूठे केस: छत्तीसगढ़ ने कैसे 121 आदिवासियों को उस जुर्म के लिए 5 साल जेल में डाला जो उन्होंने किया ही नहीं, 21 जुलाई 2022

बलात्कार की 20 घटनाएं शामिल थीं।[287] ग़ैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्टें यह भी दिखाती हैं कि भाजपा शासन के तहत छत्तीसगढ़ में भूमि की जब्ती बढ़ी है, साथ ही आदिवासी महिलाओं के खिलाफ संबंधित यौन हिंसा में भी वृद्धि हुई है।[288] फरवरी 2019 में, एक विद्रोह विरोधी अभियान में, सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर पांच महिलाओं के पैरों में गोली मारी, उनके साथ बलात्कार किया और फिर उन्हें मार डाला। उनके शव बाद में क्षत-विक्षत पाए गए, जिसमें उनके जननांग भी शामिल थे।[289] सोनी सोरी और हिड़मे मरकाम जैसी महिला मानवाधिकार रक्षक, जिन्होंने इस हिंसा को उजागर किया, उन्हें भी मनमानी गिरफ्तारी और झूठे आपराधिक आरोपों का शिकार बनाया गया। हिरासत में सोनी सोरी को भी यौन हिंसा का शिकार बनाया गया।[290]

केस स्टडी: विशिष्ट क्षेत्रों में यातना

छत्तीसगढ़ में एक महिला की यातना और मृत्यु

18 फरवरी 2021 को, छत्तीसगढ़ के गुडसे गांव की 20 वर्षीय महिला पांडे कवासी को छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने उसकी सहेली के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि पांडे के खिलाफ कभी कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया, पुलिस ने उसे "आत्मसमर्पण करने वाली माओवादी" बताया। उसे केवल 20 फरवरी को अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई, जिन्होंने उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखे, जिसमें उसकी जांघों और पीठ पर बड़े नीले निशान शामिल थे। पांडे ने अपने परिवार को बताया कि उसे और उसकी सहेली को पहले पास के जंगल में ले जाया गया, घंटों तक पेड़ से बांधा गया, और अगर उन्होंने "आत्मसमर्पण" नहीं किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्हें दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब पांडे का परिवार 23 फरवरी को पुलिस स्टेशन लौटा, तो उन्हें सूचित किया गया कि पांडे ने आत्महत्या कर ली है। उसकी मां ने पत्रकारों को बताया कि पांडे के शरीर पर शारीरिक और यौन हिंसा के स्पष्ट निशान थे। पांडे के परिवार का मानना है कि पुलिस ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी।[291]

छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी के खिलाफ व्यवस्थित उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी उन्हें चुप कराने के लिए मनमानी गिरफ्तारी और झूठे आपराधिक आरोपों का शिकार बनाया जाता है। 2017 में, नागरिक समाज समूहों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हिंसा की रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाने पर प्रकाश डाला, जिसमें यौन हिंसा भी शामिल थी।[292] मानवाधिकार रक्षकों को UAPA और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे क़ानूनों के तहत हिरासत में लिया जाता है। उन्हें यातना और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और कुछ मामलों में उन्हें अत्यधिक स्तर के एकांत कारावास में रखा जाता है — जैसे कुख्यात "अंडा सेल्स" में, जो छोटे, बंद कोश होते हैं और जिनका उद्देश्य बंदियों की गतिविधियों को सीमित करना, उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करना, और संवेदनात्मक उत्तेजना से वंचित करना होता है।[293] पत्रकार प्रशांत राही[294] और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा सहित कुछ व्यक्तियों ने ऐसी परिस्थितियों में वर्षों बिताए हैं।[295] इसके अतिरिक्त, चिकित्सा देखभाल से जानबूझकर इनकार करना अक्सर जेल अधिकारियों द्वारा सजा के रूप में उपयोग किया जाता है।

287 इंडिया जस्टिस प्रोजेक्ट और ECCHR, छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर, आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन और घटती जगह, 14 अक्टूबर 2022
288 सर्वाइवल इंटरनेशनल, प्रतिरोध के लिए क्रूरता: मोदी के भारत में स्वदेशी महिलाओं पर हमला, 2022
289 ग्राउंडजेरो, सोनी सोरी के साथ एक साक्षात्कार: बस्तर में राष्ट्रीय राजनीति और 'परिवर्तन', 25 मार्च 2019
290 फ्रंटलाइन डिफेंडर्स, सोनी सोरी, [n.d] हिड़मे मरकम [n.d] सर्वाइवल इंटरनेशनल,प्रतिरोध के लिए क्रूरता: मोदी के भारत में स्वदेशी महिलाओं पर हमला, 2022
291 फोरम अगेंस्ट मिलिटराइजेशन एंड कॉरपोरेटाइजेशन और अन्य, भारत के ICCPR समीक्षा (2024) के लिए मानवाधिकार समिति को एनजीओ प्रस्तुति, 2024, पृष्ठ 26-27
292 द वायर, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की मांग, 'बस्तर में कानून का शासन बहाल करो', 31 जनवरी 2017
293 ज्योति पुनवानी, Rediff, अंडा सेल में मेरे 7 साल एकांत कारावास का सबसे अमानवीय रूप थे, 18 मार्च 2024
294 द इंडियन एक्सप्रेस, 'यकीन था कि मैं सभी आरोपों से बरी हो जाऊंगा': जेल में एक दशक के बाद बरी, पूर्व पत्रकार भविष्य पर विचार कर रहे हैं, 28 अप्रैल 2024
295 द इंडियन एक्सप्रेस, 'गौतम नवलखा कौन हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जल्द ही गृह नज़रबंदी में रखा जाएगा?21 ,' नवंबर 2022; द इंडियन एक्सप्रेस, 'कैसे "अंडा सेल" का इस्तेमाल जेल के क़ैदियों को अनुशासित करने के लिए किया जाता है29 ,' अक्टूबर 2021

केस स्टडी: विशिष्ट क्षेत्रों में यातना

9 मई 2014 को, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. जीएन साईबाबा[296] - जो भारत में आदिवासी और दलित समुदायों की वकालत के लिए जाने जाते थे - को पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। उन्हें उनकी व्हीलचेयर से हटा दिया गया और पुलिस वैन में फेंक दिया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं।[297] प्रोफेसर साईबाबा को पांच अन्य लोगों के साथ UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया,[298] और उन पर अन्य आरोपों के अलावा "प्रतिबंधित माओवादी विद्रोही समूह के साथ सहयोग करने" का आरोप लगाया गया।[299] दस वर्षों से अधिक के कारावास के दौरान, उन्हें कथित तौर पर दुर्व्यवहार का शिकार बनाया गया, जिसमें "अंडा सेल" में एकांत कारावास भी शामिल था,[300] जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यातना की श्रेणी में आ सकता है।[301] कमर से नीचे लकवाग्रस्त होने और कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने के बावजूद, उन्हें व्हीलचेयर और पर्याप्त चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया, जिससे उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट आई।[302] 2021 में, WGAD ने उनकी हिरासत को मनमाना पाया और नोट किया कि उनके खिलाफ आरोप, जैसे "भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने" का इरादा, व्यापक और अस्पष्ट थे।[303] प्रोफेसर साईबाबा को अंततः 5 मार्च 2024 को रिहा कर दिया गया, जब एक भारतीय अदालत ने आरोपों या यहां तक कि मुकदमे की आवश्यकता को सही ठहराने के लिए "कोई ठोस सामग्री नहीं" पाई। 12 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया।[304]

2022 में, पांडु नरोटे, जिन्हें उसी मामले में हिरासत में लिया गया था, की पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के अनुसार, जेल में घोर चिकित्सा उपेक्षा के कारण 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की कोई जांच नहीं की गई।[305]

भारत-बांग्लादेश सीमा (बीएसएफ हिंसा)

भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा क्षेत्र लंबे समय से भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा हिंसा का केंद्र रहा है, जिसमें न्यायेतर हत्याएं और यातना शामिल हैं।[306] बीएसएफ, भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत एक अर्धसैनिक बल है,[307] जो भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में संचालित होता है। यह क्षेत्र मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों सहित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का घर है - ऐसे समूह जो भारत भर में प्रणालीगत भेदभाव का सामना करते हैं, जैसा कि पिछले खंडों में बताया गया है।[308] भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा-संबंधी मौतों को "शून्य"[309] तक लाने की 2022 की संयुक्त प्रतिबद्धता के बावजूद, गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं। मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि बीएसएफ ने 2013 और 2023 के बीच सालाना लगभग 30 बांग्लादेशी लोगों को मार डाला।[310] इसी अवधि के दौरान, बीएसएफ ने कथित तौर पर 500 बांग्लादेशी नागरिकों का अपहरण किया, जिनमें से 126 अभी भी लापता हैं।[311] MASUM ने बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य पश्चिम बंगाल में 2013 और 2020 के बीच यातना और हिरासत में मौत की 328 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया।[312]

296 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), डॉ. जी.एन. साईबाबा का असामयिक निधन, 14 अक्टूबर 2024
297 USCIRF, गोकाराकोंडा नागा साईबाबा, [n.d]
298 इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को 'नक्सल लिंक' के आरोप में गिरफ्तार किया गया, 10 मई 2014
299 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF), गोकाराकोंडा नागा साईबाबा, [n.d]
300 फ्रंटलाइन, जीएन साईबाबा ने 10 साल की कैद के दौरान यातना और अन्याय का खुलासा किया, 9 मार्च 2024
301 OHCHR, यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने एकांत कारावास पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, 18 अक्टूबर 2011
302 फ्रंटलाइन, जीएन साईबाबा ने 10 साल की कैद के दौरान यातना और अन्याय का खुलासा किया, 9 मार्च 2024. सिख सियासत न्यूज़, मानवाधिकार रक्षक अलर्ट: जीएन साईबाबा को हिरासत में पर्याप्त चिकित्सा उपचार से वंचित किया गया, 26 अप्रैल 2018
303 OHCHR, गोकाराकोंडा नागा साईबाबा (भारत) से संबंधित राय संख्या 21/2021, 17 जून 2021
304 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, कैद में एक दशक: न्याय प्रणाली प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा के लिए कैसे विफल रही, 14 मार्च 2024. देखें भी: एमनेस्टी इंटरनेशनल, भारत: मानवाधिकार रक्षक जी.एन. साईबाबा की पुनर्बरीअत निरंतर दमन पर न्याय की विजय है, 5 मार्च 2024
305 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, डॉ. जीएन साईबाबा का असामयिक निधन, 14 अक्टूबर 2024
306 द डिप्लोमैट, बांग्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024. HRW, भारत: कथित सीमा बल हत्याओं की जांच करें, 9 फ़रवरी 2021
307 भारत का गृह मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। देखें यह भी: OMCT, भारत-बांग्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले में तत्काल न्याय की अपील, 5 अप्रैल 2024
308 OMCT, भारत-बांग्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले में न्याय का तत्काल आह्वान, 05 अप्रैल 2024
309 ढाका ट्रिब्यून, पीएम हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत-बांग्लादेश संयुक्त बयान, 8 सितंबर 2022
310 द डिप्लोमैट, बांग्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024
311 द डिप्लोमैट, बांग्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024
312 MASUM, 3 जून 2024 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के समक्ष भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट पर उसके 141वें सत्र (3 जून 2024) में विचार हेतु प्रस्तुति

बीएसएफ न केवल सीमाओं पर व्यक्तियों को गोली मारने में शामिल रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करते हुए,[313] सीमा पार करने का प्रयास करने वाले संदिग्धों के खिलाफ पेलेट गन का भी उपयोग करता है।[314] इसके अतिरिक्त, बीएसएफ द्वारा यातना में "गोली के घाव, काटने के घाव, व्यक्तियों को पानी में डुबोने से पहले उनके हाथ-पैर बाँधना, प्लायर से नाखून निकालना, संगीन से घोंपना, कान काटना, शारीरिक पिटाई, सिगरेट से पूरे शरीर या शरीर के विशिष्ट अंगों को जलाना" जैसे कृत्य शामिल हैं।" और भी गंभीर कार्रवाइयों में जलाना, अपंग करना, जननांगों को काटना, आंखें फोड़ना, शवों को कंटीले तारों पर लटकाना और बलात्कार की घटनाएं शामिल हैं"।[315]

केस स्टडी: बीएसएफ द्वारा हिरासत में यातना

सिराजुल हक

नवंबर 2017 में, NHRC को बीएसएफ कर्मियों द्वारा सिराजुल हक की हिरासत में यातना और हत्या के बारे में शिकायत मिली। सिराजुल की पत्नी ने कहा कि सिराजुल को बांग्लादेश के साथ सीमा के पास एक दूरस्थ स्थान पर हिरासत में लिया गया था, जहां उसे पीट-पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया जिससे एनजीओ MASUM को NHRC से अपील की। जवाब में, बीएसएफ ने यह तर्क देते हुए मुआवजे के दावे से इनकार किया, कि आपराधिक कार्यवाही चल रही थी और NHRC के पास सशस्त्र बलों पर अधिकारक्षेत्र नहीं है। NHRC ने अपने निष्कर्ष को दोहराया कि यातना हुई थी, सशस्त्र बलों के अभियानों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में दी गई अभियोजन से छूट का आह्वान करने के लिए बीएसएफ की आलोचना की, और सिफारिश की कि 200,000 रुपये सिराजुल के परिजनों को मुआवजे के रूप में दिए जाएं। इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं मिला और NHRC ने मामला बंद कर दिया।[316]

केस स्टडी: भारत-बांग्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या

बसेर अली

एनजीओ MASUM ने 2024 में HRCttee को अपनी प्रस्तुतियों में बीएसएफ द्वारा सीमा पर न्यायेतर हत्याओं की 19 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। ऐसा ही एक मामला बसेर अली का है, जिसे 2019 में कालजनी नदी में नहाते समय बीएसएफ कर्मियों ने मार दिया था। MASUM के अनुसार, उस पर संभवतः गौ-तस्करी का संदेह था। नदी में, कथित तौर पर उसे बीएसएफ की नावों ने घेर लिया, जानबूझकर कुचला और गंभीर रूप से घायल छोड़ दिया। फिर बीएसएफ अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे नदी के किनारे घसीटा और करीब से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।[317]

मवेशी तस्करी के संदेह में व्यक्तियों पर फायरिंग भारत-बांग्लादेश सीमा पर हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है, जहां सैन्यीकरण और गरीबी ने स्थानीय समुदायों को अस्तित्व के साधन के रूप में तस्करी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।[318]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ द्वारा हिंसा के अन्य मामलों में 16 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के शिमोन टॉय का मामला शामिल है, जिसे 19 अप्रैल 2020 को पेट में गोली मार दी गई थी। कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब शिमोन और उसके पिता ने बीएसएफ अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया।[319]

313 द डिप्लोमैट, बांग्लादेश और भारत के बीच जानलेवा बॉर्डर, 23 फरवरी 2024। HRW, इंडिया: इन्वेस्टिगेट अलेजेड बॉर्डर फोर्स किलिंग्स, 09 फरवरी 2021 भी देखें

314 OHCHR, कानून प्रवर्तन में कम-घातक हथियारों पर मार्गदर्शन, 2020

315 बांग्लादेश के नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में इतिहास के सहायक प्रोफेसर डॉ. सालेह शाह्रियार के एक शोध पत्र के अनुसार, द डिप्लोमैट, बांग्लादेश और भारत के बीच घातक सीमा, 23 फरवरी 2024

316 NHRC, केस/फाइल नंबर 24/25/6/2018, एक्शन नंबर 11 दिनांक 27 फरवरी 2020

317 MASUM, 3 जून 2024 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के समक्ष भारत की चौथी आवधिक रिपोर्ट पर उसके 141वें सत्र (3 जून 2024) में विचार हेतु प्रस्तुति

318 OMCT, भारत-बांग्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले में न्याय का तत्काल आह्वान, 05 अप्रैल 2024

319 HRW, भारत: कथित सीमा बल हत्याओं की जांच करें, 9 फरवरी 2021

5 अप्रैल 2024 को 'वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर' (OMCT) ने नोट किया, "वर्षों से बीएसएफ, एक अर्धसैनिक बल के रूप में काम करते हुए, भारत-बांग्लादेश सीमा पर आतंक का राज चला रहा है, सीमावर्ती समुदायों को दंडमुक्ति के साथ यातना, न्यायेतर हत्याओं और उत्पीड़न के अधीन कर रहा है"।[320]

जम्मू और कश्मीर (AFSPA-सक्षम हिंसा)

जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान की सीमा पर है और लंबे समय से दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों और सशस्त्र संघर्ष का केंद्र रहा है।[321] 1947 से, इस क्षेत्र को भारतीय संविधान के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, जिससे इसे अपने आंतरिक मामलों के प्रबंधन में स्वायत्तता के महत्वपूर्ण स्तर की अनुमति मिली थी।[322]

हालांकि, 2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इस विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और क्षेत्र को प्रत्यक्ष और केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया — यह कदम 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य किया गया।[323] इस निर्णय के बाद, क्षेत्र में नागरिक समाज, मानवाधिकार रक्षकों और मीडिया पर भारतीय सरकार की कार्रवाई तेज़ हो गई, विशेष रूप से UAPA जैसे आतंकवाद विरोधी क़ानूनों के उपयोग के माध्यम से।[324] इस अवधि में जम्मू और कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग का भी विघटन हुआ, जिसके बंद होने के समय लगभग 8,000 मामले लंबित थे।[325]

भारत का AFSPA - क्षेत्र के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद भी -जम्मू और कश्मीर में लागू है, और सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है जिसने गैर-अपमानजनक मानवाधिकारों के उल्लंघन को सुगम बनाया है।[326] क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन में योगदान देने वाले अन्य कानूनों में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम शामिल है, जिसके तहत नाबालिगों को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है।[327] AFSPA के ढांचे को इस रिपोर्ट के अगले भाग में अधिक विस्तार से संबोधित किया गया है, पर कानून के तहत सुरक्षा बलों को दी गई व्यापक शक्तियों के कारण न्यायेतर हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां, और यातनाएं पूरी तरह से दंडमुक्ति के साथ की गई हैं।[328] कथित तौर पर 2018 से 2023 तक नागरिकों की मौतों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है।[329] जम्मू और कश्मीर पर काम करने वाले मानवाधिकार संगठनों ने क्षेत्र में 1990 और 2019 के बीच हिरासत में यातना के 432 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है।[330] इन पीड़ितों में से 70% नागरिक थे और 11% की यातना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई।[331]

सुरक्षा बलों द्वारा की गई यातना के रूपों में वॉटर-बोर्डिंग, बिजली के झटके, यौन यातना, जलाना और डंडों, केबलों और चमड़े के बेल्ट से पीटना शामिल है।[332] हिंसा का एक और रूप जो संभवतः जम्मू और कश्मीर में यातना के बराबर है, वह सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए धातु के छर्रे दागने के लिए शॉटगन का उपयोग है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर चोटें आती हैं।[333] जम्मू और कश्मीर में स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की 2019 की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2016 के मध्य और 2018 के अंत के बीच धातु के छर्रों से 1,253 लोग अंधे हो गए थे।[334] 2016 में, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुरक्षा बलों द्वारा छर्रों के उपयोग के परिणामस्वरूप 10,000 से अधिक चोटों और 80 मौतों के बाद छर्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करते हुए एक मामला दायर किया।[335] परन्तु उच्च न्यायालय ने पेलेट गन पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया।[336]

320 OMCT, भारत-बांग्लादेश सीमा पर न्यायेतर हत्या: लिटन मिया के मामले में न्याय का तत्काल आह्वान, 05 अप्रैल 2024
321 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, 29 अप्रैल 2024
322 BBC, अनुच्छेद 370: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को बरकरार रखा, 11 दिसंबर 2023
323 BBC, अनुच्छेद 370: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को बरकरार रखा, 11 दिसंबर 2023
324 AI, हमें कानून द्वारा दंडित किया जा रहा है, 2 सितंबर 2022, पृष्ठ 21. इंटरनेशनल फ़ेडरेशन फ़ॉर ह्यूमन राइट्स, भारत: कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक खुर्म परवेज की मनमानी हिरासत के तीन वर्ष, 21 नवंबर 2024
325 AI, हमें कानून द्वारा दंडित किया जा रहा है, 2 सितंबर 2022, पृष्ठ 25; 326. AI, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 पर भारत ब्रीफिंग, 8 मई 2005
326 AI, आर्म्ड फ़ोर्सेज़ (स्पेशल पॉवर्स) एक्ट 1958 पर भारत ब्रीफ़िंग, 8 मई 2005
327 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ ज्यूरीस्ट्स, जम्मू और कश्मीर में गलत हिरासतें बंद करें, 15 अक्टूबर 2016
328 HRW, भारत, 2020 की घटनाएं
329 द न्यूयॉर्क टाइम्स, कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ यातना के आरोपों की जांच की मांग की, 6 जुलाई 2019
330 जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019
331 जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019
332 जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019. द वॉशिंगटन पोस्ट, जिस रात सैनिक आए: कश्मीर में उत्पीड़न के आरोप सामने आए, 30 सितंबर 2019
333 HRW, भारत: कश्मीर में पैलेट-फायरिंग शॉटगन का उपयोग बंद करें, 4 सितंबर 2020
334 OHCHR, भारत-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति का अद्यतन, 8 जुलाई 2019
335 द वायर, मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त, पैलेट गन के निरंतर उपयोग ने राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और चिकित्सा पेशेवरों पर अत्यधिक दबाव डाला है, 29 मार्च 2017; LSE ब्लॉग, कश्मीर में पैलेट गनों के अवैध उपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन: विभिन्न दृष्टिकोण और चुनौतियाँ, 16 जून 2022
336 द वायर, मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त, पैलेट गन के निरंतर उपयोग ने राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और चिकित्सा पेशेवरों पर अत्यधिक दबाव डाला है, 29 मार्च 2017

हालांकि भारत सरकार का कहना है कि पेलेट गन गैर-घातक हैं, ओमेगा फाउंडेशन, एक संगठन जो यातना की माला वाले सुरक्षा बलों के हनन के विश्लेषण में विशिष्ट है, ने निष्कर्ष निकाला है कि गंभीर चोट या मृत्यु के उच्च जोखिम को देखते हुए, ऐसे हथियारों को घातक बल का एक रूप माना जाना चाहिए और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।[337] यह स्थिति लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा समर्थित है। आज तक, जम्मू और कश्मीर में यातना, हत्याओं और अन्य उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं।[338]

केस स्टडी: जम्मू और कश्मीर

रिजवान पंडित की यातना और मृत्यु

29 वर्षीय स्कूल शिक्षक रिजवान पंडित को मार्च 2019 में अवंतीपोरा गांव में उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रिजवान के भाई ने कहा कि गिरफ्तारी के समय, पुलिस ने उसके परिवार को आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।[339] जबकि पुलिस ने दावा किया कि रिजवान एक आतंकवादी हमले में शामिल था, उसके भाई ने इन आरोपों से इनकार किया, कि रिजवान का ऐसे किसी भी अपराध में कोई हाथ नहीं था।[340] गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद हिरासत में रिजवान की मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि उसकी मृत्यु जलने के निशान और यातना के अन्य संकेतों सहित कई चोटों के कारण खून की कमी से हुई थी।[341] पुलिस ने घटना की जांच करने का वादा किया, लेकिन आज तक, शामिल अधिकारियों के निलंबन या अभियोजन की कोई खबर नहीं है।

केस स्टडी: जम्मू और कश्मीर

कश्मीरी नागरिकों की यातना और मृत्यु

अगस्त 2024 में, एक विद्रोही हमले के बाद जिसमें चार भारतीय सेना के जवान मारे गए थे, सेना ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में आठ कश्मीरी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद शौकत (22), सफीर हुसैन (45), और शब्बीर अहमद (32) शामिल थे, जिनकी संभवतः यातना के परिणामस्वरूप, हिरासत में मृत्यु हो गई, जैसा कि उनके शरीर के निशानों से पता चलता है।[342] शेष पांच बंदियों को हिरासत में लगी चोटों के कारण उनकी रिहाई के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायलों में से एक की बेटी के अनुसार, बंदियों को बिजली के झटके दिए गए और उनके निजी अंगों में मिर्च पाउडर डाला गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में सेना के जवानों को जमीन पर लेटे नागरिकों के निजी अंगों पर मिर्च पाउडर छिड़कते हुए दिखाया गया।[343] इसके बाद, भारत सरकार ने मृतकों के परिवारों को नौकरी और मौद्रिक मुआवजे की पेशकश की, जिसे रिश्तेदारों के अपमान के रूप में माना गया, जो हत्याओं के लिए न्याय की मांग जारी रखे हुए हैं।[344]

मणिपुर में राज्य हिंसा

भारत का पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र, विशेष रूप से मणिपुर, विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के बीच दशकों पुराने अंतर-सांप्रदायिक तनाव से चिह्नित है, जो राज्य हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है।[345] मणिपुर विभिन्न प्रकार के जातीय समूहों का घर है, जिसमें मैतेई - मुख्य रूप से हिंदू -, और कुकी और नागा - मुख्य रूप से ईसाई - प्रमुख जातीय समूहों के रूप में हैं।[346] 'भारत-बांग्लादेश सीमा (बीएसएफ हिंसा)' खंड में ऊपर बताए गए संदर्भ

337 ओमेगा रिसर्च फाउंडेशन, ओमेगा रिसर्च फ़ाउंडेशन द्वारा प्रस्तुति: सभाओं, जिनमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी शामिल हैं, के संदर्भ में कम-घातक हथियारों और गोला-बारूद प्रौद्योगिकी के उपयोग के मानवाधिकारों पर प्रभाव के संबंध में, अक्टूबर 2019
338 OHCHR, कानून प्रवर्तन में कम-घातक हथियारों पर मार्गदर्शन, 2020
339 अल जज़ीरा, पुलिस हिरासत में शिक्षक की मौत के बाद कश्मीर में झड़पें, 19 मार्च 2019
340 अल जज़ीरा, पुलिस हिरासत में शिक्षक की मौत के बाद कश्मीर में झड़पें, 19 मार्च 2019
341 OHCHR, भारत-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति का अद्यतन, 8 जुलाई 2019 पृष्ठ 28
342 अल जज़ीरा, भारतीय सेना पर हिरासत में नागरिकों की हत्या का आरोप लगाने के बाद कश्मीर में गुस्सा, 24 दिसंबर 2023
343 अल जज़ीरा, भारतीय सेना पर हिरासत में नागरिकों की हत्या का आरोप लगाने के बाद कश्मीर में गुस्सा, 24 दिसंबर 2023
344 अल जज़ीरा, भारतीय सेना पर हिरासत में नागरिकों की हत्या का आरोप लगाने के बाद कश्मीर में गुस्सा, 24 दिसंबर 2023
345 BBC मणिपुर हिंसा: क्या हो रहा है और क्यों, 20 जुलाई 2023
346 AI, भारत: अधिकारियों को मानवाधिकारों को बनाए रखना चाहिए और बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में हिंसा को समाप्त करना चाहिए, 11 फरवरी 2025

के समान, भारतीय सुरक्षा बलों ने AFSPA[347] के तहत कार्य करते हुए दंडमुक्ति के साथ व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं।मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडमुक्ति दशकों तक बनी रही और उल्लंघनों की जांच सीमित रही है, विशेष रूप से NHRC को कभी-कभी मणिपुर में बंदियों से मिलने से प्रतिबंधित किया गया है।[348]

2012 में, एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल एक्ज़िक्यूशन विक्टिम फ़ैमिलीज़ एसोसिएशन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला दायर किया, जिसमें 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में सेना, अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से की गई 1,528 फ़र्ज़ी मुठभेड़/अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं के मामलों को उठाया गया।[349] जुलाई 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक को न्यायेतर हत्याओं के कम से कम 85 मामलों की जांच करने का आदेश दिया, और माना कि मणिपुर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती क्योंकि उसके अपने कर्मी कथित रूप से कुछ मामलों में शामिल थे।[350] हालांकि सीबीआई ने न्यायेतर हत्याओं के मामलों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन प्रगति में लगातार देरी हुई है — जिसमें एक कारण 2018 में 356 सुरक्षा और सेना अधिकारियों द्वारा दायर वह याचिका भी है, जिसमें इन जाँचों को चुनौती दी गई थी।[351] इस बीच, पीड़ितों के परिवारों को उत्पीड़न और प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है।[352] 2019 में, यह बताया गया कि सीबीआई को अभी भी सरकार से "अभियोजन स्वीकृति" प्राप्त नहीं हुई थी, जो लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय कानून के तहत एक कानूनी शर्त है (रिपोर्ट का अगला भाग देखें)।[353]

मई 2023 में, मैतेई और कुकी सहित विभिन्न जातीय समूहों के बीच हिंसा के परिणामस्वरूप घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को जला दिया गया और नष्ट कर दिया गया, और फरवरी 2025 तक 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए।[354] नवंबर 2024 तक, 258 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से लगभग दो-तिहाई कुकी थे।[355]

2023 में, ऐसी खबरें सामने आईं कि सामूहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके खिलाफ भीड़ की हिंसा देखी लेकिन हस्तक्षेप करने में विफल रहे।[356] जब पीड़ितों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।[357] भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तब से राज्य सरकार से शिकायतों को दर्ज करने और जांच करने में पुलिस की विफलता की व्याख्या करने का अनुरोध किया है। इसने मणिपुर पुलिस को हिंसा शुरू होने के बाद से दर्ज यौन हिंसा सहित 6,000 से अधिक हिंसा के मामलों के जवाब में की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड प्रदान करने का भी आदेश दिया।[358]

इस क्षेत्र में हुई हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप, 2023 में संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से "सभी आयु वर्ग की सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाली लैंगिक-आधारित हिंसा, जो मुख्यतः कुकी जातीय अल्पसंख्यक की थीं," के संबंध में।[359] उन्होंने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और दमन के कृत्यों को सही ठहराने के लिए आतंकवाद विरोधी उपायों के दुरुपयोग के बारे में भी चिंता जताई है।[360]

347 OMCT, मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं पर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के मामले का अनुपालन किया जाना चाहिए, 26 सितंबर 2018
348 अमेरिकी विदेश विभाग, भारत में मानवाधिकारों पर 2016 की रिपोर्ट, 2016, पृष्ठ 4. NHRC ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सुश्री इरोम शर्मिला तक पहुँच पर लगाए गए मनमाने प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की मांग की गई है, 30 अक्टूबर 2013
349 HRW, भारत: शीर्ष अदालत ने मणिपुर हत्या जांच का आदेश दिया, 15 जुलाई 2017
350 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स भारत: अधिकारियों को मणिपुर हत्याओं की पूरी जांच करनी चाहिए, 30 जुलाई 2017
351 OMCT, मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं पर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के मामले का अनुपालन किया जाना चाहिए, 26 सितंबर 2018
352 OMCT, मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं पर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के मामले का अनुपालन किया जाना चाहिए, 26 सितंबर 2018
353 OMCT, भारत: मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच में नई देरी और पीड़ित परिवारों के खिलाफ प्रतिशोध, 31 जनवरी 2019
354 AI, भारत: अधिकारियों को मानवाधिकारों को बनाए रखना चाहिए और बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में हिंसा को समाप्त करना चाहिए, 11 फरवरी 2025
355 BBC, मणिपुर हिंसा: क्या हो रहा है और क्यों, 20 जुलाई 2023. देखें साथ ही, दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, "मणिपुर में 90 और CAPF जवानों की तैनाती; जातीय हिंसा में कुल मौतों की संख्या 258 पहुँची: राज्य सुरक्षा सलाहकार, 22 नवंबर 2024 साथ ही देखें HRW,"भारत: मणिपुर राज्य में नवीनीकृत जातीय हिंसा," 14 सितंबर 2024
356 द गार्जियन, मणिपुर में महिलाओं पर यौन हमले का वीडियो सामने आने के बाद मोदी बोले, 20 जुलाई 2023
357 BBC, नग्न हमले के वीडियो वाली मणिपुर की महिलाएं 'हार नहीं मानेंगी', 10 नवंबर 2023
358 BBC, मणिपुर: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वायरल हमले के वीडियो में महिलाओं की याचिका सुनी, 31 जुलाई 2023
359 OHCHR, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ: मणिपुर, 4 सितंबर 2023
360 OHCHR, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ: मणिपुर, 4 सितंबर 2023

यातना को वैध बनाना: राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

© Reuters/P Ravikumar

भारत के नए नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ 2020 में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड के पीछे तैनात दंगा-रोधी पुलिस बल। भारत में शांतिपूर्ण सभाओं पर की गई पुलिसिंग में बल के अत्यधिक उपयोग का दस्तावेज़ीकरण किया गया है, जहाँ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीक़े से तितर-बितर किया और उन्हें डराया-धमकाया।

यातना-निरोधक मानकों का प्रभावी रूप से घरेलू क़ानूनों में समावेश और उनका व्यावहारिक प्रवर्तन, यातना और अन्य दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक मज़बूत क़ानूनी ढांचा न केवल अत्याचारों को रोकता है, बल्कि जवाबदेही और पीड़ितों को प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए आधार भी प्रदान करता है।

भारत ने अब तक UNCAT की पुष्टि नहीं की है, स्वतंत्र यातना-विरोधी क़ानून का अभाव है, मौजूदा क़ानूनों में यातना को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, और स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बल के उपयोग — जिसमें विरोध प्रदर्शनों की पुलिसिंग भी शामिल है — को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त रूप से विनियमित करने वाले कोई भी क़ानून या दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं। अंततः, आतंकवाद-रोधी क़ानूनों का बार-बार उपयोग असहमति को दबाने और अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करने के लिए किया जाता है। इन क़ानूनी खामियों के कारण एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें यातना जारी रहती है। यह खंड भारत के क़ानूनी ढांचे की उन प्रमुख कमियों की पड़ताल करता है जो राज्य द्वारा व्यापक रूप से यातना के उपयोग में योगदान देती हैं।

UNCAT की पुष्टि करने और यातना को अपराध घोषित करने में विफलता

1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर करने के बाद से अंतरराष्ट्रीय निकायों और राज्यों के बार-बार आह्वान के बावजूद, भारत ने अभी तक संधि की पुष्टि नहीं की है।[361] जुलाई 2024 में, HRCttee ने ऐसा करने में भारत की निरंतर विफलता पर खेद व्यक्त किया[362] और नवंबर 2022 में भारत के चौथे UPR के दौरान, 31 राज्यों ने UNCAT की पुष्टि की सिफारिश की।[363]फिर भी, भारत उन 21 देशों में से एक बना हुआ है जिन्होंने संधि की पुष्टि नहीं की है।

UNCAT की पुष्टि किए बिना भी, भारत यातना के पूर्ण निषेध से बंधा हुआ है। यह निषेध प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य मानदंड है, जिसका अर्थ है कि संधि की पुष्टि की परवाह किए बिना यह राज्यों पर बाध्यकारी है।[364] यह निषेध अपमानजनक नहीं है और इसे युद्ध, युद्ध के खतरे, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, या किसी अन्य सार्वजनिक आपातकाल सहित किसी भी असाधारण परिस्थिति के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है।[365]

UNCAT से परे, यातना का निषेध नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR) सहित कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है, जिसकी पुष्टि भारत ने की है। हालांकि, भारत ने ICCPR की पुष्टि करते समय प्रमुख आपत्तियाँ दर्ज की, जिससे HRCttee - संधि की निगरानी संस्था - को व्यक्तिगत शिकायतों, पूछताछ, या मानवाधिकार उल्लंघनों के संबंध में अंतरराज्यीय संचार पर विचार करने से रोका गया।[366] घरेलू जवाबदेही के रास्तों की अपर्याप्तता को देखते हुए, ये आपत्तियाँ पीड़ितों और जीवित बचे लोगों की न्याय तक पहुंच को काफी सीमित करते हैं। भारत ने UNCAT पर हस्ताक्षर करते समय भी इसी तरह की व्यक्त की थीं[367], जिसके बारे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह भविष्य के अनुसमर्थन के प्रभाव को सीमित करेगा।[368]

UNCAT की पुष्टि करने के लिए UPR की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत होने के बावजूद, भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है, और अपनी देरी को सही ठहराने का बार-बार प्रयास किया है। अगस्त 2022 में, भारत ने दावा किया कि:

> भारत का विधि आयोग अनुसमर्थन प्रक्रिया को पूरा करने से पहले घरेलू कानून में आवश्यक परिवर्तनों की जांच कर रहा है। हालांकि, मौजूदा कानूनी ढांचा, जैसे कि भारत के संविधान, भारतीय दंड संहिता, और दंड प्रक्रिया संहिता सहित अन्य के प्रावधान, किसी भी प्रकार की यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा की गारंटी देते हैं।[369]

ये औचित्य निराधार प्रतीत होते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में प्रलेखित उल्लंघन प्रदर्शित करते हैं, मौजूदा ढांचे और उनके प्रवर्तन की कमी यातना को रोकने और उसका जवाब देने में अपर्याप्त या अनुपयुक्त साबित हुई है। इसके बजाय, सरकार की अनिच्छा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जो संभवतः अंतरराष्ट्रीय जांच के प्रति उसके व्यापक प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। यह न केवल ICCPR के प्रति उसके आपत्तियों में बल्कि स्वतंत्र जांच की अनुमति देने से उसके लंबे समय से इनकार में भी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, यातना पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने पहली बार 1999 में देश के दौरे का अनुरोध किया था और तब से कम से कम आठ फॉलो-अप अनुरोध भेजे हैं - फिर भी भारत

361 HRC, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, 17 जुलाई 2017 पैरा 33, 161.5-29, and 161.74

362 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024

363 HRC, भारत का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, चौथा चक्र: सिफारिशों का मैट्रिक्स, [n.d]. लीफलेट, भारत द्वारा मानवता के खिलाफ या यातना निषेध कन्वेंशन (UNCAT) को अनुमोदित करने से लगातार इनकार करना तर्कहीन है, 21 नवंबर 2022। देखें: OHCHR, UPR के चौथे चक्र के परिणाम के प्रकाश में टिप्पणियाँ, 17 जुलाई 2023, जिसमें 2017 की UPR में 30 राज्यों ने भारत को UNCAT अनुमोदन की सिफारिश की थी। देखें HRW, भारत: प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सिफारिशों की अनदेखी, 21 सितंबर 2017

364 यातना पर विशेष प्रतिवेदक (SRT), जुआन ई. मेंडेज़ ने 2014 में 'क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार 'की अनिवार्य स्थिति को स्वीकार किया था (देखें: UNHRC, विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट – यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर, जुआन ई. मेंडेज़ – घाना मिशन (रिपोर्ट ऑफ़ द SRT ऑन मिशन टू घाना), 5 मार्च 2014, UN Doc. A/HRC/25/60/Add.1, पैरा 40)। इस स्थिति को इंटर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है (देखें: लोरी बेरेंसन-मेहिया बनाम पेरू, केस नंबर 119, 25 नवंबर 2004, पैरा 100) और न्यायालय की न्यायशास्त्र पर टिप्पणी में भी (देखें: असोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर (APT) और सेंटर फॉर जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ (CEJIL), टॉर्चर इन इंटरनेशनल लॉ: ए गाइड टू ज्यूरिसप्रूडेंस, 2008, पृ. 113)

365 UNCAT, अनुच्छेद 2.2; CAT, सामान्य टिप्पणी संख्या 2, 24 जनवरी 2008, पैरा 3. RIG, पैरा 9 और 11। देखें HRCttee, सामान्य टिप्पणी 20: अनुच्छेद 7 (यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का निषेध) (सामान्य टिप्पणी 20), 10 मार्च 1992, पैरा 3

366 संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय डेटाबेस: भारत की अनुसमर्थन स्थिति, 5 दिसंबर 2024 को एक्सेस किया गया

367 भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार्यान्वयन, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 4

368 नित्या रामकृष्णन, हिरासत में: कानून, दंडमुक्ति और दक्षिण एशिया में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, 10 अप्रैल 2019, अध्याय 2

369 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद के प्रस्तावों के अनुसरण में प्रस्तुत भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट, 17 अगस्त 2022, पैरा 54

सरकार की ओर से प्रतिक्रिया अभी भी लंबित है।[370] मई 2025 तक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा कुल 18 लंबित यात्रा अनुरोध हैं, जिन पर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।[371]

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी यातना को अपराध घोषित करने वाले घरेलू कानून को पारित करने में विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 2010 में 'यातना निवारण विधेयक' के साथ आया था। विधेयक को 26 अप्रैल 2010 को भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में इसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजा गया, जहां अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का समर्थन किया।[372] इसके बाद इसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया, जिसने कई संशोधनों का प्रस्ताव रखा।[373] हालांकि, अंततः अपने कार्यकाल के अंत में लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया।[374]

2017 में, एक और प्रयास किया गया जब एक निजी सदस्य विधेयक - जो कि यातना निवारण विधेयक भी था - संसद में पेश किया गया।[375] हालांकि, यह सरकार का समर्थन हासिल करने में विफल रहा और इसे अधिनियमित नहीं किया गया।[376]

यातना विरोधी कानून पारित करने में बार-बार की विफलता को इस दावे से उचित ठहराया गया है कि भारत के मौजूदा कानून पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सरकार ने एक अलग कानून की अनावश्यकता के प्रमाण के रूप में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और संवैधानिक सुरक्षा के प्रावधानों की ओर इशारा किया है।[377]

2023 में, औपनिवेशिक युग के अधिनियमों को बदलने के लिए भारत में तीन नए आपराधिक कानून बनाए गए, जो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव को चिह्नित करते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) को भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अधिनियमित किया गया था; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया।

हालाँकि, ये सुधार भी यातना को एक स्वतंत्र अपराध बनाने में विफल रहे। BSA की साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) के समान बने रहने के लिए आलोचना की गई है, और BNS की लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहने और अन्य गंभीर कमियों के लिए आलोचना हुई है।[378] उदाहरण के लिए, जबकि "राजद्रोह" के औपनिवेशिक अपराध को हटा दिया गया है, BNS में संबंधित प्रावधान ने एक अलग नाम से राजद्रोह का एक नया, व्यापक अपराध बनाया है: "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में

370 OHCHR, 1998 से मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं के देश के दौरे देखें, [n.d]. देखें: भारत, 6 दिसंबर 2024 तक

371 OHCHR, मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं (Special Procedures) के देश के दौरे, [n.d]

372 राज्यसभा चयन समिति, समिति रिपोर्ट यातना निवारण विधेयक 2010, दिसंबर 2010, पृष्ठ iv

373 चयन समिति ने कई प्रावधानों की पहचान की जो UNCAT मानकों को पूरा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, विधेयक ने यातना के उद्देश्य को केवल 'स्वीकारोक्ति प्राप्त करने 'तक सीमित कर परिभाषित किया, जबकि दंड, दबाव, डराने-धमकाने या भेदभाव जैसे अन्य उद्देश्य को नजरअंदाज किया। इसके अलावा, इसने जवाबदेही पर प्रक्रियात्मक बाधाएँ लगाईं, जिसके तहत अपराधियों पर मुकदमा चलाने से पहले 'संबंधित प्राधिकरण '(राज्य या केंद्र सरकार) की पूर्व अनुमति आवश्यक थी और शिकायत दर्ज करने की समयसीमा केवल छह महीने तक सीमित कर दी गई। जबकि चयन समिति ने संशोधनों की सिफारिश की, राष्ट्रीय विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर अभी भी चिंतित थे कि महत्वपूर्ण अंतराल और कमी को संबोधित नहीं किया गया। देखें: नित्या रामाकृष्णन, इन कस्टडी: लॉ, इम्प्युनिटी एंड प्रिज़नर एब्यूज़ इन साउथ एशिया, 2013, पृ. 62

374 NHRC, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, 2019, पृष्ठ 40-41

375 हालांकि इस विधेयक ने यातना की परिभाषा का विस्तार किया और दंड, डराने-धमकाने या दबाव को यातना के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इसने भेदभावपूर्ण यातना को मान्यता नहीं दी और अन्य मुद्दों को संबोधित नहीं किया, जैसे अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता और मामलों की रिपोर्ट करने की छह महीने की समयसीमा। देखें: भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार्यान्वयन, अक्टूबर 2017

376 यातना को अपराध मानने के अन्य कम प्रमुख प्रयास भी असफल रहे हैं, जिनमें 2018 में Prevention of Torture Bill का पुनः प्रस्तुत करना, 2020 में आपराधिक संहिता में संशोधन के प्रस्ताव, और 2021 में Prevention of Torture and Atrocities (By Public Servants) Bill शामिल हैं, जिनकी प्रगति पर कोई अपडेट नहीं है। एक और छूटी हुई संभावना पुराने विधायी ढांचे के रूप में थी, जो औपनिवेशिक काल से आपराधिक कानून और प्रक्रिया में लागू था। देखें: NHRC, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, [n.d], [4.9-4.14] पर; नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, भारतीय दंड संहिता में यातना के अपराधों को जोड़ने की अनिवार्यता, 18 अगस्त 2020. द पोलिस प्रोजेक्ट, ज्यूडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इन केसिस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया (2015-2016), 2022; नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, भारतीय न्याय संहिता: डिकोलोनाइजिंग ऑर रिइंफोर्सिंग कॉलोनियल आइडियाज, 25 जनवरी 2024. एक पूर्व असफल प्रयास में राष्ट्रीय आयोग द्वारा संविधान के कार्यपद्धति की समीक्षा के लिए सिफारिशें शामिल थीं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 में संशोधन कर यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर एक खंड शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। देखें:डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, रिपोर्ट ऑफ़ द नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ़ द कॉन्स्टीट्यूशन, वॉल्यूम I, चैप्टर 3: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, पैरा 3.9

377 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कार्य समूह ऑन द यूनिवर्सल पिरियॉडिक रिव्यू, भारत राष्ट्रीय रिपोर्ट जो मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 5/1 और 16/21 के अनुसार प्रस्तुत की गई, इकतालीसवीं सत्र, 17 अगस्त 2022, A/HRC/WG.6/IND/1, पैरा 54

378 पीयूसीएल, एक वास्तविक पुलिस शासन को एक कानूनी पुलिस राज्य में बदलना: 3 नए आपराधिक कानूनों की आलोचना, 11 जुलाई 2024

डालने वाला कार्य" ।[379] इससे उन कृत्यों के लिए असहमति जताने वालों का अपराधीकरण हुआ है "जो अन्यथा अपने आप में गैर-आपराधिक कृत्य हो सकते हैं" ।[380] जैसा कि अगले भाग में बताया गया है, BNSS के संबंध में भी चिंताएं उठाई गई हैं।[381]

जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यातना के कृत्य जीवन और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करते हैं,[382] इसके घरेलू ढांचे में यातना के लिए एक विशिष्ट आपराधिक अपराध का अभाव है। यातना की श्रेणी में आने वाले कुछ कृत्यों पर BNS में अन्य सामान्य अपराधों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे:

- कबूलनामा वसूलने या संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना;[383]
- कबूलनामा वसूलने के लिए गलत तरीके से कैद करना;[384] और
- महिलाओं के खिलाफ "क्रूरता" (केवल तभी जब महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा की गई हो)।[385]

अन्य कृत्यों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम (2015) की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ किए जाने पर कई कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान करता है।[386]

हालाँकि, भारत के कानूनी ढांचे में यातना के एक विशिष्ट आपराधिक अपराध की कमी, यातना के कृत्यों को उचित रूप से वर्गीकृत करने और उचित गंभीरता के साथ व्यवहार करने से रोकती है। अपराधीकरण की कमी का मतलब यह भी है कि यातना के मामलों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले बताया गया है। इसके अतिरिक्त, "चोट" और "गंभीर चोट" की परिभाषाएं अदालतों द्वारा विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुली रही हैं और असंगत रूप से लागू की गई हैं। स्पष्ट अपराधीकरण के बिना, अपराधियों को बहुत कम जवाबदेही का सामना करना पड़ता है, और जीवित बचे लोग यातना के लिए उचित क्षतिपूर्ति से वंचित रह जाते हैं, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा आवश्यक है।

इस रिपोर्ट में जांचे गए संदर्भ में, राजनीतिक प्रतिरोध ने एक भूमिका निभाई है, इस चिंता के साथ कि एक मजबूत यातना विरोधी कानून कानून प्रवर्तन और सुरक्षा बलों को अधिक जांच और जवाबदेही के दायरे में ला सकता है।[387] नतीजतन, सरकार ने यातना के व्यापक उपयोग के बढ़ते सबूतों के बावजूद, यातना को अपराध घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने से लगातार परहेज किया है।

कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता

अंतरराष्ट्रीय कानून और मानक उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं जो अपनी स्वतंत्रता से वंचित हैं, जो न्याय के प्रशासन और यातना की रोकथाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। UNCAT और प्रासंगिक टिप्पणी से पता चलता है कि हिरासत के शुरुआती घंटों और दिनों में कानूनी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करना यातना के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।[388]

भारतीय कानून, जिसमें BNSS (जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली) शामिल है, में स्वतंत्रता से वंचित लोगों के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इनमें कानूनी वकील तक पहुंच का अधिकार, पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तारी की रिकॉर्डिंग, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना पाने का

379 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 152 पहले भारतीय दंड संहिता, धारा 124A। देखें: कॉमन कॉज तीन नए आपराधिक कानून, जुलाई-सितंबर 2024. देखें: AI, भारत: अधिकारियों को तत्काल दमनकारी नए आपराधिक कानूनों को रद्द करना चाहिए, 1 जुलाई 2024

380 AI, भारत: अधिकारियों को 'अनुचित' जांच को तुरंत समाप्त करना चाहिए और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रिहा करना चाहिए, 19 मई 2025, 19 मई 2025. कॉमन कॉज तीन नए आपराधिक कानून, जुलाई-सितंबर 2024. p4

381 कॉमन कॉज, तीन नए आपराधिक कानून, जुलाई-सितंबर 2024

382 भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार्यान्वयन, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 37. देखें: सुप्रीम कोर्ट का मामला डी के बासु बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, 1997 1 SCC 416

383 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 120. पूर्व में भारतीय दंड संहिता, धारा 330-331

384 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 126-127. पूर्व में भारतीय दंड संहिता, धारा 348, 503

385 नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टार्चर भारतीय दंड संहिता में यातना के अपराध जोड़ने की अनिवार्यता, 18 अगस्त 2020, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, धारा 80, पूर्व में भारतीय दंड संहिता, धारा 498A

386 CHRI, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम,1995, जैसा कि 2015 में संशोधित किया गया: एक मार्गदर्शिका, 2018. देखें: नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टार्चर भारतीय दंड संहिता में यातना के अपराध जोड़ने की अनिवार्यता, 18 अगस्त 2020

387 द लीफलेट, उचित संदेह से परे गलत काम साबित करने की मजबूरी का अभाव सुरक्षा कानूनों की स्थायी अपील के केंद्र में है, 10 नवंबर 2022

388 UNCAT अनुच्छेद 11 CAT, कैदीयों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियमों की समीक्षा पर यातना के खिलाफ समिति के टिप्पणियाँ, 28 मार्च 2014, CAT/C/51/4

अधिकार और परिवार के सदस्य या तीसरे व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तारी पर एक स्वतंत्र चिकित्सा परीक्षा का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार शामिल है।[389]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को और विकसित किया है।[390] पिछले दशकों में हिरासत में मौत और यातना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में,सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशानिर्देश जारी किए,[391] जिसमें सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश शामिल है। जबकि समाचार रिपोर्टें संकेत देती हैं कि, नवंबर 2024 तक, भारत में कई पुलिस स्टेशनों ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं,[392] हिरासत में यातना और न्यायेतर हत्याओं के मामलों की व्यापकता - जैसा कि इस रिपोर्ट में प्रलेखित है - इस उपाय के पूर्ण कार्यान्वयन और प्रभाव पर सवाल उठाती है।

इसके अतिरिक्त, BNSS की पुलिस अधिकार का विस्तार करने, पुलिस हिरासत पर सीमाओं को कमजोर करने और जमानत के प्रावधानों को सख्त करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता कमजोर हुई है और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ सुरक्षा कम हुई है।[393] उदाहरण के लिए, BNSS अब पुलिस हिरासत को 15 दिनों तक सीमित नहीं करता है और इसे हिरासत के पहले 40 या 60 दिनों के भीतर किसी भी समय अधिकृत करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि केवल गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिनों के भीतर, जैसा कि पिछली दंड प्रक्रिया संहिता के तहत था।[394] पुलिस हिरासत में यह बदलाव "यातना और अन्य दुर्व्यवहार के लिए एक उपजाऊ प्रजनन स्थल प्रदान करता है" ।[395]

राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अस्तित्व के बावजूद, REDRESS द्वारा भारत में कई विशेषज्ञ वकीलों और शोधकर्ताओं के साथ परामर्श से पता चलता है कि कानूनी ढांचे - नए आपराधिक कानूनों सहित - और जमीन पर अभ्यास के बीच का अंतर बहुत है। उदाहरण के लिए, हालांकि एक मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि व्यक्ति की आगे की हिरासत उचित है या नहीं, व्यवहार में, यह सुरक्षा उपाय एक अतिभारित मजिस्ट्रेट प्रणाली द्वारा सारहीन कर दिया गया है जो अक्सर उनके सामने आए मामले और हिरासत दस्तावेजों की पर्याप्त जांच करने में विफल रहती है।[396]

संयुक्त राष्ट्र के निकायों और विशेषज्ञों द्वारा भी व्यवहार में ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की कमी को नोट किया गया है। 2024 में, HRCttee ने पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी पहचान बताए बिना या गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत किए बिना व्यक्तियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की।[397] इसने आपराधिक अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता तक सीमित पहुंच पर भी प्रकाश डाला, खासकर पुलिस स्टेशनों में।[398] अन्य चिंताओं में लंबी (मुक़दमे से पहले) हिरासत, महत्वपूर्ण न्यायिक देरी और लंबित मामलों का बोझ, साथ ही बंदियों के लिए चिकित्सा सेवाओं, पारिवारिक संपर्क, कानूनी वकील और - विदेशी नागरिकों के लिए - राजनयिक या कांसुलर सहायता तक अपर्याप्त पहुंच शामिल थी।[399] 2024 में, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत से गिरफ्तारी, पूछताछ और हिरासत से संबंधित अपने नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का आह्वान किया।[400]

यातना के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय कानून कानूनी कार्यवाही में यातना और दुर्व्यवहार के माध्यम से प्राप्त सबूतों को प्रतिबंधित करता है। इस बहिष्करण नियम का उद्देश्य यातना के उपयोग को हतोत्साहित करना है और इसके लगातार उद्देश्यों में से एक को कमजोर करना है: कबूलनामा निकालना।[401] भारत का BSA प्रदान करता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना पुलिस अधिकारी को

389 भारत का संविधान, अनुच्छेद 22; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 38, 47, 48, 53, 57, और 58, पूर्व में भारत की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धाराएँ 41D, 50-50A, 54

390 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, हिरासत में हिंसा की निगरानी, 14 जुलाई 2020 देखें: डी.के. बासु बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, 1997 1 SCC 416, अमिकस क्यूरी के पक्ष में दिशानिर्देशों के लिए आवेदन, डॉ. अभिषेक मनु सिंहवी, 2020, पृ. 7

391 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, हिरासत में हिंसा की निगरानी, 14 जुलाई 2020

392 टाइम्स ऑफ इंडिया, सीसीटीवी: सरकार ने जवाबदेही बढ़ाने के लिए 28 पुलिस स्टेशनों में व्यापक सीसीटीवी निगरानी शुरू की, 1 नवंबर 2024. देखें: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, डेटा के माध्यम से न्याय को आगे बढ़ाना [n.d]

393 कॉमन कॉज, तीन नए आपराधिक कानून, जुलाई-सितंबर 2024. अलजज़ीरा, भारत द्वारा औपनिवेशिक युग के कानूनों को नई आपराधिक संहिताओं से बदलने पर उठ रही चिंताएँ, 1 जुलाई 2024

394 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 187. पूर्व में भारत की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 167

395 एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI), भारत: अधिकारियों को दमनकारी नए आपराधिक कानूनों को तुरंत निरस्त करना चाहिए, 1 जुलाई 2024

396 डेक्कन हेराल्ड, 'साथनकुलम में मजिस्ट्रेट ने क्या किया?', 29 जुलाई 2020

397 HRCttee समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 35

398 HRCttee समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 35

399 HRCttee समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 39

400 OHCHR, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों का बयान, 7 मार्च 2024

401 REDRESS और फेयर ट्रायल्स, टेंटेड बाय टॉर्चर: एग्ज़ैमिनिंग द यूज़ ऑफ़ टॉर्चर एविडेन्स, मई 2018

या पुलिस हिरासत में किए गए कबूलनामे,[402] साथ ही प्रलोभन या धमकी के माध्यम से प्राप्त कबूलनामे, आपराधिक कार्यवाही में अस्वीकार्य हैं।[403] हालांकि, व्यवहार में इसका लगातार पालन नहीं किया जाता है।[404] इसके अलावा, स्वीकार्यता पर इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए अक्सर BSA की अन्य धाराओं का उपयोग किया जाता है।[405] उदाहरण के लिए, हालांकि BSA की धारा 23 पुलिस अधिकारियों को दिए गए कबूलनामे को अस्वीकार्य बनाती है, यह ऐसे कबूलनामे के परिणामस्वरूप बरामद की गई सामग्री के प्रवेश की अनुमति देती है।[406] इसने कथित तौर पर कबूलनामा निकालने के लिए यातना के उपयोग को प्रोत्साहित किया है,[407] एक ऐसा अभ्यास जिसे इस रिपोर्ट में शामिल किए गए कई प्रलेखित मामलों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

वास्तव में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में सेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी द्वारा 2017 के एक अध्ययन में मृत्युदंड और, अधिक व्यापक रूप से, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के अनुसार, "भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में यातना के प्रचलन पर चर्चा करने वाले 39 पूर्व न्यायाधीशों में से 38 का मानना था कि यह बड़े पैमाने पर है" ।[408]

सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाला कानून

जैसा कि इस रिपोर्ट के 'विशिष्ट क्षेत्रों में यातना' खंड में बताया गया है, सशस्त्र बलों को दी गई विशेष शक्तियों के शासन वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति यातना के प्रति विशेष रूप से असुरक्षित हैं।[409] AFSPA सशस्त्र बलों को राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा "अशांत" घोषित क्षेत्रों में गिरफ्तारी, तलाशी और घातक बल का उपयोग करने के व्यापक और अनियंत्रित अधिकार प्रदान करता है।[410] इसके अलावा, क्षेत्र-विशिष्ट कानून जैसे कि सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम विशिष्ट क्षेत्रों में AFSPA के प्रावधानों को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ करते हैं।[411]

'अशांत क्षेत्रों' का पदनाम व्यापक और अस्पष्ट मानदंडों का उपयोग करते हुए सरकार के विवेक पर आधारित है।[412] उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर में, "भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने" या "भारतीय ध्वज का अपमान करने"[413] के अस्पष्ट आधारों पर सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।यह अस्पष्ट भाषा गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल कर सकती है और संवैधानिक अधिकारों के व्यापक उल्लंघन का कारण बनी है। जैसा कि 'विशिष्ट क्षेत्रों में यातना' खंड में बताया गया है, AFSPA ने सशस्त्र बलों को दंडमुक्ति के साथ व्यापक हत्याएं और यातनाएं करने में सक्षम बनाया है।[414]

AFSPA के तहत, किसी भी कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी, या समकक्ष रैंक के पास समूह समारोहों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ गोलीबारी का उपयोग करने का अधिकार है।[415] कानून इन अधिकारियों को इमारतों को नष्ट करने, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने और बिना वारंट के संपत्तियों की तलाशी लेने का अधिकार भी देता है। सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम संदिग्धों को ले जाने के संदेह वाले वाहनों या जहाजों की तलाशी और जब्ती की भी अनुमति देता है।[416]

402 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, धारा 23 पूर्व में भारत साक्ष्य अधिनियम, 1872, धाराएँ 25–26
403 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, धारा 23 पूर्व में भारत साक्ष्य अधिनियम, 1872, धाराएँ 24
404 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली - सेंटर ऑन द डेथ पेनाल्टी, मैटर्स ऑफ जजमेंट, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 26-34
405 यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत लागू था और BSA के तहत भी लागू रहता है
406 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, धारा 23 पूर्व में भारत साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 27
407 आर्टिकल 14, पुलिस यातना और भारत की टूथ मशीनें, 10 अगस्त 2020; CNN, भारतीय पुलिस न्याय पाने के लिए हिंसा को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करती है — और इसका सबसे ज़्यादा भार सबसे गरीब लोग उठाते हैं, 3 दिसंबर 2020; देखें: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आपराधिक अपीलीय अधिकार-क्षेत्र, आशीष जैन बनाम मरकन्द सिंह 2019 (3) SCC 770, 14 जनवरी 2019, पैरा 21–22, जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि स्वीकारोक्ति "अनुचित दबाव और जांच अधिकारी के दबाव में दी गई हो, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो ऐसी स्वीकारोक्ति से प्राप्त होने वाली बरामदगी का साक्ष्य मूल्य शून्य हो जाता है।"
408 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली - सेंटर ऑन द डेथ पेनाल्टी, मैटर्स ऑफ जजमेंट, अक्टूबर 2017, पृष्ठ 26
409 AI, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट: भारत में मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक नया विवाद, 24 जून 2014
410 द पब्लिक स्फीयर जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA): मारने के लिए कानूनी दंडमुक्ति, 2022
411 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990
412 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990
413 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990
414 जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी (JKCCS), यातना, 20 मई 2019
415 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990, धारा 4
416 सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1990, धारा 4

दशकों से, राष्ट्रीय[417] और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों[418], राष्ट्रीय विधायी समितियों, क्षेत्रीय राजनेताओं[419], कानूनी मामलों और राष्ट्रीय मीडिया[420] ने इन शक्तियों के हानिकारक प्रभाव को उजागर करने और AFSPA को निरस्त करने की वकालत करने की मांग की है।[421] संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्रों ने भी AFSPA में संशोधन या इसे निरस्त करने की सिफारिश की है।[422] जबकि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सों में जहां इसे शुरू में लगाया गया था, वहां से कई AFSPA ढांचे पूरी तरह या आंशिक रूप से हटा दिए गए हैं, सरकार द्वारा इन आह्वानों पर पूरी तरह से विचार किया जाना बाकी है।[423] उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2024 में, सरकार ने असम के कुछ हिस्सों में AFSPA को और छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया, जहां यह 1990 से प्रभावी है।[424] नवंबर 2024 में, चल रही अंतर-सांप्रदायिक हिंसा के जवाब में केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के कुछ हिस्सों में AFSPA के आवेदन को नवीनीकृत किया गया।[425]

इस संदर्भ में, सशस्त्र बलों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जवाबदेही अत्यंत सीमित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के तहत, NHRC के पास सशस्त्र बलों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की जांच करने की सीमित शक्तियां हैं, जिससे इन दुर्व्यवहारों के दंडमुक्ति के साथ होने की संभावना और भी अधिक हो जाती है।[426] उदाहरण के लिए, 2016 में, मीडिया ने बताया कि कश्मीर के एक गाँव पर आधी रात को हुई छापेमारी के दौरान भारतीय सेना ने 32 वर्षीय लेक्चरर शब्बीर अहमद मंगू को पीट-पीट कर मार डाला, जिसमें 50 अन्य लोगों ने गंभीर चोटों की सूचना दी।[427] एक पुलिस जांच ने कथित तौर पर शामिल 23 सेना कर्मियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की। हालाँकि, ऐसे अभियोजनों के लिए पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो हमारी जानकारी के अनुसार, आज तक नहीं दी गई है।[428]

आतंकवाद विरोधी कानून

भारत का मुख्य संघीय आतंकवाद विरोधी कानून UAPA है, जिसे मूल रूप से 1967 में अधिनियमित किया गया था, और बाद में 2004, 2008, 2013 और 2019 में संशोधित किया गया।[429] UAPA के 2004 के संशोधन से पहले, आतंकवाद विरोधी प्रयास मुख्य रूप से दो कानूनों द्वारा शासित थे: आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA) 1987 और आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (POTA) 2002।[430] दोनों कानूनों की आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को सक्षम करने के लिए आलोचना की गई थी। हालाँकि अंततः उन्हें निरस्त कर दिया गया, लेकिन उनके कई समस्याग्रस्त प्रावधानों को UAPA के संशोधनों के माध्यम से फिर से पेश किया गया है।[431]

UAPA में अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक प्रावधान हैं जो हिरासत में यातना सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन को सक्षम करते हैं, शिथिल परिभाषित परिस्थितियों में मनमानी गिरफ्तारी और लंबी हिरासत की अनुमति देते हैं।[432] व्यक्तियों को "गैरकानूनी" के रूप में वर्गीकृत गतिविधियों में शामिल होने या "गैरकानूनी संबद्धता" के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। गैरकानूनी गतिविधियों में अलगाव के लिए समर्थन व्यक्त करना, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या बाधित करने या बाधित करने का इरादा रखने वाले आचरण में शामिल होना, या "जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है या पैदा करने का इरादा रखता है" शामिल हो सकता है।[433] इन प्रावधानों से दुरुपयोग होता है और इनका उपयोग संरक्षित भाषण और असहमति को अपराधी बनाने के लिए किया गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले चर्चा की गई है।

417 ई-पाओ, दिल्ली में AFSPA को निरस्त करने पर सम्मेलन आयोजित, 1 नवंबर 2015; देखें साथ ही: टाइम्स ऑफ़ इंडिया, "मणिपुर में मानवाधिकार दिवस पर AFSPA के खिलाफ प्रदर्शन," 10 दिसंबर 2024

418 इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, भारत: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को तुरंत निरस्त करें, 05 नवंबर 2015; ह्यूमन राइट्स वॉच, भारत: AFSPA को एक बेहतर, अधिकार-सम्मानजनक कानून से बदलें, 24 अगस्त 2014

419 टाइम्स ऑफ इंडिया, असम के राजनीतिक दल AFSPA को निरस्त करने की मांग में शामिल हुए, 6 दिसंबर 2021

420 द हिंदू, पूर्ण निरस्तीकरण के लिए: AFSPA पर, 4 अप्रैल 2022. साथ ही देखें, न्यूज़क्लिक, स्पष्ट किया गया: जम्मू-कश्मीर में AFSPA हटाने के कभी न खत्म होने वाले वादे, 6 अप्रैल 2024

421 HRW सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के 50 साल हत्या के साथ बचना, अगस्त 2008

422 संयुक्त राष्ट्र एचआरसी (UN HRC), यूपीआर 2022, पैरा 151.50, 151.51. HRCttee समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 28

423 फर्स्ट पोस्ट, मेघालय ने राज्य से AFSPA को हटाने के केंद्र के कदम का स्वागत किया, 24 अप्रैल 2018

424 टाइम्स ऑफ इंडिया, असम ने 'बांग्लादेश में हालिया अशांति' का हवाला देते हुए चार जिलों में AFSPA बढ़ाया, 9 अक्टूबर 2024

425 इंडियन एक्सप्रेस, गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर की स्थिति 'अस्थिर' रहने के निष्कर्ष पर 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA वापस, 15 नवंबर 2024

426 NHRC, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, धारा 19 देखें

427 NDTV, सेना की हिरासत में कथित रूप से एक व्यक्ति की मौत के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, 19 अगस्त 2016

428 द इंडियन एक्सप्रेस, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लेक्चरर की मौत के लिए 23 सेना के जवानों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी, 10 मार्च 2018

429 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, संक्षिप्त इतिहास: UAPA को चुनौतियां, 11 मई 2020

430 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, UAPA संशोधन की संवैधानिकता, अंतिम अद्यतन 28 जनवरी 2025

431 PUCL, UAPA: असहमति का अपराधीकरण और राज्य आतंक, 28 सितंबर 2022; यह भी देखें: पोलिस प्रोजेक्ट, भारत में एक आतंक-विरोधी कानून का आतंक: गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की एक संक्षिप्त कहानी, 9 फ़रवरी 2023

432 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, धारा 43 (ए), 43 (डी)

433 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 धारा 2(ओ)(iii)

प्रारंभ में, UAPA ने "गैरकानूनी गतिविधियों" से जुड़े समूहों या संगठनों को अपराधी बना दिया जो राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करते हैं, या जिन्हें "आतंकवादी संगठन" के रूप में लेबल किया गया है, व्यक्तियों पर उनकी कथित संबद्धता के आधार पर मुकदमा चलाया जाता है।[434] हालाँकि, 2019 के एक विवादास्पद संशोधन ने सरकार को व्यक्तियों - न कि केवल संगठनों - को "आतंकवादी" के रूप में नामित करने की अनुमति देकर कानून के दायरे का विस्तार किया, जिससे मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा और कम हो गई।[435]

UAPA लंबी प्री-ट्रायल हिरासत की भी अनुमति देता है। UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति सामान्य आपराधिक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की तुलना में अलग हिरासत नियमों के अधीन हैं। UAPA प्री-ट्रायल जांच के दौरान न्यायिक हिरासत की समय सीमा बढ़ाता है, जिसे कुछ मामलों में 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि BNSS के तहत यह सीमा 90 दिन है।[436]

UAPA अत्यधिक प्रतिबंधात्मक जमानत शर्तें भी लगाता है जो संदिग्धों को रिहाई की संभावना से प्रभावी रूप से वंचित करती हैं। मजिस्ट्रेटों की शक्ति को गंभीर रूप से कम कर दिया गया है, और UAPA के तहत आरोपित व्यक्तियों को अक्सर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है।[437] गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में, एक सिख कार्यकर्ता की हिरासत से संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि UAPA[438] के तहत "जेल नियम है, जमानत अपवाद है",एक सिद्धांत जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का खंडन करता है।[439] मई 2017 में, भारत के विधि आयोग ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए UAPA जमानत आवश्यकताओं के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हुए कि "जमानत से इनकार को राज्य के कार्यों को वैध बनाने के लिए हेरफेर के संभावित उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए",[440] और "[अनावश्यक] प्री-ट्रायल कारावास"[441] को कम करने का आह्वान किया।इसके अलावा, UAPA यातना सहित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों में बाधा डालता है।[442]

इसकी व्यापक शक्तियों और सामान्य आपराधिक कानून से प्रक्रियात्मक विचलन को देखते हुए, UAPA फर्जी आपराधिक अभियोजनों को आधार देने वाला एक प्रमुख कानूनी साधन बन गया है, जिसमें, जैसा कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों ने देखा है, "प्रक्रिया ही एक सजा है"।[443] जैसा कि ऊपर 'असंतुष्टों के खिलाफ यातना' खंड में दिखाया गया है, मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों को पिछले एक दशक में UAPA के तहत आपराधिक अभियोजन और लंबी प्री-ट्रायल हिरासत का शिकार बनाया गया है।[444]

2021 में, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने मानवाधिकार रक्षकों को निशाना बनाने और नागरिक समाज को प्रतिबंधित करने के लिए UAPA के उपयोग पर चिंता व्यक्त की।[445] 2022 में भारत के चौथे UPR में, कई राज्यों ने चिंता व्यक्त की "कि आतंकवाद विरोधी कानून के लागू होने से मानवाधिकार रक्षकों को हिरासत में लिया गया है"।[446] HRCttee ने भी भारत से ICCPR के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप UAPA की समीक्षा करने का आह्वान किया है।[447]

2021 में मानवाधिकार रक्षक फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत के बाद 2022 में, 13 मानवाधिकार संगठनों ने UAPA को निरस्त करने का आह्वान किया, जिस पर इस रिपोर्ट के 'असंतुष्टों के खिलाफ यातना' खंड में चर्चा की गई थी।[448] राष्ट्रीय चुनावों के बाद 2024 में भी इसी तरह

434 HRW, भारत: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समीक्षा में गंभीर चिंताएं उठाई गईं, 18 नवंबर 2022
435 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967,
436 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, धारा 43D
437 जमानत नहीं दी जाएगी यदि 'विश्वास करने के उचित आधार 'हों कि आरोप 'प्राइमा फेसी 'सत्य हैं, जो व्यवहार में जमानत चाहने वालों के लिए पार करना बहुत कठिन साबित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जाँच एजेंसी द्वारा संकलित साक्ष्य तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि बंदी द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के माध्यम से उनका खंडन, निषेध या खारिज न किया जाए (देखें: भारत संघ बनाम बरकतुल्लाह 2024 INSC 452 पैरा 9; और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम जहीर अहमद शाह वटाली2019 (5) SCC 1)। चिंताजनक रूप से, यह प्रमाण का भार प्रतिवादी पर स्थानांतरित कर देता है।
438 PUCL, "जेल, जमानत नहीं": क्या सुप्रीम कोर्ट घड़ी को पीछे कर रहा है?, 20 फरवरी 2024
439 ICCPR, 16 दिसंबर 1966, अनुच्छेद 9(3)
440 भारत का विधि आयोग, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन - जमानत से संबंधित प्रावधान, मई 2017
441 भारत का विधि आयोग, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन - जमानत से संबंधित प्रावधान, पैरा 12.2 पर
442 भारत सरकार, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, धारा 49
443 लॉ चक्र, पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश-न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर: "हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में, प्रक्रिया ही सजा है," 10 जुलाई 2024. यह भी देखें: प्रोजेक्ट 39A, क्राइम, पनिशमेंट एंड जस्टिस इन इंडिया: द ट्रैजेक्टरीज़ ऑफ क्रिमिनल लॉ, 2018
444 UAPA और व्यापक रूप से आतंकवाद-रोधी कानूनों पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए देखें पीयूसीएल, UAPA: असहमति का अपराधीकरण और राज्य आतंक, 28 सितंबर 2022
445 OHCHR, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने भारतीय अधिकारियों से कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक खुर्रम परवेज को निशाना बनाना बंद करने और उन्हें तुरंत रिहा करने का आग्रह किया, 22 दिसंबर 2021. यह भी देखें: डॉयचे वेले, भारत: संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद-रोधी कानूनों की आलोचना की, 6 दिसंबर 2021
446 UN HRC, UPR 2022, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया पृष्ठ 7 पर
447 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024
448 AI, भारत: एक साल बाद, हिरासत में फादर स्टेन स्वामी की मौत के लिए न्याय की मांग, 5 जुलाई 2022

के आह्वान किए गए थे।[449]फरवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों को UAPA और इसके संशोधनों के लिए संवैधानिक चुनौतियों पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया।[450] हालांकि, सुधार के बार-बार आह्वान के बावजूद, UAPA अपरिवर्तित और लागू है।

UAPA के साथ-साथ, भारत में अन्य कानून भी यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों को सुगम बनाते हैं। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), जिसे शुरू में 1999 में महाराष्ट्र राज्य में अधिनियमित किया गया था और बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू करने के लिए विस्तारित किया गया,[451] पुलिस अधिकारियों को दिए गए कबूलनामे की स्वीकार्यता की अनुमति देता है और छह महीने के लिए अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है - प्रावधान जो हिरासत में दुर्व्यवहार को सुगम बनाते हैं।[452]इसी तरह, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) बिना मुकदमे के लंबी हिरासत को अधिकृत करते हैं, और कथित तौर पर असहमति को चुप कराने के लिए इनका उपयोग किया गया है।[453] 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को भी कथित तौर पर नागरिक समाज के अभिनेताओं के खिलाफ हथियार बनाया गया है, "मानवाधिकार रक्षकों, कार्यकर्ताओं और गैर-लाभकारी संगठनों पर हमला करने, डराने और परेशान करने के लिए, [विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम] (FCRA) के तहत आरोपों को पूरक करके, उनकी संपत्तियों को जब्त करके, और उन पर कड़ी जमानत शर्तें लगाकर"।[454]

449 फ्रंटलाइन, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने दुरुपयोग और अधिकारों के उल्लंघन पर UAPA को निरस्त करने का आह्वान किया, 20 मई 2024
450 राकिया इमरान, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को UAPA संशोधनों की जांच करने की अनुमति दी, 6 फरवरी 2025; सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर, UAPA संशोधन की संवैधानिकता, 28 जनवरी 2025
451 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 [दिल्ली विस्तार] अधिनियम 1999 का 30, 24 अप्रैल 1999
452 द एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू पर वर्किंग ग्रुप के 27वें सत्र के लिए भारत पर संयुक्त हितधारक रिपोर्ट, सितंबर 2016, पैरा 37
453 HRC, विश्व मुस्लिम कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान, 28 फरवरी 2024 UN Doc A/HRC/55/NGO/208, p. 2
454 AI, भारत: आतंकवाद विरोधी नियमों का दुरुपयोग बंद करें, 3 नवंबर 2023

यातना के लिए दण्डहीनता

© iStock/anil_shakya19

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि भारतीय सैन्य तथा पुलिस बलों में यातना के लिए दण्डहीनता की संस्कृति गहराई से जड़ें जमा चुकी है

जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए दंडमुक्ति की संस्कृति भारतीय सेना और पुलिस बलों में गहराई से निहित है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों और विशेष प्रक्रियाओं, और नागरिक समाज द्वारा मान्यता दी गई है।[455] यह संस्कृति आंशिक रूप से बनी हुई है क्योंकि राज्य के अधिकारियों को यातना और दुर्व्यवहार के कृत्यों के लिए शायद ही कभी जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। अप्रभावी जांच, दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ प्रतिशोध, और राज्य के अधिकारियों को दी गई कानूनी प्रतिरक्षा के कारण दंडमुक्ति को बल मिलता है। यह खंड बताता है कि कैसे भारत यातना की प्रभावी जांच और अभियोजन पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों से कम रह जाता है, जो अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और इस अपराध को खत्म करने के लिए आवश्यक है।

प्रभावी जांच का अभाव

अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत, राज्यों पर यह दायित्व है कि वे जहाँ भी ऐसे उचित आधार हों जिससे यह विश्वास किया जा सके कि उनके अधिकार-क्षेत्र में यातना का कोई कृत्य किया गया है, वहाँ वे जाँच करें — चाहे वह किसी शिकायत के जवाब में हो या स्वयं पहल करते हुए।[456] यह दायित्व

455 मुंशी सिंह गौतम (डी) और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2005 (9) SCC 631; OHCHR, न्यायेतर, सरसरी या मनमानी फांसी पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, क्रिस्टोफ़ हेन्स, 26 अप्रैल 2013. HRCttee समापन टिप्पणियाँ 2024; कॉमन कॉज़, स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025, 26 मार्च 2025; OMCT & MASUM, भारत: जहानूर हक़ की हत्या: पश्चिम बंगाल में दण्डमुक्ति बरकरार, 2 मई 2025। यह भी देखें: HRW, "बाउंड बाय ब्रदरहुड" — पुलिस हिरासत में हत्याओं को समाप्त करने में भारत की विफलता, 19 दिसंबर 2016

456 UNCAT अनुच्छेद 12 और 13

दोहरा है: इसमें सक्षम प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार और उस शिकायत की शीघ्र और निष्पक्ष जांच कराने का अधिकार दोनों शामिल हैं। ICCPR के तहत जांच करने के अपने कर्तव्य के बावजूद, और सिद्धांत रूप में - व्यक्तियों के लिए राज्य के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कई तंत्रों के अस्तित्व के बावजूद, व्यवहार में, भारतीय अधिकारी नियमित रूप से यातना और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की पर्याप्त जांच करने में विफल रहते हैं।[457]

प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में विफलताएं

पुलिस, जो अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आपराधिक अपराधों के आरोपों की जाँच करने की ज़िम्मेदार होती है[458], किसी शिकायत दर्ज किए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिए बाध्य है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेते हुए, BNSS का उद्देश्य "जीरो एफआईआर" और ई-एफआईआर" प्रक्रियाओं को शुरू करके एफआईआर दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना था, जो पीड़ितों को अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में, या ईमेल, पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देता है - हालांकि व्यक्तिगत पुष्टि अभी भी आवश्यक है।[459]

बहरहाल, पुलिस अधिकारी लगातार एफआईआर दर्ज करने का विरोध करते हैं, देरी करते हैं या पूरी तरह से विफल रहते हैं, जिसके बिना जांच आगे नहीं बढ़ती है।[460] उदाहरण के लिए, जैसा कि 2024 में HRCttee द्वारा नोट किया गया है, रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "1979 से 2012 तक मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं के 1,528 प्रलेखित मामलों में से केवल 39 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गईं"।[461] यह देश भर में एक लंबे समय से रुझान रहा है, जैसा कि नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रलेखित किया गया है और इस रिपोर्ट के पिछले खंडों में केस स्टडीज में चित्रित किया गया है।[462] वास्तव में, पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के पास लाई गई शिकायतों पर CHRI के शोध से पता चला है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ठीक एफआईआर दर्ज करने में विफलता से संबंधित है, यह मुद्दा असम में शिकायतों की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी को दर्शाता है।[463]

केस स्टडी: यातना का मामला दर्ज करने से इनकार

दीनाकृष्ण ठाकुर

एक प्रतीकात्मक मामला पौंड्र के अनुसूचित जाति समुदाय के एक कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता दीनाकृष्ण ठाकुर का है। फरवरी 2024 में, उन्हें 35-40 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बुरी तरह पीटा गया और फिर जाति-आधारित अपमान करते हुए पुलिस ने उन पर और हमला किया। नतीजतन, उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसमें दोनों कानों को दीर्घकालिक क्षति शामिल है। जब दीनाकृष्ण ने बकुलतला पुलिस स्टेशन में यातना की रिपोर्ट करने का प्रयास किया, तो पुलिस अधिकारियों ने यह दावा करते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि इसे जयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र था।[464] बाद में, जब दीनाकृष्ण ने जयनगर में शिकायत दर्ज करने के लिए परिवार के एक सदस्य को भेजा, तो स्टेशन पर एक सब-इंस्पेक्टर ने इनकार कर दिया, परिवार के वाहन को नष्ट कर दिया, और उन्हें उनके घर तक पहुंच से वंचित कर दिया। अंततः एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इसमें दीनाकृष्ण की जाति की स्थिति सहित प्रमुख विवरणों को छोड़ दिया गया।[465]

457 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR), 16 दिसंबर 1966, अनुच्छेद 2(1). अधिक टिप्पणी के लिए सामान्य टिप्पणी संख्या 31 (2004) देखें

458 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, अध्याय XIII

459 कॉमन कॉज तीन नए आपराधिक कानून, जुलाई-सितंबर 2024, पृष्ठ 5-6

460 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 15 और 29

461 HRCttee, समापन टिप्पणियां 2024, 25 जुलाई 2024, पैरा 29

462 HRW, भाईचारे से बंधे: पुलिस हिरासत में हत्याओं को समाप्त करने में भारत की विफलता, 19 दिसंबर 2016

463 CHRI, भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5

464 झूठे क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों का उपयोग आमतौर पर एफआईआर दर्ज न करने के कारण के रूप में किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ही यह अनिवार्य कर दिया था कि पुलिस को स्थान की परवाह किए बिना सूचना दर्ज करनी चाहिए और क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को बाद में संबंधित थाना को सूचना अग्रेषित करके निपटाना चाहिए। देखें: Sआंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनाती रामुलु और अन्य 1994 SCC (SUPP) 1 590 पैरा 4

465 MASUM मासिक रिपोर्ट, मार्च 2024

पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी रिपोर्टों को दर्ज करने में यह प्रतिरोध या विफलता आंशिक रूप से उनके कर्मियों के खिलाफ शिकायतों की उनकी धारणा से समझी जा सकती है। जैसा कि कॉमन कॉज द्वारा प्रलेखित किया गया है, देश भर के पुलिस अधिकारियों के साथ साक्षात्कार से पता चला है कि "एक तिहाई पुलिस कर्मियों का दृढ़ विश्वास है कि पुलिस के खिलाफ शिकायतें झूठी और तुच्छ हैं, जबकि अन्य 42 प्रतिशत इस बयान से कुछ हद तक सहमत हैं" ।[466] इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार किए गए 29% पुलिस अधिकारियों का "दृढ़ विश्वास है कि पुलिस के खिलाफ दर्ज की गई अधिकांश शिकायतें राजनीति से प्रेरित हैं, जबकि एक तिहाई से कुछ अधिक (36%) ने कहा कि वे इससे कुछ हद तक सहमत हैं" ।[467]

निष्पक्षता, तत्परता और प्रभावशीलता का अभाव

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी, अनावश्यक देरी के बिना जाँच पूरी करने के लिए कानूनी प्रावधान होने के बावजूद,[468] जाँचें अक्सर विलंबित होती हैं या अपर्याप्त रूप से संचालित की जाती हैं। वास्तव में, राज्य हिंसा की अपर्याप्त जांच के मुद्दे ने सुप्रीम कोर्ट और NHRC को पिछले दशकों में कई दिशानिर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें हिरासत में मौत और न्यायेतर हत्याओं के मामले शामिल हैं।[469] जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने याद किया, "पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर अत्याचार अक्सर प्रत्यक्ष साक्ष्य या अन्य प्रत्यक्ष सबूतों के बिना छोड़ दिए जाते हैं जो यह साबित करते हैं कि अपराधी कौन हैं" ।[470] यह यातना और हिरासत में हुई मौतों के पर्याप्त दस्तावेजीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकता, और प्रभावी और निष्पक्ष जांच के महत्व को भी को रेखांकित करता है।

स्थानीय पुलिस की द्वैध भूमिका—एक ओर अपराधी के रूप में और दूसरी ओर प्रारम्भिक जाँचकर्ता के रूप में—को लेकर अनेक गंभीर चिंताएँ उठाई गई हैं।[471] स्वतंत्रता की यह कमी न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, बल्कि व्यवहार में जांच को भी काफी कमजोर करती है।[472] उदाहरण के लिए, गैर सरकारी संगठनों ने हिरासत में मौत के मामलों में पोस्ट-मार्टम परीक्षण में पुलिस के हस्तक्षेप का दस्तावेजीकरण किया है, जो अन्यथा राज्य के दुर्व्यवहार का महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकता था। कुछ मामलों में, पुलिस ने शव परीक्षण किया और परिवार को देखने का अवसर दिए जाने से पहले ही पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।[473]

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा कर्मियों ने बताया है कि तथाकथित "फ़र्ज़ी मुठभेड़" मामलों में रिपोर्टों को गलत साबित करने से इनकार करने पर उनके पेशेवर जीवन के अवसर सीमित हो जाते हैं।[474]

जवाबदेही के एक दुर्लभ उदाहरण में, 2024 में, एक भारतीय न्यायालय ने महेंद्र राठौड़ की हिरासत में मौत के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, और जांच के दौरान मुद्दों पर प्रकाश डाला। 2016 में बेंगलुरु में पुलिस हिरासत में महेंद्र की मौत के बाद, कोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने यातना के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों को बरामद या जब्त नहीं किया, सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने में विफल रहे, और केस डायरी और गिरफ्तारी रिकॉर्ड में हेरफेर किया। फिर भी, न्यायालय अन्य साक्ष्यों—जिनमें पीड़ित को हुई चोटों का विवरण देने वाली एक चिकित्सकीय रिपोर्ट भी शामिल थी—पर आंशिक रूप से निर्भर करते हुए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम रहा।[475]

इसके अतिरिक्त, हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं हो सकता है, प्रलेखित उदाहरण दिखाते हैं कि यातना या अन्य गंभीर उल्लंघनों की जांच अक्सर आगे बढ़ने में विफल रहती है, जब तक कि किसी वकील या गैर सरकारी संगठन द्वारा उनकी सक्रिय रूप से निगरानी और संचालन नहीं किया जाता है।[476] कई मामलों में, कानूनी प्रतिनिधियों या गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को पुलिस को कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए अदालती

466 कॉमन कॉज भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), 2025, पृष्ठ 127
467 कॉमन कॉज भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), 2025, पृष्ठ 127
468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 193
469 डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 1 SCC 416. अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं पर एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के लिए देखें: यूथ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ़ अक्टूबर 2021
470 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य 1995 (4) SCC 262, 9 मई 1995
471 जस कॉर्पस लॉ जर्नल, भारत में स्वतंत्र जांच की आवश्यकता: पुलिस बर्बरता और कानून, 27 फरवरी 2017
472 UNCAT, अनुच्छेद 12
473 पीपुल्स वॉच, रिपोर्ट - विग्नेश कस्टोडियल डेथ, 22 अप्रैल 2022, पृष्ठ 30. र्व-नियत दाह-संस्कार के एक अन्य मामले के लिए देखें: नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, वार्षिक रिपोर्ट, 18 मार्च 2020, पृष्ठ 177। यह भी देखें: सालिनी बनाम जिला कलेक्टर WP(MD).23672/2024
474 डॉ ब्रह्मा देव बनाम श्री विजय सांपला और अन्य CONT.CAS(C) 1043/2022, पैरा 4
475 कर्नाटक राज्य बनाम एजाज खान और अन्य SC No.1723/2019. यह भी देखें विकास का विमर्श, न्याय हुआ: हिरासत में मृत्यु के लिए पुलिस अधिकारी जेल में, 27 नवम्बर 2024
476 MASUM, वार्षिक रिपोर्ट 2023, पृष्ठ 25

आदेशों की मांग करनी पड़ी है।[477] हालांकि, ऐसा हस्तक्षेप काफी संख्या में मामलों में संभव नहीं है, क्योंकि पीड़ितों और उनके परिवारों के पास स्थानीय गैर सरकारी संगठनों या कानूनी सहायता वकीलों तक पहुंच नहीं है।[478] यह जवाबदेही सुनिश्चित करने में निरंतर निगरानी और दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह भी कि जांच को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है।

इनमें से कुछ मुद्दों के जवाब में, भारत के विधि आयोग ने हिरासत में चोट या मृत्यु से जुड़े मामलों में सबूत के बोझ को उल्टा करने की सिफारिश की।[479] यह दृष्टिकोण अदालतों को यह मानने की अनुमति देगा कि नुकसान अधिकारियों द्वारा किया गया था, जिससे अधिकारियों पर यह साबित करने का बोझ आ जाएगा कि व्यक्ति को यातना या दुर्व्यवहार के अधीन नहीं किया गया था। सिफारिश मिनेसोटा प्रोटोकॉल के अनुरूप है, जो पुष्टि करता है कि "राज्य द्वारा हिरासत में रखे गए लोगों पर प्रयोग किए गए नियंत्रण के कारण, ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी का एक सामान्य अनुमान है"।[480] हालांकि, विधि आयोग की सिफारिश को अभी तक पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है।[481]

यातना के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच करने में स्थानीय पुलिस की लगातार विफलता को देखते हुए, भारतीय अदालतों ने, कुछ मामलों में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।[482] हालांकि, सीबीआई की स्वतंत्रता के बारे में भी चिंताएं उठाई गई हैं, विशेष रूप से उन आरोपों के आलोक में कि वर्तमान सरकार ने राजनीतिक रूप से प्रेरित जांच के माध्यम से मानवाधिकार रक्षकों को परेशान करने और डराने के लिए संस्था का उपयोग किया है।[483] सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया है कि अपर्याप्त स्थानीय पुलिस जांच की भरपाई के लिए सीबीआई पर निर्भर रहना एक स्थायी समाधान नहीं है।[484]

अन्य निकायों द्वारा जांच भी संभव है।[485] उदाहरण के लिए, मजिस्ट्रेटों के पास लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच का आदेश देने का अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट, संघ और राज्य सरकार गंभीर अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (Special Investigation Team-SIT) के गठन का निर्देश भी दे सकती है, खासकर जहां मानक जांच की निष्पक्षता, पर्याप्तता या प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं हैं।[486] इन दलों ने आमतौर पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा, या राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित के अन्य मामलों से जुड़े बहुचर्चित मामलों को संभाला है।[487] उदाहरण के लिए, "1984 के सिख विरोधी दंगों, 2002 के गुजरात दंगों, COVID-19 के दौरान नकली टीकों, और कर चोरी की निगरानी के लिए एक निरीक्षण निकाय के रूप में" जांच करने के लिए विशेष जांच दल बनाए गए हैं।[488]

इसके अतिरिक्त, पुलिस या न्यायिक हिरासत में हुई मौत, गुमशुदगी या बलात्कार के मामलों में, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अनिवार्य है—भले ही पुलिस द्वारा कोई जाँच पहले ही की गई हो।[489] फिर भी, व्यवहार में, ऐसी पूछताछ हमेशा नहीं होती है। जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट किया गया है, NCRB के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 और 2022 के बीच:

477 उदाहरण के लिए देखें पीपुल्स वॉच मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच के समक्ष रिट याचिका, 16 अक्टूबर 2020. एक कथित यातना पीड़ित की उचित पोस्ट-मॉर्टम कराने का प्रयास। देखें यह भी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका, जिसमें पूर्व-सतर्कतापूर्वक अदालत से सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया, , पीपुल्स वॉच, Chand (Patrakar), और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य, CRIMINAL MISC. WRIT PETITION सं. – 16809/2024, पैरा 1 में। जब जांच पूरी हो जाती है, तो कुछ मामलों में अदालतों को अंतिम चार्जशीट प्रस्तुत करने का आदेश भी देना पड़ता है, जो आपराधिक अभियोजन की शुरुआत करता है

478 द वायर, जाति पूर्वाग्रह और लैंगिक अंतराल: 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कानूनी प्रणाली की प्रमुख विफलताओं पर प्रकाश डालती है, 16 अप्रैल 2025

479 भारत का विधि आयोग, UNCAT का कार्यान्वयन, 27 अक्टूबर 2017, पैरा 7.5

480 UN OHCHR, मिनेसोटा प्रोटोकॉल, 2016

481 नित्या रामकृष्णन, हिरासत में: कानून, दंडमुक्ति और दक्षिण एशिया में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, मई 2013, पृष्ठ 32

482 इंडिया टुडे, तूतीकोरिन हिरासत में मौतें: पिता-पुत्र की जोड़ी को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, अपना खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है, 27 अक्टूबर 2020. देखें यह भी: बार एंड बेंच हल्दी समारोह में उठाया गया व्यक्ति, पुलिस हिरासत में यातनाएं देकर हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, 20 मई 2025

483 HRW, भारत: शांतिपूर्ण असहमति पर कार्रवाई के लिए कानूनों का दुरुपयोग, 08 फरवरी 2024

484 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम रेबेका खातून मुल्ला (आपराधिक) संख्या 15481/2024 पैरा 5. देखें यह भी: वर्डिक्टम, आर.जी. कर प्रदर्शन | कोलकाता में कथित हिरासत में महिला पर यातना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया, और कोलकाता उच्च न्यायालय के सीबीआई निर्देश में संशोधन किया, 25 नवंबर 2024

485 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 175(4)

486 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, विशेष जांच दल (SIT), [n.d]

487 ज्यूरिस्टिक इन्फो, विशेष जांच दल (SIT): यह कैसे काम करता है और इसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां, 14 जनवरी 2025

488 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, विशेष जांच दल (SIT), [n.d]

489 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 196(2); लाइव लॉ, कस्टोडियल डेथ्स: पूछताछ की प्रक्रिया क्या है? 28 जून 2020

पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में आधे से भी कम मामलों में न्यायिक जांच का आदेश दिया गया था (...) 2022 तक, पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में न्यायिक जांच कराने के क़ानूनी आदेश का लगभग दो-तिहाई मामलों में पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, पुलिस हिरासत में मौत के बीस प्रतिशत से अधिक मामलों में, न तो न्यायिक और न ही मजिस्ट्रेट जांच, यानी किसी भी तरह की जांच नहीं की गई।[490]

विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जताई है कि, BNSS के तहत, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास अब ऐसी पूछताछ का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है, जिससे यह जिम्मेदारी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, उप-मंडल मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों पर छोड़ दी गई है। इस बदलाव की स्वतंत्र निरीक्षण को कमजोर करने के लिए आलोचना की गई है, क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट राज्य प्रशासन का हिस्सा हैं और पुलिस दुर्व्यवहार की जांच के लिए आवश्यक निष्पक्षता की कमी हो सकती है।[491]

कमजोर बाहरी शिकायत निकाय

भारत में, मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए कई बाहरी निकाय स्थापित किए गए हैं, विशेष रूप से राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों से संबंधित। इनमें पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCAs), NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) कानून प्रवर्तन संस्थाओं के दुर्व्यवहार की जांच के लिए अनिवार्य हैं। हालांकि, जवाबदेही सुनिश्चित करने और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में इन संस्थानों की प्रभावशीलता पर बार-बार सवाल उठाए गए हैं।पुलिस सुधारों पर 2006 के एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के निर्माण का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने हिरासत में मौत, गंभीर चोट और पुलिस हिरासत में बलात्कार सहित पुलिस कर्मियों द्वारा "गंभीर दुर्व्यवहार" के आरोपों की जांच के लिए राज्य और जिला दोनों स्तरों पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की।[492] इन निकायों का व्यापक लक्ष्य व्यक्तियों को पुलिस कदाचार की रिपोर्ट करने और निवारण की मांग करने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र प्रदान करना था।

हालाँकि, CHRI की 2023 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना के लगभग 15 साल बाद भी पुलिस जवाबदेही पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के आधे से भी कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय पुलिस शिकायत प्राधिकरण हैं, और इन निकायों की स्वतंत्रता अक्सर उनके संचालन में सेवारत पुलिस और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी से कमजोर होती है।[493] 2021 तक, "केवल 8 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में स्वतंत्र सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया बनाई हैं, और केवल 5 जिला PCAs के लिए" ।[494] चिंताजनक रूप से, सितंबर 2023 तक, 11 सक्रिय पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में से कम से कम नौ सेवारत सरकारी या पुलिस अधिकारियों से बने हैं, और केवल एक में स्वतंत्र नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व है, जो राजनीतिक जुड़ाव से मुक्त है।[495] यह स्वतंत्रता की कमी इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि केवल दो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणों ने पूछताछ का समर्थन करने के लिए एक अलग जांच विभाग स्थापित किया है। नतीजतन, ऐसे निकायों का बहुमत "अपने स्वयं के कर्मियों के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच के लिए राज्य पुलिस विभाग पर ही निर्भर करता है" ।[496]

इसके अतिरिक्त, पुलिस शिकायत प्राधिकरणों द्वारा शिकायतों को स्वीकार करने के लिए व्यवहार में अपनाया गया दायरा विशेष रूप से संकीर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण संख्या में आरोप अनसुलझे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में हजारों शिकायतें दर्ज होने के बावजूद, केवल 17 के परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई।[497]

एक अन्य प्रासंगिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC है, जिसे देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जनादेश के साथ स्थापित किया गया है। इसका दायित्व है कि यह मानवाधिकारों को बढ़ावा दे, हिरासत केंद्रों का निरीक्षण कर परिस्थितियों का आकलन करे और सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करे, तथा किसी सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की जाँच करे।[498] शिकायतों पर विचार और जांच करने पर, NHRC कथित रूप से ऐसे दुर्व्यवहारों में शामिल अधिकारियों के अभियोजन की सिफारिश कर सकता है, और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे का आदेश दे सकता है।[499]

490 कॉमन कॉज, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), 2025, पृष्ठ 166
491 प्रोजेक्ट 39A), एनोटेटेड तुलना, 2023, पृष्ठ 64-65
492 CHRI, पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सरकारी अनुपालन, मूल्यांकन, सितंबर 2021
493 CHRI, भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, इन संगठनों की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की गई थी, जैसा कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, WP (C) 310 (1996)मामले में हुआ था।
494 CHRI, पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सरकारी अनुपालन, मूल्यांकन, सितंबर 2021
495 CHRI, भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023
496 CHRI, भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5-6
497 CHRI, भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5
498 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993, 2006 में संशोधित, धारा 12
499 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 धारा 18

व्यवहार में, NHRC को अपनी अप्रभावीता के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2014 से 2022 की अवधि के दौरान, NHRC को हिरासत में होने वाली मौतों की 20,000 से अधिक शिकायतें मिलीं, फिर भी इसने केवल 995 मामलों में पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश की, केवल 28 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया, और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के किसी भी अभियोजन की सिफारिश नहीं की।[500] यह स्पष्ट विसंगति जवाबदेही को आगे बढ़ाने के लिए NHRC की प्रतिबद्धता और क्षमता के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। विशेष रूप से, NHRC के पास अपनी सिफारिशों को लागू करने का अधिकार नहीं है, जिसमें मुआवजा देने वाली सिफारिशें भी शामिल हैं, जो मानवाधिकारों के हनन के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर इसके प्रभाव को और सीमित करता है।[501] यह मुद्दा सशस्त्र बलों द्वारा उल्लंघन को संबोधित करने के लिए NHRC की लगभग पूर्ण शक्ति की कमी से और बढ़ गया है।

जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले बताया गया है, सशस्त्र बलों द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों के संबंध में, NHRC केवल किसी विशेष स्थिति पर सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और उस रिपोर्ट के आधार पर सिफारिशें कर सकता है, लेकिन यह अपनी स्वयं की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है।[502] यह सीमा विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और छत्तीसगढ़ जैसे बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि वाले राज्यों के साथ-साथ उन क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है जहां विशिष्ट अभियानों का संचालन करने के लिए अक्सर सशस्त्र बलों को तैनात किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के ग्लोबल एलायंस (GANHRI) ने NHRC की आलोचना की है और 2016 के बाद से तीन बार इसे मान्यता देने में देरी की है। हाल ही में, मार्च 2025 में, इसने सिफारिश की कि NHRC को श्रेणी "A" (पेरिस सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से अनुपालन) से "B" (आंशिक रूप से अनुपालन) में कर किया जाए। रिपोर्टों के अनुसार, GANHRI ने "जांच में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी, आयोग की संरचना में बहुलवाद की कमी, अपारदर्शी चयन और नियुक्ति प्रक्रियाओं, प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया, और नागरिक समाज के साथ खराब सहयोग" के बारे में चिंता व्यक्त की।[503] इसने विशेष रूप से जांच में निष्पक्षता की कमी की आलोचना की, जो "पीड़ितों की मानवाधिकार न्याय तक पहुंचने की क्षमता" को प्रभावित करती है।[504] अंत में, राज्य स्तर पर, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए समान जनादेश के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) स्थापित किए गए थे। हालाँकि, इन निकायों के संबंध में भी इसी तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। रिपोर्टें बताती हैं कि उनमें अक्सर कर्मचारियों की कमी होती है,[505]

और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही में योगदान देने में वे धीमे और अप्रभावी होते हैं।[506] लंबी जांच के एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में, 2021 में, पीपुल्स वॉच ने एक मामले का दस्तावेजीकरण किया जहां तमिलनाडु में SHRC को हिरासत में बलात्कार की शिकार को मुआवजे की सिफारिश करने में दस साल लग गए। प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करते हुए, पीपुल्स वॉच ने SHRCs के सुधार का आह्वान किया।[507]

शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध

अंतरराष्ट्रीय कानून, ICCPR सहित, के तहत, भारत पर यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्ति जो यातना या अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्ट करते हैं, उनकी शिकायत या द्वारा प्रदान किए गए किसी भी सबूत के कारण होने वाले किसी भी दुर्व्यवहारया धमकियों से सुरक्षित रहें।[508] यह प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षित रूप से शिकायत दर्ज करने और जवाबदेही प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसे सुरक्षा उपायों के बिना, प्रतिशोध का जोखिम दंडमुक्ति को संबोधित करने के प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।

500 ये आंकड़े हिरासत में मौत के बारे में शिकायतों की कुल संख्या लेते हैं जिसमें NHRC ने मुआवजे के पुरस्कार की सिफारिश की थी, जैसा कि एनएचआरसी वार्षिक रिपोर्ट (2013-2022) में दर्ज है वार्षिक रिपोर्ट 2021-22; वार्षिक रिपोर्ट 2019-20; वार्षिक रिपोर्ट 2018-19; वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018; वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017; वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016; वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015; वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014

501 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 धारा 18

502 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 धारा 19

503 द न्यूज़ मिनट, भारत के NHRC को 'ए' से 'बी' स्थिति में डाउनग्रेड का सामना क्यों करना पड़ रहा है, 28 अप्रैल 2025; GANHRI, प्रत्यायन स्थिति, पृष्ठ 7. GANHRI, 20 नवंबर 2024 तक मान्यता की स्थिति, पृ. 7; द वायर, भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 'ऐतिहासिक 'गिरावट का सामना, संयुक्त राष्ट्र-संबंधित संस्था ने सरकारी हस्तक्षेप को इंगित किया, 28 अप्रैल 2025

504 द न्यूज़ मिनट, भारत के NHRC को 'ए' से 'बी' स्थिति में डाउनग्रेड का सामना क्यों करना पड़ रहा है, 28 अप्रैल 2025. GANHRI

505 NHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग, 17 दिसंबर 2024

506 द वायर, भारत के राज्य मानवाधिकार आयोगों में 2 में से लगभग 1 पद खाली है: रिपोर्ट, 4 अप्रैल 2023

507 पीपुल्स वॉच, अधिकार मंच ने यौन हमले की शिकार को मुआवजे की सिफारिश करने वाले तमिलनाडु एसएचआरसी (SHRC) के आदेश का स्वागत किया, 24 दिसंबर 2021

508 ICCPR, अनुच्छेद 2(3)

सिद्धांत रूप में, पुलिस शिकायत प्राधिकरणों - जहां ऐसे निकाय स्थापित और कार्यरत हैं - के पास पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की उच्च संख्या यह सुझाव दे सकती है कि भारत में अधिक पीड़ित हिंसा या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में सहज महसूस करते हैं।[509] हालाँकि, ये तंत्र पूरे देश में अपनी व्यापकता और प्रभावशीलता में सीमित हैं, और इसलिए यह यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के सभी या अधिकांश पीड़ितों के अनुभवों को दर्शा नहीं सकते हैं। वास्तव में, शिकायतकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न और धमकियों की घटनाएं संकेत देती हैं कि शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं।[510] जैसा कि 2021 में सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति और गैर- पुनरावृत्ति की गारंटी के प्रचार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने नोट किया:

भारत में, पुलिस ने कथित तौर पर कानूनी कार्यवाही को बाधित करने के लिए पीड़ितों को परेशान किया है और धमकाया है, और न्याय प्रणाली, जो कुछ अल्पसंख्यकों के खिलाफ संरचनात्मक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और अत्यधिक नौकरशाही से ग्रस्त है, ने मणिपुर, जम्मू और कश्मीर में हुई घटनाओं के संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की है या उन्हें तदनुसार दंडित नहीं किया है।[511]

उदाहरण के लिए, जनवरी 2024 में, एनजीओ MASUM ने पश्चिम बंगाल में BSF द्वारा माबिया खातून के खिलाफ की गई यातना के मामले का दस्तावेजीकरण किया। एक मस्जिद के रास्ते में, माबिया को उसकी छोटी बेटी के सामने BSF कर्मियों द्वारा पीटा गया और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि पुलिस उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उन्होंने उसे शिकायत दर्ज करने के खिलाफ चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर उसने घटना की सूचना दी तो वे नशीले पदार्थ से संबंधित आरोप लगाएंगे।[512] एक अन्य रिपोर्ट किए गए मामले में, पुलिस ने 30 वर्षीय व्यक्ति की यातना और हत्या में शामिल अधिकारियों के निलंबन की मांग करने वाले एक कार्यक्रम के आयोजक को यातना दी। इस व्यक्ति के साथ जाति-आधारित गाली-गलौज की गई और उसे लाठी से पीटा गया।कथित तौर पर पिटाई के परिणामस्वरूप उसका जबड़ा टूट गया था। उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन नागरिक समाज संगठनों के हस्तक्षेप के बाद अदालत ने इसे रद्द कर दिया।[513]

एक अलग मामले में, 2020 में, हबीब मोहम्मद ने तमिलनाडु के अरुमुगनेरी पुलिस स्टेशन में छह पुलिस अधिकारियों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने की सूचना दी। जब उसने चिकित्सा उपचार की मांग की और अपनी चोटों का कारण बताया, तो पुलिस अधिकारी अस्पताल आए, उसे कहीं और इलाज कराने के खिलाफ धमकी दी, और चेतावनी दी कि अगर उसने यातना की सूचना दी तो झूठे आपराधिक आरोप दायर किए जाएंगे।[514]

केस स्टडी: यातना की रिपोर्टिंग के लिए पुलिस का प्रतिशोध

यूनुस शाह

जून 2022 में, 67 साल के यूनुस शाह ने अलापुर पुलिस स्टेशन में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने उनके रिश्तेदार को बुरी तरह पीटा, बिजली के झटके दिए और सेक्सुअल वायलेंस किया। FIR दर्ज होने के बाद, पांच पुलिस अधिकारियों को उनके कथित तौर पर शामिल होने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से काम पर रख लिया गया। फिर उन्हीं अधिकारियों ने कथित तौर पर यूनुस और उनके परिवार को धमकाया और परेशान किया ताकि वे शिकायत वापस ले लें।

दिसंबर 2022 में, 10-15 पुलिस अधिकारियों का एक ग्रुप यूनुस के घर गया और टॉर्चर की शिकायत वापस लेने की मांग की। जब परिवार ने मना कर दिया, तो यूनुस और उसके तीन रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर अलापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उन्हें टॉर्चर किया गया। उन्हें डंडों से पीटा गया और घूंसे मारे गए; परिवार के एक सदस्य को कान और सिर में बिजली के झटके दिए गए और बाद में तबीयत बिगड़ने पर उसे बदायूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। टॉर्चर की वजह से, यूनुस की उंगली में फ्रैक्चर हो गया, और परिवार के एक और सदस्य के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मारपीट के दौरान, पुलिस ने बार-बार शिकायत वापस लेने की मांग की।

509 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI), भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 5

510 MASUM, मासिक रिपोर्ट सितंबर 2024, पृष्ठ 3; मासिक रिपोर्ट जून 2024 [n.d], p. 3-4;
पीपुल्स वॉच, 24 फरवरी 2024 थूथुकुडी में ऑटो ड्राइवर हबीब के खिलाफ क्रूर यातना, 24 फरवरी 2024; OMCT, भारत: एक यातना पीड़ित के परिवार को सुरक्षा कानूनों के तहत दंडित और चुप कराया गया, 15 नवंबर 2023; HRW, पुलिस ने एक युवा महिला को अपनी बलात्कार शिकायत वापस लेने के लिए कैसे दबाव डाला, 8 नवंबर 2017

511 ह्यूमन राइट्स कॉउन्सिल, सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति और गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी के प्रचार पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट, फैबियन साल्विओली, 9 जुलाई 2021, पैरा 46

512 MASUM, मई 2024 मासिक रिपोर्ट, [n.d], पृष्ठ 5

513 पीपुल्स वॉच, JAACT कार्यकर्ता हिरासत में मौत में हस्तक्षेप के लिए गिरफ्तार, 25 फरवरी 2024

514 पीपुल्स वॉच, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक मूल याचिका का ज्ञापन, 2020

इसके बाद यूनुस पर भारतीय कानून के कई कानूनी नियमों के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें दंगा करना, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाना, दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालना, हत्या की कोशिश और आपराधिक साज़िश शामिल हैं। जनवरी 2024 में ज़मानत पर रिहा होने तक उसकी हिरासत कई बार बढ़ाई गई। यूनुस के खिलाफ आरोप अभी भी लगे हुए हैं।

21 फरवरी 2024 को, WGAD ने यूनुस की तरफ से एक सबमिशन मिलने के बाद, यूनुस के मामले के बारे में भारत सरकार को एक मैसेज भेजा। भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन, WGAD ने अपनी राय दी कि यूनुस की हिरासत मनमानी थी।[515]

यहां तक कि पुलिस अधिकारियों ने भी हिंसा के उपयोग के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बारे में चिंता व्यक्त की है। हालिया एम्पिरिकल रिसर्च, जिसमें देशभर के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया था, के अनुसार 44% ने इस बात से "पूरी तरह सहमति" जताई कि यदि कानूनी सुरक्षा मौजूद हो तो वे ऐसे शिकायत दर्ज करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। 36% ने "मध्यम स्तर की सहमति" व्यक्त की, और 8% ने कहा कि "वे कभी भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के उपयोग को लेकर शिकायत दर्ज करने में सहज महसूस नहीं करेंगे, भले ही उनके पास कानूनी सुरक्षा क्यों न हो।"[516] इस संदर्भ में, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो व्यक्ति पुलिस या अन्य अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, वे प्रतिशोध के डर से आगे आने में संकोच करेंगे।

नागरिक समाज संगठनों, वकीलों और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ प्रतिशोध - जैसा कि इस रिपोर्ट के पहले के खंडों में प्रलेखित है - जवाबदेही प्रयासों में भी बाधा डालता है। ये सभी लोग उल्लंघनों को दर्ज करने, कानूनी सहायता प्रदान करने, पीड़ितों का साथ देने और जांच की मांग उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।असहमति के प्रति शत्रुता, संरचनात्मक भेदभाव, राज्य हिंसा और पीड़ितों के उत्पीड़न से प्रभावित संदर्भों में, नागरिक समाज संगठनों पर प्रतिबंध और मानवाधिकारों रक्षकों पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ सीधे तौर पर पीड़ितों की सहायता प्राप्त करने, उल्लंघनों की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने, या न्याय की मांग करने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। पीड़ितों की सहायता करने वालों के काम को कमजोर करना अंततः दंडमुक्ति के चक्र और राज्य हिंसा के परिणामस्वरूप सामान्यीकरण में योगदान देता है।

प्रतिशोध को संबोधित करने के लिए केवल औपचारिक शिकायत तंत्र से अधिक की आवश्यकता है - इसके लिए ठोस, सुलभ सुरक्षित उपायों की आवश्यकता है जो धमकी और प्रतिशोध को रोकें। यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित, गवाह और नागरिक समाज बिना किसी डर के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कर सकें, किसी भी प्रभावी जवाबदेही ढांचे का एक केंद्रीय घटक माना जाना चाहिए। इसके मद्देनज़र, CHRI ने सिफारिश की है, कि पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को केवल सुरक्षा उपायों पर सलाह देने तक सीमित रहने के बजाय, "गवाहों, पीड़ितों और उनके परिवारों की सुरक्षा का आदेश देने की शक्तियां दी जानी चाहिए जो शिकायत करने के लिए खतरे या उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं"।[517] ऐसे सुधार महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें व्यापक, प्रणालीगत परिवर्तनों का हिस्सा होना चाहिए जिसका उद्देश्य निगरानी निकायों की स्वतंत्रता को मजबूत करना, निहित शक्ति असंतुलन को दूर करना, और यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा उन संस्थानों के विवेक पर न छोड़ी जाए जिन पर दुर्व्यवहार का आरोप है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यातना और मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व या समर्थन करने वाले, या अधिक व्यापक रूप से जवाबदेही को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले नागरिक समाज संगठन स्वतंत्र रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने में सक्षम हों।

जवाबदेही के लिए अन्य बाधाएं

यातना के ऐसे मामलों में, जिनमें चार्जशीट दायर की जाती है और आपराधिक अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है, अक्सर पुलिस अधिकारियों, सशस्त्र बलों के सदस्यों, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और अन्य लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए कार्यपालिका की अनुमति (जिसे 'पूर्व स्वीकृति' कहा जाता है) की आवश्यकता के कारण बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।[518] चूंकि सरकार शायद ही कभी ऐसी मंजूरी देती है, इसलिए यह आवश्यकता यातना के कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में एक बड़ी बाधा बनती है।[519] इसके अलावा, ऐसे प्रावधान पीड़ितों के निवारण के अधिकार और यातना के कृत्यों की जांच करने, और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराधियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने के राज्य के कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं।[520]

515 संयुक्त राष्ट्र वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, यूनुस शाह (भारत) से संबंधित राय संख्या 45/2024, 10 अक्टूबर 2024
516 कॉमन कॉज, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), पृष्ठ 129
517 कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI), भारत में पुलिस शिकायत प्राधिकरण, 2023, पृष्ठ 146
518 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 151, 218
519 कॉमन कॉज, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), पृष्ठ 148
520 UNCAT, अनुच्छेद 4,7,12,13,14

BNSS अदालत को किसी लोक सेवक, जिसमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति के बिना "संज्ञान लेने", यानी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति नहीं देता है।[521] यह प्रावधान

यातना से संबंधित अधिकांश अपराधों को शामिल करता है, लेकिन भ्रष्टाचार[522] और यौन हिंसा[523] के अपराधों के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में किसी अधिकारी के अभियोजन को मंजूरी देने के अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए सरकार के विवेक पर समय सीमा का प्रावधान नहीं था। हालांकि, BNSS के तहत, जो जुलाई 2024 में लागू हुआ, यदि सरकार अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय लेने में विफल रहती है, तो मंजूरी दी गई मानी जाएगी।[524] इस नए प्रावधान के कार्यान्वयन, और यातना के कृत्यों के लिए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाना बाकी है।

जिन मामलों में अनुमति दी जाती है, उनमें सरकार के पास यह अधिकार भी होता है कि वह यह तय करे कि किन विशिष्ट अपराधों की सुनवाई होगी, कार्यवाही की निगरानी कौन-सा न्यायाधीश करेगा, कार्यवाही किस प्रकार संचालित की जाएगी, और मुकदमे की सुनवाई किस न्यायालय में होगी।[525] BNSS को "गैरकानूनी" सभाओं को तितर-बितर करने में बल के प्रयोग के लिए सशस्त्र बलों और पुलिस पर मुकदमा चलाने के लिए भी सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है।[526]

सशस्त्र बलों को BNSS के तहत अत्यधिक व्यापक भाषा के साथ व्यापक प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, जो यह प्रदान करता है कि "संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने का इरादा रखने वाले किसी भी कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद।"[527] इसके अलावा, BNSS प्रदान करता है कि "सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य जो किसी भी आदेश के पालन में कोई कार्य करता है जिसका पालन करने के लिए वह बाध्य था, उसे कोई अपराध करने वाला नहीं माना जाएगा"।[528] AFSPA प्रदान करता है कि "अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए या किए जाने का इरादा रखने वाले किसी भी कार्य" के संबंध में सशस्त्र बलों के सदस्यों के खिलाफ सभी अभियोजन और कानूनी कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।[529] व्यवहार में, सशस्त्र बलों के सदस्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लगभग कभी नहीं दी जाती है।[530] आतंकवाद विरोधी कानून में व्यापक प्रतिरक्षा पाई जाती है। उदाहरण के लिए, UAPA "आतंकवाद का मुकाबला" करने के उद्देश्य से ऑपरेशन करने वाले सैन्य या अर्धसैनिक कर्मियों सहित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन और कानूनी कार्यवाही को प्रतिबंधित करता है।[531]

उन मामलों की संख्या को इंगित करने के लिए कोई उपलब्ध डेटा नहीं मिला जहां पुलिस या सुरक्षा अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी दी गई या अस्वीकार कर दी गई। हालांकि, भारतीय नागरिक समाज और मीडिया प्लेटफॉर्म प्रासंगिक डेटा रिपोर्ट करने में कामयाब रहे हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय एनजीओ MASUM ने रिपोर्ट दी है कि 2015 के बाद से, केंद्र सरकार ने राज्य सुरक्षा बलों द्वारा यातना और न्यायेतर हत्याओं से जुड़े पश्चिम बंगाल में 49 मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। [532]भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट दी कि केंद्र सरकार ने 2001 और 2016 के बीच जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा की गई यातना, न्यायेतर हत्याओं, बलात्कार और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े 50 में से 49 मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।[533]

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने एक मामले का दस्तावेजीकरण किया जिसमें दिसंबर 2021 में नागालैंड में सैन्य कर्मियों द्वारा 14 नागरिक मारे गए थे।[534] हालांकि हत्याओं की जांच मार्च 2022 में पूरी हो गई थी और अप्रैल में आरोप जारी किए गए थे, लेकिन आरोपित अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में मामला बंद कर दिया।[535]

521 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 218
522 (BNSS) की धारा 218 के तहत, भ्रष्टाचार विरोधी अपराधों के लिए अनुमति की आवश्यकता का अपवाद है
523 (BNSS), की धारा 218 यह प्रदान करती है कि बलात्कार सहित यौन हिंसा अपराधों के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
524 (BNSS), धारा 218 (1) (बी)
525 (BNSS), धारा 218 (5)
526 (BNSS), धारा 151
527 (BNSS), धारा 42 (1)
528 (BNSS), धारा 151
529 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, धारा 6
530 इंडियन एक्सप्रेस, सशस्त्र बल कर्मियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी: कौन से नियम लागू होते हैं?, 21 जुलाई 2024. अधिक जानकारी के लिए नागालैंड सैनिकों के मुकदमे की अंतरराष्ट्रीय एनजीओ कवरेज देखें, HRW, इंडिया इवेंट्स ऑफ 2023, 24 जुलाई 2023। ऐतिहासिक उदाहरण के लिए देखें, AI, डिनाइड: जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही में विफलताएँ 30 जून 2015
531 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, धारा 49
532 MASUM और OMCT संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को प्रस्तुति, 3 जून 2024, पृष्ठ 8-9 पर
533 द वायर, रक्षा मंत्रालय, सेना के पास सुरक्षा कर्मियों पर मुकदमा चलाने की खारिज याचिकाओं पर 'फाइलें नहीं हैं', 30 अप्रैल 2018
534 द वायर एक्सक्लूसिव: एसआईटी का कहना है कि सेना अधिकारी ने 'जानबूझकर' जानकारी छिपाई जो नागालैंड हत्याओं को रोक सकती थी, 7 जुलाई 2022
535 द टाइम्स ऑफ इंडिया, नागा ऑपरेशन में गड़बड़ी: SC ने 30 सेना के जवानों के खिलाफ आपराधिक मामले बंद किए, 18 सितंबर 2024

कुछ मामलों में, अदालतों ने इन प्रावधानों के प्रभाव को सीमित कर दिया है। मार्च 2023 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि हिरासत में यातना के मामलों में पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है,[536] जैसा कि दिसंबर 2024 में केरल उच्च न्यायालय ने किया था।[537] जुलाई 2024 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मंजूरी की आवश्यकता ने इंस्पेक्टर के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों की रक्षा नहीं की।[538] हालांकि, ये कदम छिटपुट और असंगत बने हुए हैं क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में हिरासत में मौत के एक कथित मामले में पूर्व मंजूरी की आवश्यकता बताई है।[539] राष्ट्रीय स्तर पर, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक यह स्थापित किया जा सकता है कि कोई कार्य कर्तव्य के दौरान किया गया था, तो उसे पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी, भले ही वह कार्य अत्यधिक हो[540] जिसमें ड्यूटी के दौरान लोक सेवकों द्वारा किए गए यातना के सभी मामले शामिल होंगे।

इन संरचनात्मक बाधाओं के परिणामस्वरूप, यातना या संबंधित अपराधों के कृत्यों के लिए लगभग न के बराबर आपराधिक दोषसिद्धि में दंडमुक्ति स्पष्ट है।एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने से लेकर 2022 तक, देशभर में यातना के 25 मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से दर्ज किए गए, जिनमें 14 मामलों में अभियोजन शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तीन दोषसिद्धियाँ और एक बरी होना दर्ज किया गया।[541]जिसका अर्थ है कि 2018-2022 के बीच पुलिस कर्मियों के खिलाफ यातना के केवल आठ मामले दर्ज किए गए थे और इसी अवधि के लिए कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गई थी।[542]

जैसा कि इस रिपोर्ट में चित्रित किया गया है, नागरिक समाज की रिपोर्टों और NHRC के आंकड़ों की तुलना में, NCRB डेटा पंजीकृत मानवाधिकार उल्लंघनों, जिसमें हिरासत में मौत और यातना शामिल है, का गंभीर रूप से कम अनुमान है। इसके अलावा, यातना के एक विशिष्ट आपराधिक अपराध की कमी के कारण यातना के सभी मामलों के आधिकारिक आंकड़े अनुपलब्ध हैं। फिर भी, NCRB द्वारा संकलित जानकारी को देखने पर भी, यह बहुत छोटा नमूना केवल 12% दोषसिद्धि दर दिखाता है।

हिरासत में मौत या पुलिस मुठभेड़ों जैसी यातना-संबंधी घटनाओं के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों का उपयोग सिस्टम में दंडमुक्ति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। NCRB ने बताया कि 2014 और 2022 के बीच, हिरासत में मौत के 328 मामले हुए, लेकिन 0% दोषसिद्धि की भी सूचना दी, जिसमें 89% अभियोजन कार्यवाही या तो खारिज कर दी गई या मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली।[543] अंत में, NCRB ने पुलिस मुठभेड़ हत्याओं की 35 घटनाओं की सूचना दी, जिससे 15 अभियोजन हुए लेकिन 2017 और 2022 के बीच कोई दोषसिद्धि नहीं हुई।[544]

536 लाइव लॉ, कस्टोडियल टॉर्चर आधिकारिक कर्तव्य नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को चोट से हत्या तक बढ़ाने का निर्देश दिया, 28 मार्च 2023

537 लाइव लॉ, 'यातना' पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं, ऐसे कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं: केरल उच्च न्यायालय, 2 दिसंबर 2024

538 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं: HC, 26 जुलाई 2024

539 श्रीमती कली बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य आवेदन धारा 482 नंबर - 17579/2024, 30 सितंबर 2024

540 ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय 2024 INSC 979, पैरा 66. पूर्ण न्यायिक उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखें: ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय, आपराधिक अपील सं. 5267–5268 / 2024, जिसमें न्यायालय ने समस्त प्रासंगिक न्याय-दृष्टान्तों का विस्तृत विवरण दिया है, और अपना मुख्य तर्क पैराग्राफ 65(ii) में प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि: "यदि अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य से अधिक कार्य करता है, तो यह अतिक्रमण अपने-आप में दंप्रसं (CrPC) की धारा 197 के अंतर्गत दिए गए संरक्षण से उस लोक सेवक को वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा

541 NCRB, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 वर्षों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले. (ध्यान दें कि एनसीआरबी के पास 2022–24 के वर्षों में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पुलिस कर्मियों के दोषसिद्धि संबंधी कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा नहीं है)। एनसीआरबी में यातना के मामलों के लिए एक उप-श्रेणी शामिल है, लेकिन भारतीय कानूनी ढाँचे में यातना को एक अलग आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता न होने के कारण, एनसीआरबी द्वारा यातना के मामलों को दर्ज करने के लिए अपनाए गए मानक और परिभाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

542 कॉमन कॉज, भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025, पुलिस यातना और (जवाबदेही का अभाव), पृष्ठ 172

543 NCRB, यह आंकड़ा 2014-2022 के लिए 'भारत में अपराध' और वार्षिक रिपोर्टों 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 (से 'हिरासत में मौतों के कारण' तालिका से लिया गया है। ध्यान दें कि मई 2025 तक, 2023 या 2024 के लिए क्राइम इन इंडिया की कोई वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है)

544 NCRB, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 वर्षों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले (ध्यान दें कि एनसीआरबी के पास वर्ष 2022–24 के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज मामलों का कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा नहीं है।)

REDRESS

Ending torture, seeking justice for survivors

फोटो कवर बी माथुर/ रॉयटर्स
नई दिल्ली में भ्रष्टाचार और बढ़ती खाद्य कीमतों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक चप्पल पुलिस के पास पड़ी दिखाई देती है। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियों, पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

redress.org

REDRESS
Unit G01, 65 Glasshill Street
SE1 0QR, London, UK
+44 (0)20 7793 1777
info@redress.org

company/REDRESS
redresstrust
Subscribe